

भारतीय नरेश
और
राष्ट्रीयता

जगन्नाथ प्रसाद मिश्र

संजय—प्रकाशन

प्रेमनगर

एटा (उ० प्र०)

प्रकाशक
 शीला मिश्रा
 सजय प्रकाशन
 प्रेमनगर, एटा (उ० प्र०)
 © जगन्नाथ प्रसाद मिश्रा

प्रथम संस्करण 1100
 1969

मूल्य	{ जन संस्करण	3 50
	राज संस्करण	7 00

मुद्रा
 श्री कम्पोजिंग सेंटर द्वारा चित्रित मुद्राकरण विनारो बाजार
 बरक बासी गली नम्बर 6

समर्पण

अनेकों खण्डो-उपखण्डों मे विभक्त भारत को
एक सघ का रूप प्रदान करने वाले
सरदार वल्लभ भाई पटेल
एव
भारतीय नरेशो
को

अन्तर्मन से

मुझे न तो भूतपूर्व नरेशों से कोई लगाव है और न कांग्रेस अथवा किसी अन्य राजनैतिक दल से कोई शत्रुता। हाँ, अन्याय को चाहे वह किसी के प्रति हो और किसी भी रूप में क्यों न हो, मैं सहन नहीं कर पाता, उसका विरोध करना मैं अपना धर्म समझता हूँ।

भारत का वर्तमान सघ-रूप, नरेशों के स्व-उन्मूलन का फल है, इसलिये भारत सघ (दूसरे शब्दों में भारतीय जनता) द्वारा नरेशों के साथ किए गए समझौते एवं प्रतिज्ञा-पत्रों के उन्मूलन का नारा नरेशों के प्रति (और भारतीय जनता के प्रति) घोर अन्याय है तथा 'प्राण जाहूँ वरु वचन न जाई' आप्त वाक्य को अपने सांस्कृतिक जीवन का मूल स्वर मानने वाले भारतीय जनमानस द्वारा अपने नरेशों को दिये वचन का भंग करना है। इस प्रस्तावित जघन्य के विरोध-स्वरूप यह पुस्तक आपके हाथों में है।

राजनीति से अथवा किसी दलबन्दी से न मेरा कोई सम्बन्ध है और न मेरे विचारों के मूर्त रूप इन पृष्ठों का। भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैंने जो कुछ देखा, सुना, पढ़ा एवं अनुभव किया, उसे मेरे लेखक ने यहाँ अभिव्यक्त कर दिया है। प्रस्तुत प्रणति प्रणयन काल में सहयोग देने के लिए प्रियवन्दु श्रीराम कृष्ण शर्मा 'कवैल' का मैं आभारी हूँ।

मेरा दृष्टिकोण भारतीय जनमानस का किस सीमा तक प्रतिनिधित्व कर पाया है, इसका निर्णय करना सुधि एवं प्रबुद्ध पाठकों पर है।

गणतन्त्र दिवस, 1969

जगन्नाथ प्रसाद मिश्र

विषयानुक्रमिका

खध्याय

पृष्ठ संख्या

एक :

प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारों का राष्ट्रघाती प्रस्ताव

कांग्रेसी प्रस्ताव	9
प्रस्ताव पारित होने की कहानी	10
प्रस्ताव एवं भारत सरकार	12

दो :

भारत संघ का गठन

विभाजन	15
रियासतों की सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न स्थिति	17
रियासतों का सघ में विलय	19
रियासतों की देन	21

तीन :

संविलयन अनुबन्ध एवं प्रसंविदाएँ	22
---------------------------------	-----	-----	----

चार :

नरेशों के प्रिवीपर्स एवं विशेषाधिकार	27
प्रिवीपर्स	29
विशेषाधिकार	33

पाँच :

प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारों का औचित्य

(कानूनी पक्ष)

भारतीय सविधान की दृष्टि में	40
धन्तराष्ट्रीय कानून की दृष्टि में	50
नैतिक पक्ष	53

(हमारी परम्पराएँ)

प्राण और वचन	64
विश्वास	67
(राजनैतिक)			
हमारी सीमाएँ	70

नरेशो की लोक प्रियता

नरेश और चुनाव	73
नरेशों का प्रभाव	76
सात	

बापू

बापू और समाजवाद	
बापू और नरेश	79
छाठ	81

प्रस्ताव की प्रतिक्रिया

समाचार पत्र और नरेश	
समाचार पत्र (विपक्ष में)	83
(राजनीति)	90
(सरकार के बाहर)	
श्री कट्टीयालान माणिकलाल मुन्शी	95
जनवर्ती श्री राजगोपालाचारी	98
जनवर्ती श्री राजगोपालाचारी	100
श्री० एम० आर० पई	103
जनवर्ती श्री राजगोपालाचारी	104
श्री० बी० गिबाराव	106
श्री० मुरारजी आर० दसाई	112
(सरकार के भीतर)	
कुमारा माणिकलाल पटेल (कायम)	119
श्री दबीरसिंह (स्वतंत्र)	120
श्री बजरंग मधोव (जनसंघ)	121
श्री प्रकाशचंदर लाल (निर्दलीन)	122
(गविश्वनाथ सम्राट)	
डाक्टर बी० पट्टाभि साधनमरा	123
नरेश	123
जनवाणी	128

प्रेरणा

“कोई भी आदमी जो सक्रिय अहिंसा में विश्वास रखता है, सामाजिक अन्याय को, फिर वह कहीं भी क्यों न होता हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता वह उसका विरोध किये बिना नहीं रह सकता।”

—राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी

प्रिवापसों एवं विशेषाधिकारों के
उन्मूलन का गान्धिवार्ता
ग्रन्थाव

हुई जिसमें निष्पक्ष किया गया कि संविधान का धारा 291 में, जो 'प्रिवापस' के भुगतान के विषय में 'गारण्टी' देनी है संशोधन कर लिया जाए।

उधर भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने भी, गृह मंत्रालय की सलाह दी है कि भारतीय नरेशों के पक्ष की वकालत देने वाली संविधान की धारा 3291 व 362 को समाप्त कर दिया जाए।

वास्तव में कांग्रेस के प्रस्ताव, मंत्रिमण्डल की आन्तरिक मामला की समिति के निष्पक्ष व विधिमन्त्रालय द्वारा दिये गये सुझाव के औचित्य या अनीचित्य का सही रूप में समझने के लिए इस विषय के कानूनी पक्ष के साथ साथ इसके ऐतिहासिक सामाजिक नैतिक एवं राजनीतिक पक्षों का अध्ययन विवेचन करना भी बहुत जरूरी है।

सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि स्वाधीनता मिलने के समय और उसमें पहले देश की राजनीतिक स्थिति क्या थी? संगठित भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल का छोटी में वह जादू किस आ गया कि जिन जसे उनकी छोटी धूमनी गई भारतीय रियासतों ने एक एक करके आत्मसमर्पण कर लिया?

उस छोटी को जादुई छोटी बनाने में तत्कालीन नरेशों का कितना हाथ था? उसमें उनकी भी कुछ योगदान था या नहीं? उनके और सरदार पटेल के मध्य क्या संधियां हुई थी? यह बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वे भी तथाकथित समाजवादियों की निराधार एवं भ्रामक बातों के फेर में पड़कर इस विषय पर निष्पक्ष एवं योग्य सगत दृष्टि नहीं डाल पा रहे।

प्रस्ताव के पारित होने की कहानी

अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति में नरेशों के 'प्रिवापसों' एवं विभाजन विचारों को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कराने का घटना भी बड़ी मनोरंजक है।

महासमिति के सदस्यों का कुल संख्या 600 है। उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए बसल आये दो सप्ताह आ पाये थे। अधिवेशन के अंत में बसल

बीस सदस्यों की उपस्थिति में नरेशों के विरोधाधिकारों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया, महाराष्ट्र के सदस्य श्री मोहनलाल धारिया ने इस प्रस्ताव में यह संशोधन प्रस्तुत किया कि विरोधाधिकारों के साथ नरेशों के प्रिवीपर्सों को भी समाप्त कर दिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली और प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं अन्य कांग्रेसी नेता उस समय उपस्थित नहीं थे। जैसे ही इस प्रस्ताव पर मतदान प्रारम्भ हुआ, उपप्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई भी मतदान में भाग लेने के लिए पहुँच गए। अब सदस्यों की संख्या 21 हो गई। प्रस्ताव के पक्ष में 17 एवं विरोध में 4 मत पड़े और वह पारित हो गया। इन 17 सदस्यों में से कुछ ऐसे भी थे जो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करने थे। विरोध में दिए 4 मतों में से एक मत उपप्रधान मंत्री का था, जो ठीक मतदान के समय पर केवल अपना विरोध व्यक्त करने के लिए ही वापस लाए थे। इस प्रकार महामिति के सदस्यों की कुल संख्या के तीसरे भाग में भी कम सदस्यों की राय को पूरी महामिति के ऊपर लाद दिया गया है। लोकतन्त्र प्रणाली के दहमत का जैसा उपहान इस प्रस्ताव के पारित करने में हुआ, वह अपने नमूने की एक ही घटना है।

हुई जिसमें निम्नलिखित किया गया कि संविधान की धारा 291 में, जो प्रिवीपंस के भुगतान के विषय में धारणा देती है संशोधन कर दिया जाए।

उधर भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने भी, गृह मंत्रालय की सलाह दी है कि भारतीय नरेशों के एक को वस देने वाली संविधान की धारा 291 व 362 को समाप्त कर दिया जाए।

वास्तव में कांग्रेस के प्रस्ताव मंत्रिमण्डल की आंतरिक मामला की समिति के निम्नलिखित विधिमंत्रालय द्वारा दिये गये सुझाव के अधीन या अनौचित्य का सहा रूप में समझने के लिए इस विषय के कानूनी पक्ष के साथ साथ इसने ऐतिहासिक सामाजिक नैतिक एवं राजनीतिक पक्षों का अध्ययन विवक्षित करना भी बहुत जरूरी है।

सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि स्वाधीनता मिलने के समय और उससे पहले देश की राजनैतिक स्थिति कसी थी? संगठित भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की छोटी में यह जादू कैसे आ गया कि जिन जिन उनकी छोटी घूमती गई भारतीय रियासतों ने एक एक करके आत्मसमर्पण कर दिया?

उस छोटी की जादुई छोटी बनान में तत्कालीन नरेशों का किना हाथ था? उसमें उनका भी कुछ योगदान था या नहीं? उनसे और सरदार पटेल के मध्य क्या मंचिया हुई थी? यह सब प्रश्न हैं जिन्हें उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वे भी तथ्यावलीन समाजशास्त्रियों की निराधार एवं भ्रामक बातों के पर में पड़कर इस विषय पर निष्पक्ष एवं वास्तविक दृष्टि नहीं डाल पा रहे।

प्रस्ताव के पारित होने की कहानी

भारत सरकार का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल में करार के प्रिवीपंसों एवं विदेश विभाग को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कराने का प्रयास भी बड़ी मनारजक है।

मंत्रिमण्डल के मस्यौदा का कुल सदस्य 600 है। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कब्रन आये हो मस्यौदा का पाठ थे। अधिवेशन के अंत में कब्रन

बीस सदस्यों की उपस्थिति में नरेशो के विशेषाधिकारो को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया, महाराष्ट्र के सदस्य श्री मोहनलाल धारिया ने इस प्रस्ताव में यह संशोधन प्रस्तुत किया कि विशेषाधिकारो के साथ नरेशो के 'प्रिवीपर्सों' को भी समाप्त कर दिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली और प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी एवं अन्य कांग्रेसी नेता उस समय उपस्थित नहीं थे। जैसे ही इस प्रस्ताव पर मतदान प्रारम्भ हुआ, उपप्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई भी मतदान में भाग लेने के लिए पहुँच गए। अब सदस्यों की संख्या 21 हो गई। प्रस्ताव के पक्ष में 17 एवं विरोध में 4 मत पड़े और वह पारित हो गया। इन 17 सदस्यों में से कुछ ऐसे भी थे जो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। विरोध में दिए 4 मतों में से एक मत उपप्रधान मन्त्री का था, जो ठीक मतदान के समय पर केवल अपना विरोध व्यक्त करने के लिए ही वापस आए थे। इस प्रकार महासमिति के सदस्यों की कुल संख्या के तीसरे भाग से भी कम सदस्यों की राय को पूरी महासमिति के ऊपर लाद दिया गया है। लोकतन्त्र प्रणाली के बहुमत का जैसा उपहास इस प्रस्ताव के पारित करने में हुआ, वह अपने नमूने की एक ही घटना है।

इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रस्ताव कांग्रेस के आदर्शों के अनुरूप नहीं है, बल्कि कुछ गिने चुने लोगों की नरेशो के प्रति व्यक्तिगत ईर्ष्या एवं द्वेष की प्रतिक्रिया है।

प्रस्तावित निर्णय को लोकतन्त्री जामा पहनाने के लिए इसे लोक सभा में लाया गया। जहाँ संयुक्त समाजवादी दल तथा प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों को इसमें भाग लेने के लिए उकसाया गया, और कांग्रेसियों से 'ह्विप' के बल पर इसका समर्थन कराया गया।

स्वतन्त्र दल के श्री सी० सी० देसाई ने, जिनका सरदार पटेल से निकट का सम्पर्क रहा था, सदस्यों को सम्बोधित करते हुए प्रश्न किया, "यदि आज सरदार जीवित होते तो क्या इस समूह में से कोई भी व्यक्ति 'प्रिवीपर्सों' के समाप्ति की बात करने का साहस कर पाता?" आगे उन्होंने सरदार पटेल के वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए बताया कि अकेले ग्वालियर के महाराजा ने ही इतनी धनराशि दी है कि नरेशो के 'प्रिवीपर्सों' का बहुत बड़ा भाग उस राशि से ही चुकाया जा सकता है।

श्री देसाई ने कांग्रेस पर प्रत्यक्ष आरोप लगाते हुए कहा, "आपका कहना उचित है, नरेश अब अपनी रियासतें आपको सौंप चुके हैं और आपके शिकजे

म बम गए हैं। इसलिए आप चाहें तो अब उनक गले में फासी भी लगा सकते हैं।”

श्री प्रेम् एथानी ने भी काग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सस्ती लोक प्रियता प्राप्त करने में लग गई है। उन्होंने सरदार पटेल की सत्यनिष्ठा पर विगप बल देते हुए कहा कि सरदार ने कई बार दुहराया था कि मैं नरेशों का वचन दिया है। शियासत में क्षेत्र व सम्पत्ति के रूप में हम जा कुछ मिला है, वह बहुमूल्य है। इसका अर्थ है, उस महान नेता ने नरेशों के ‘प्रिन्सिपल’ अधिकारों एवं विनोपाधिकारों का अक्षुण्ण रखने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया था ताकि बाता ठर में कोई उन्हें उनसे वधित करने की बात न कह सके।

प्रस्ताव एवं भारत सरकार

सविधान में संशोधन करने के लिए लोक सभा के दो तिहाई सदस्यों का एक मत होना अनिवार्य है। दुर्भाग्य से आज मदन में काग्रेस के दो तिहाई सदस्य नहीं हैं, किंतु यका यह अब नहीं है कि वह अपने इस कुमन्त्रणाजय प्रस्ताव को सदन में नहीं लाएगा। उस हम बार का पूर्ण विश्वास है कि गर काग्रेसी वामपक्षी दलों के सदस्य समकथित समाजवाद के नाम पर उसकी इस कुमन्त्रणा में साथ लगे और काग्रेस, नरेशों के प्रति अपनी द्वेषात्मक प्रवृत्ति के मूल रूप, इस प्रस्ताव पर उनके मत प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। किंतु क्या ऐसा करना देश की विकास के लिए जनता के साथ विश्वासघात नहीं होगा? भारतीय जनता द्वारा नरेशों की दिये वचन को भंग करने के पक्ष में मत देना भारतीय जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो सकता है?

पिछले नाम चुनावों में लगभग 40 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाली काग्रेस भारतीय जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती, फिर नरेशों के अनुबोध एवं प्रसविदाये तो भारत सरकार (अर्थात् भारतीय जनता) से हुए हैं न कि काग्रेस से। किसी एक दल के विचार राष्ट्र पर बाप देना अव्याय नहीं तो क्या है?

अवस्त में कम का चकोस्लोवाकिया पर यगस्त्र आक्रमण भी इसी द्वेष जय प्रतिक्रिया का मूलरूप है। चकोस्लोवाकिया का अपराध यदि कुछ था

तो केवल इतना कि उसने रूसी प्रभुत्व से मुक्त हो कर एक स्वाधीन देश की भाँति सम्मानित जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया था तथा इस दिशा में सद् प्रयत्न करने आरम्भ कर दिये थे । यद्यपि रूस के अधिकांश नेता इस निन्दनीय कदम को उठाने के पक्ष में नहीं थे किन्तु कुछ सकुचित प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने येन-केन-प्रकारेण अपनी कुमन्यना को व्यावहारिक रूप दिलवा दिया — और उसके लिए अपयश का भागी बनना पड़ा है रूसी जनता को क्योंकि अब कोई उसकी सद्भावना को निदशक दृष्टि से देखने को तैयार नहीं । इसी प्रकार कांग्रेस का यह प्रस्ताव केवल कुछ कुण्ठाग्रस्त व्यक्तियों की सकुचित द्वेष भावना का साकार रूप है जिसके अपयश का भागी कांग्रेस के उस श्रेष्ठ विशाल वर्ग को बनाना पड़ेगा जिसकी इसमें कोई सक्रिय रूचि नहीं है । नरेशों का अपराध यदि कुछ है तो केवल इतना ही कि उन्होंने देश को वर्तमान दूषित एवं भ्रष्ट वातावरण से मुक्त कराके इसमें श्रेष्ठ प्रशासन स्थापित करने की जन साधारण की इच्छा में अपना सक्रिय सहयोग देना अपना पावन कर्तव्य समझा और पिछले आम चुनावों में एक भूक दर्शक की भूमिका न निभाकर सक्रिय भाग लिया, जिससे इन तथाकथित समाजवादियों को अपना आसन हिलता नजर आया और उन्होंने यह कुत्सित प्रस्ताव सम्पूर्ण कांग्रेस पर थोप दिया । यदि दूर्भाग्यवश, यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो सोचिये कि फिर विश्व की दृष्टि में भारतीय जनता की सद्भावना एवं सदास्था का क्या मूल्य रह जाएगा ।

कांग्रेस के इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में वे लोग भी हैं, वल्कि वे ही इस प्रस्ताव से अधिक प्रसन्न भी हैं, जिनके मक्का-मदीना, मास्को एवं पेरिस हैं, जहाँ पर समाजवाद की वेदी पर व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को वलिदान कर मानव को जीवित शव में परिणत कर दिया गया है ।

फ्रांस में आज भी 'नाइट' है, इंग्लैंड में आज भी 'लार्ड' है और इन दोनों देशों का विश्व के लोकतान्त्रिक देशों में अग्र स्थान है । सच तो यह है कि इन देशों में लोकतन्त्र की नींव इतनी गहरी है कि उसे दो-दो महायुद्धों का भूकम्प भी नहीं हिला सका ।

आश्चर्य इस बात का है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इन सब तथ्यों से-मली-भाँति अवगत होते हुए भी इस गलत कदम को रोकने के स्थान पर इसे-ससदीय स्वीकृति दिलाने का दुष्प्रयत्न कर रहे हैं । यदि उनका कहना यह है कि वे अपने दल की महासमिति में पारित प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप

दन के लिए बाध्य है तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा, और ध्यान रखिय कि राष्ट्र के सामने दल का कोई महत्त्व नहीं है नरेगा को दिए वचनों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है ? क्या राष्ट्र की बागडोर सम्भाले इन नेताओं को जो स्वयं को प्रबुद्ध एवं विवेकी बतलाते हैं, यह छोटी सी बात समझने नहीं आती कि इस प्रस्ताव के संसद में पारित होने से सिवा भास्को पीकिंग भक्तों के और किसी का कोई लाभ नहीं होगा ही विद्वज्जमीन निंदा एवं अपयश का भागी अवश्य बनना पड़ेगा ? और जहाँ तक भास्को पीकिंग भक्तों का प्रश्न है उनके तो दोनों हाथों में लक्ष्मी है । यदि यह प्रस्ताव अधिनियम बन गया तो उनकी लोकतन्त्रवादी कुमभ्रमा सफल हो गई और यदि यह प्रस्ताव अधिनियम न बन सका तो उन्हें कांग्रेस पर कीचड़ उछालने का एक अच्छा बहाना मिल जाएगा ।

एक ओर तो वे नरेगों के प्रिवीपर्सों एवं विधायिकाओं का समाप्त कराने का श्रम लेकर जनसाधारण पर यह प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे कि बिना उनके प्रयत्नों एवं सहयोग के यह काम सम्भव नहीं था । दूसरी ओर अपने नेताओं के वचन भंग करने के नतिकता से गिर जाने का भी दुष्परिणाम हावे व अकली कांग्रेस को ही भुगतने होंगे जिसका वे दूसरी तरह से लाभ उठावेंगे । इसे कहते हैं अपने परा में आगे कुल्हाड़ी मारना । अपनी अदूरदर्शिता की गिनार निरीह (?) कांग्रेस ।

इस अधिवेशन की समाप्ति के समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में स्वयं को प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से बचाते हुए यह स्वीकार किया है कि पिछले आम चुनावों में कांग्रेस की विफलता का कारण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस निरंतर दुबल होती जा रही थी । उन्होंने महासमिति के कुछ संस्था द्वारा कांग्रेस के नवतार के प्रति की गई आलोचना का स्वागत करते हुए कहा कांग्रेस के हर प्रतिनिगील काम में नए नए उत्पन्न किए हैं और उसे नयी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है । उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे प्रतिनिगील काम कौन से थे, जिनके कारण उनके दल का पराजय का मूल्य देवना पड़ा ।

मसद् में नरेगों के प्रिवीपर्सों एवं विधायिकाओं का समाप्त करने का काम उठाने से पहले कांग्रेसी संस्था का प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के उपपुत्र कथन को ध्यान में रखते हुए यह साबित करना चाहिए कि क्या उनका यह काम भी अथवा कामों का भावि नरेश्वर उत्पन्न करने वाला एवं नया चुनौतियों का जन्म देने वाला तो नहीं है ?

भारत संघ का गठन

विभाजन

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे देश के क्षेत्रफल का दो तिहाई भाग और तीन चौथाई जनसंख्या ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत थी, शेष एक तिहाई भाग में छोटी बड़ी 565 भारतीय रियासतें थी। ये रियासतें सीधे ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत नहीं थी, बल्कि भारतीय नरेशों के साथ कुछ विशेष समझौतों के अनुसार ही इंग्लैंड के बादशाह का उन पर अधिकार था, इसलिए भारत को स्वाधीनता देते समय ब्रिटिश सरकार ने कानून व नैतिकता की दृष्टि से इन रियासतों को पूर्ण स्वतन्त्र ही माना।

भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 बनने से पूर्व इंग्लैंड से एक मन्त्रिमंडलीय शिष्ट मंडल भारत भेजा गया था, जिसने 12 मई 1946 को यह ज्ञापन घोषित किया था—

“इंग्लैंड के बादशाह से समझौता होने के फलस्वरूप जो अधिकार भारतीय रियासतों को मिले थे, वे अब समाप्त हो जायेंगे तथा भारतीय रियासतों ने अपने जो अधिकार सार्वभौम सत्ता को समर्पित कर दिये थे, उनको फिर वापस मिल जायेंगे। इस प्रकार इंग्लैंड के बादशाह एवं ब्रिटिश भारत के साथ अब तक चले आ रहे भारतीय रियासतों के राज-नैतिक सम्बन्ध समाप्त हो जायेंगे—इस शून्य को भरने के लिये भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारत की उत्तराधिकारी सरकार या सरकारों से सघीय अथवा विशिष्ट राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने होंगे।”

16 मई 1946 को उसी गिफ्ट मण्डल ने अपनी यह योजना घोषित की —

‘भारतीय सत्ता न तो इंग्लैंड के बादशाह के पास रह सकती है और न नयी सरकार को हस्तांतरित की जा सकती है ।’

फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार का वक्तव्य प्रकाश में आया

‘इंग्लैंड के बादशाह की सरकार इस बात का शिष्टाचार स्पष्ट कर देना चाहती है कि भविष्यकालीन गिफ्टमण्डल के 12 मई 1946 के वापन में घोषित भारतीय स्वायत्तता से सम्बंधित नाति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।’

इस वक्तव्य को कांग्रेस और मुस्लिम लीग लाना ने ही स्वीकार किया और आगे बढ़कर वही उत्तराधिकारी सरकारों का सत्ता हस्तांतरित करने की पद्धति का आधार बना ।

अतः भारत को स्वाधीनता देने के लिए भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 बनाया गया, जिसके अनुसार ब्रिटिश भारत को भारत व पाकिस्तान दो अधिराज्यां में विभाजित किया गया ।

भारतीय स्वायत्तता के विषय में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का खंड 7 इस प्रकार है —

नये राज्यों की स्थापना के परिणाम — (1) नियत दिनांक 15 अगस्त 1947 से (ब) भारतीय स्वायत्तता पर से इंग्लैंड के बादशाह का अधिकार समाप्त होता है और उसके साथ साथ वे समस्त संप्रदाय एवं समझौते भी जो इंग्लैंड के बादशाह और भारतीय स्वायत्तता के शासक के बीच में हुये थे ।

×

×

×

इस उपखंड के अनुच्छेद (ब) और (स) में किसी विशिष्ट व्याख्या के न रहने पर भी आयात कर, परिवहन संचार टारिफ या इसी प्रकार के अन्य मामलों में सम्बंधित पुराने समझौते ही उस समय तक मान्य होंगे जब तक कि भारतीय स्वायत्तता के शासक कबीला व सरदार अथवा अधिराज्य और प्रदेश की सरकार उनको अमान्य घोषित न कर दें या फिर नये समझौतों के अस्तित्व में आने से वे स्वयं रद्द न हो जायें ।’

प्रस्तुत उपखंड से यह स्पष्ट है कि भारतीय रियासतों पर किसी भी सत्ता या सरकार का आधिपत्य नहीं था। आयातकर, संचार, डाक-तार आदि से सम्बन्धित जो समझौता ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच था, उसे ही एक विशिष्ट उपखंड के द्वारा चालू रखा गया था। किन्तु वह भी कोई प्रतिबन्ध नहीं था बल्कि किसी भी क्षण, किसी भी रियासत का शासक उसे अपनी रियासत के लिये अमान्य घोषित कर सकता था।

ब्रिटिश सरकार की कई घोषणाओं में यह भी कहा गया था कि रियासतें चाहे तो उस अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं, जिसके साथ उनकी भौगोलिक सीमाएं मिलती हों।

इस प्रकार हर भारतीय रियासत के शासक को यह अधिकार प्राप्त था कि वह चाहे तो पूर्ण स्वतन्त्र रहे अथवा भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में, जिसके साथ भी उसके राज्य की भौगोलिक सीमाएं मिलती हों, अपनी रियासत को मिला दे या फिर जैसा चाहे वैसा समझौता कर ले।

रियासतों की सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न स्थिति

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारे देश के सामने सबसे बड़ा राजनैतिक प्रश्न यही था कि क्या देशी राज्यों के राजा-महाराजा, राष्ट्रीय एकता की वेदी पर अपनी रियासतों की बलि देने जैसा महान् त्याग कर सकेंगे? क्योंकि इन रियासतों के भारत में मिने बिना हमारी स्वाधीनता अधूरी थी।

भारत के मध्य में स्वस्तिक के आकार में फैली इन रियासतों का, राष्ट्र को अखंड बनाने के लिये, भारतीय अधिराज्य में विलय होना कितना महत्वपूर्ण था, यह प्रसिद्ध अंगरेज विद्वान कूपलैंड के इस कथन से स्पष्ट होता है:—

“यदि भारत के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी मुसलमानी अंगों को काट भी दिया जाये, तो उसका जीवित रह सकना सम्भव है, किन्तु क्या वह अपने हृदय के बिना जीवित रह पायेगा?”

उस समय देशी नरेशों के समक्ष भी एक समस्या थी, वे इस शून्य की स्थिति को उत्पन्न होने से पहले ही भर देना चाहते थे।

भारतीय अधिराज्य में कांग्रेस की समाजवादी नीति के अनुसार रियासतों के अस्तित्व को खतरे में समझते हुए भी कुछ रियासतों ने भारत में ही मिशन की इच्छा प्रगट की, जबकि कुछ ने ही स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहा। एक तो रियासतें पाकिस्तान के साथ भी मिलना चाहती थी।

इस विषय में स्थिति से निबटने के लिये भारत की मावी सरकार (उत्तम समय की अंतरिम सरकार) ने भारतीय रियासतों के नामों का आमंत्रित किया कि वे प्रतिरक्षा पर राष्ट्र सम्बंध एक सचार नीति विषय भारतीय अधिराज्य को समर्पित कर दें।

नामों के सामने ऐसा प्रस्ताव रखते समय उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि इन तीन क्षेत्रों के अतिरिक्त उनकी स्थिति पूर्ववत् रहेगी और हम समय-समय पर उनके सम्बन्ध में उन पर किसी प्रकार का आधिकार नहीं पड़ेगा। उनकी आंतरिक स्वायत्तता और प्रभुसत्ता पर भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा। भारतीय सन्निधान को स्वीकार करने के लिये भी वह बाध्य नहीं होंगे।

दोनों राज्यों के शासकों ने भारत सरकार की बात मान ली और उन्होंने भारत अधिराज्य का ब्रिटिश सावर्भौम सत्ता से उत्तराधिकार में मिल भारतीय स्वायत्तता अधिनियम 1947 खंड 7 में निहित उपबंध—जिसके अंतर्गत आधान कर सचार शासक आदि विविध मामलों के सम्बंध में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों तथा भारतीय रियासतों के बीच अस्थायी समझौता था—उसी उपखंड के अंतर्गत उपयुक्त (प्रतिरक्षा, पर राष्ट्र सम्बंध एक सचार) केवल तीन विषयों में अपनी रियासतों का भारतीय संघ में मिलान के लिये एक सन्निधान प्रालय पर 15 अगस्त 1947 से पत्र हस्ताक्षर कर लिये जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था —

‘इस प्रावधान में कोई ऐसा बात नहीं है जिससे हम रियासतों पर मरी प्रभुता में किसी प्रकार का अंतर पड़े। इस रियासतों के नामों के रूप में जो सत्ता एवं अधिकार हम समय-समय में प्राप्त हैं, वह हम प्रांतीय पर हस्ताक्षर करने के बाद भी बचाव रखेंगे।’

इसी दिनांक पर 5 जुलाई 1947 का सरकार बयानमाई पेटेन में यह वक्तव्य भी दिया —

‘इस मूल सिद्धांत को रियासतों ने नहीं ही स्वीकार कर लिया है कि प्रतिरक्षा, परराष्ट्र सम्बंध तथा सचार का दृष्टि में वे भारतीय

रखती है तब राजनैतिक दृष्टि से व-रीय सरकार व रियासतों के बीच एक गहरी गार्ड उत्पन्न हो जायेगी तथा आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में अखिल भारतीय नीतियों का समन्वय नहीं हो पायेगा, और रियासतों में रहने वाली 8 करोड़ 90 लाख जनता लोकतन्त्र व अधिकारों से वंचित रह जायेगा। इस स्थिति में भारतीय तब कभी भी एक विकसित राष्ट्र का सही रूप ग्रहण नहीं कर सकेगा।

अतः भारत सरकार व रियासत मन्त्रालय ने दली नरेशों व सामने उपयुक्त सभी बातें रखते हुए रियासतों के एकीकरण का एक प्रस्ताव रखा।

उस समय नरेशों के सामने व सभी आश्वासन भी थे जो उनमें सन्तुष्टि प्रदान करने पर हस्ताक्षर करते समय भारत सरकार ने उन्हें दिये थे। इसलिये सरकार इस प्रस्ताव के प्रसंग में उनके साथ न तो नतिक रूप से किसी प्रकार का बल प्रयोग ही कर सकती थी और न इसकी कोई चेष्टा ही की गई। यह तो भाई चारे के रूप में नरेशों को सम हित का एक भाग बताया गया था जिसे अपमाना या न अपमाना पूणत उनकी इच्छा पर निर्भर करता था।

नरेश भारतीय सभ्यता के प्रतीक रहे थे उन्होंने अपनी परम्पराओं के द्वारा जिस सभ्यता को अक्षुण्ण रखा था उसका अनुसार राजतन्त्र में भी प्रजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती है और राजा शासक होते हुए भी केवल प्रजा का संरक्षक मात्र होता है। उ होने समय की गति का पहचान कर अपनी सभ्यता के अनुरूप समस्त भारतीय जनता की इच्छा का आदर करते हुये, अपनी प्रजा व हित में एवं भारतीय राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिये रियासत मन्त्रालय के इस प्रस्ताव को भी बड़े उत्साह से स्वीकार कर लिया और एक एक करके 554 रियासतों ने सन्तुष्टि अनुबोध व प्रसन्निधियों (मजर एमीम टस एण्ड कावन्-ट्स) पर हस्ताक्षर कर दिये।

इस तरह जो काम मुसलमान 700 वर्षों में अपनी तलवारों और अग्नेय 200 वर्षों में अपनी कूटनीतियों से न कर सके, भारतीय नरेशों की राष्ट्रीय भावना प्रजा की हितचिन्तना और त्याग वृत्ति ने वही काम एक रक्तहीन शान्ति के रूप में, सरदार पटेल के द्वारा करा दिया।

इस विषय में भारतीय रियासतों पर प्रकाशित श्वेत पत्र के पहले पृष्ठ पर निम्नलिखित वाक्य में शासकों की सराहना की गई है

‘छोटे-बड़े समस्त राजाओं ने युग के अनुरूप स्वयं को वातकर इस भावना

धारणा के खण्डन करने में अपना अपूर्व सहयोग दिया कि भारतवर्ष की स्वाधीनता राजा-महाराजाओं के दुराग्रह की गिला से टकरा कर धूर-धूर हो जायेगी । लोकतन्त्र भारत का भवन भारत के राजा-महाराजाओं तथा जन-साधारण के समन्वित प्रयत्न की सच्ची आधारगिला पर खड़ा है ।'

यह राजा-महाराजाओं के आत्मोत्सर्ग का ही फल है कि आज भारत कई शताब्दियों के बाद, एक सांविधानिक मत्ता के रूप में खड़ा है और उसने राजनीतिक एकीकरण के आदर्श रूप को प्राप्त किया है । शासकों के स्व-उन्मूलन ने भारत के इतिहास को एक नवीन दिशा प्रदान की है । 'राजा-महाराजाओं के देशभक्तिपूर्ण सहयोग के बिना, जन-साधारण एवं शासकों के परस्पर कल्याण की दिशा में हुआ भारत में यह विशाल परिवर्तन सम्भव ही नहीं था । व्यक्तिगत शासन की पद्धति के अभ्यस्त शासकों के लिए यह नयी व्यवस्था एक आमूल-धूल परिवर्तन के समान है । उन्होंने इस परिवर्तन को शान्तिपूर्वक अपनाकर कल्पना, दूरदर्शिता एवं देशभक्ति का परिचय दिया है । जनहित एवं जन-भावना को पहचान कर उन्होंने अपनी रियासतों को भारत में विलय कर दिया तथा उनकी मत्ता जनसाधारण को अन्तर्लित कर दी । वे स्वयं को उस स्वतन्त्र एवं लोकतान्त्रिक भारत का सह-गिल्पी कह सकते हैं, जिसमें प्रान्तों एवं रियासतों के लोग स्वाधीनता का समान रूप में समाश्वादन करेंगे और स्वतन्त्र भारत के नागरिकों के रूप में एक साथ आगे बढ़ेंगे ।'

—भारतीय रियासतों पर श्वेत पत्र, पृष्ठ 146-147

रियासतों की देन

भारतीय अधिराज्य का कुल क्षेत्रफल 12,60,853 वर्गमील है, जिसमें 5,87,949 वर्गमील का क्षेत्र इन रियासतों की देन है । हमारे शब्दों में गण-तन्त्र भारत के क्षेत्रफल का 47 प्रतिशत भू-भाग इन रियासतों का योगदान है । 84,471 वर्गमील वाली जम्मू एवं काश्मीर रियासत तथा 82,213 वर्गमील वाली हैदराबाद रियासत इन रियासतों में सबसे बड़ी थी । 10,000 वर्गमीलसे अधिक क्षेत्र वाली 15 रियासतें थी 1000 और 10,000 वर्गमील के बीच के क्षेत्र वाली 67 रियासतें थी तथा 10 वर्गमील से कम क्षेत्र वाली 202 रियासतें थी ।

संविलयन अनुबन्ध एवं प्रसंविदाएँ

26 जनवरी 1950 अर्थात् गणतन्त्र भारत के जन्म तक 554 रियासते भारत में मिल चुकी थी तथा उन्होंने स्वयं को गणतन्त्र के रंग में रंग लिया था। इन रियासतों के शासकों ने 'संविलयन प्रालेख' (इस्ट्रुमेंट्स आफ एक्सेसन) पर हस्ताक्षर कर के गणतन्त्र की आधार-शिला को सुदृढ़ बना दिया था। इनमें से 551 रियासतें तो 15 अगस्त 1947 के पहले ही भारतीय अधिराज्य में विलय हो गई थी, किन्तु तीन बार में पर 26 जनवरी 1950 के पहले ही विलय हुई।

संविलयन प्रालेखों (इस्ट्रुमेंट्स आफ एक्सेसन) के बाद संविलयन अनुबन्धों या प्रसंविदाओं (मर्जर ऐग्रीमेंट्स और कांवेनेण्ट्स) पर हस्ताक्षर हुए, जिसके फलस्वरूप 216 रियासतें तो अपने-अपने सलग्न प्रदेश—राज्यों में विलीन हो गईं, 61 रियासतें सीधी केन्द्रीय अनुशासन के भीतर आईं तथा 275 रियासतें नये राज्यों के रूप में परिणत हो गईं। केवल दो रियासतें—हैदराबाद और काश्मीर ने—इन अनुबन्धों पर हस्ताक्षर नहीं किए और वे गणतन्त्र भारत में नये प्रदेशों के रूप में सामने आईं।

संविलयन प्रालेखों के अन्तर्गत तो रियासतों ने केवल तीन विषय - प्रति-रक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध एवं संचार—अधिराज्य सरकार को सौंपे थे तथा शेष विषयों में उनकी प्रभुता स्वतन्त्र रही थी, किन्तु संविलयन अनुबन्धों और प्रसंविदाओं पर हस्ताक्षर करके रियासतों के शासकों ने अपनी सम्पूर्ण शासन-सत्ता एवं रियासत की क्षेत्रीय अखण्डता अधिराज्य सरकार को सौंप

की जिसके फलस्वरूप ये रियासत गणतन्त्र भारत के सवधानिक एवं राजनतिक जीवन का एक अंग बन गइ और उनकी स्वतन्त्र सत्ता समाप्त हो गई ।

सविलयन अनुबन्ध का और प्रसविनामा का अन्तर्गत भारतीय नरेशों को यह बचन दिया गया था कि उनके व्यक्तिगत अधिकार एवं विशेषाधिकार बचावत रहेंगे तथा उनके प्रिवापस बचानू रहेंगे । जसा कि मार्च 1950 में भारत सरकार ने भारतीय रियासतों पर ह्वेन पण्ड प्रकाशित कर स्थापित किया था

“प्रत्येक सभों की स्थापना करने वाले सविलयन अनुबन्ध तथा प्रसविदा हस्ताक्षरकर्त्ता शासकों के लिये अन्तिम अनुबन्ध हैं । जहां इनके अन्तर्गत रियासतों का एकीकरण तथा शासकों में सत्ता हस्तांतरण का विधान है वहां शासकों का प्रियोपस की गददी का उत्तराधिकार की, व्यक्तिगत अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति (रियासत की सम्पत्ति में मिन) का स्थायित्व एवं उसके उपयोग उपयोग की पूर्ण गारंटी दी जाता है ।

शासकों का व्यक्तिगत अधिकारों विशेषाधिकारों एवं प्रियोपसों का सम्बन्ध में सभी सविलयन अनुबन्ध तथा प्रसविदाओं में इस प्रकार की व्यवस्था मौजूद पाई जाती है । भारत सरकार प्रत्येक सविलयन अनुबन्ध में एक सविनाकारी, प्रत्येक प्रसविदा में सहमति देने वाली एवं उसमें लिखित प्रत्येक व्यवस्था की गारंटी करने वाली है । ग्वाणिशर इंदौर एवं मध्य भारत की कुछ अन्य रियासतों को मिला कर ग्वाणियर इंदौर एवं मातवा का समुक्त प्रान्त (मध्य भारत) बनाते समय इन रियासतों का शासकों तथा भारत सरकार के बीच जो प्रसविना हुआ था उसका प्राक्कथन एवं कुछ प्रत्योचित धाराओं का अवलोकन से यह सभी प्रकार स्पष्ट हो जाता है । उसमें लिखा गया है कि

ग्वाणियर इंदौर तथा मध्य भारत की कुछ ॥ रियासतों का हम शासक लोग इस बात पर सहमत होकर कि इस क्षेत्र के लोगों का दिन इसा में है कि हमारी रियासतों का एकीभूत कर का एक नया प्रान्त बना दिया जाए जिसमें साव कार्यो हो साव विधानाग हा तथा साव व्यापार हो तथा यह निषेध करने कि (भारतीय सविधान का अन्तर्गत) इस प्रान्त के सांख्यिक सविधान के बनाने का काम जनता का निर्वाचित प्रतिनिधियों की सविधान मन्त्री को हो दिया जाए ।

भारत सरकार को सहमति एवं गारण्टी मिलने के बाद, निम्नलिखित प्रसविदा करते हैं—

धारा ११

- (1) प्रत्येक प्रसविदाकारी रियासत के शासक को संयुक्त प्रदेश के राजस्व से प्रतिवर्ष अपने प्रिवीपर्स के रूप में उतनी राशि लेने का अधिकार होगा जितनी कि अनुसूची 1 में उस प्रसविदाकारी रियासत के नाम के सामने लिखी है।

ग्वालियर एवं इन्दौर रियासतों के सामने लिखी प्रिवीपर्स की यह राशि केवल वर्तमान शासकों को मिलेगी, उनके उत्तराधिकारियों को नहीं। उत्तराधिकारियों के लिए इस सम्बन्ध में नयी व्यवस्था की जाएगी।

- (2) उपरिलिखित धन राशि देने का लक्ष्य यह है कि शासक तथा उसके परिवार के समस्त खर्च इससे चलते रहे। इन खर्चों में परिवार में होने वाले विवाह, मनाये जाने वाले उत्सव, निवास-स्थानों की देखरेख आदि पर होने वाले समस्त खर्च शामिल हैं। यह राशि अनुच्छेद (1) की व्यवस्था के अधीन है तथा किसी भी कारण से न बढ़ाई जाएगी और न घटाई जाएगी।

- (3) यह राजप्रमुख की जिम्मेदारी है कि वह उपरिलिखित धनराशि प्रत्येक शासक को तिमाही के प्रारम्भ में दे दे। इस प्रकार यह राशि चार समान किस्तों में दी जाएगी।

- (4) उक्त धनराशि समस्त करो से मुक्त होगी चाहे वे कर संयुक्त प्रदेश की सरकार ने लगाए हो चाहे भारत सरकार ने।

धारा १३

प्रत्येक प्रसविदाकारी रियासत के शासक तथा उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, आदर-सम्मान तथा उपाधि-पदों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आएगा। जिस रूप में ये चीजें 15 अगस्त 1947 के दिन के एकदम पहले हैं, अविष्य में यथावत् रहेगी।

बिल्कुल यही बात भारतीय नरेशों के प्रिवापसों एवं विनोपाधिकारों के विषय में है—उन्होंने अपनी रियासतों व शासन दत्ता भारतीय अधिराज्य को सौंप दी। किंतु अपने व अपने परिवार के लिये रियासत की वापिस आय का कुछ अंश प्रिवापस के रूप में निश्चित कर लिया और साथ ही कुछ अधिकार भी अपने पास रख लिये।

य अनुबंध एवं प्रसविदामें सविधान लागू होने से पहले की हैं और सभी से लागू भी है। सविधान समाजो सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न थी उसने इन अनुबंध एवं प्रसविदाओं को उनके उसी रूप में स्वीकार करके एक प्रकार से अपने रजिस्ट्रेशन की मुहर लगा दी। भारत सरकार तो यहस्था के लिये एक ट्रस्ट है। उन यह अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है कि नरेशों के प्रिवापसों एवं विनोपाधिकारों को बिना उनकी इच्छा के बलपूर्वक छीन ले ?

प्रिवापसों एवं विनोपाधिकारों को यथावत् बने रहने देने में तो सरकार की कोई उदारता नहीं है। छीन लेने में कोई मानी अवश्य है।

वास्तव में सविधान अनुबंधों एवं प्रसविदाओं पर नरेशों के हस्ताक्षर कराने के लिये उपाधियों एवं विनोपाधिकारों की गारंटी ही ऐसा आश्वासन था, जिसके कारण उन्हें अपनी रियासतों को भारत में विलीन कराने में कोई हिचक नहीं हुई। उन्होंने सोचा—यह ऐसा समझौता है, जिसमें हमारा सम्मान भी बना रहगा और प्रजा का भी हित हो जायेगा।

आज तक कभी किसी नरेश ने अपने विनोपाधिकारों का प्रयोग नहीं किया ?

सरकारने अनुसूचित जातियों और कबीलाओं को भी तो कुछ विनोपाधिकार दे रखे हैं। इनसे जातिवाद को तो प्रोत्साहन मिल ही रहा है सरकारी नौकरियों व चुनावों में अब जातियों के अधिकारों का भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है।

सरकार को चाहिये पहले इन बनावटी और जातिवाद का प्रोत्साहन देने वाले विनोपाधिकारों का समाप्त करे, जिनके उपयोग और दुरुपयोग से समाज के अवाञ्छनीय एवं विषमभाव पैदा हो रहे हैं अनुशासनहीनता बढ़ रही है और शान्ति का गला घुट रहा है।

रही नरेशों की उपाधियाँ की बात—आज भी भारत सरकार पदम भूषण पदमश्री व भारतरत्न इत्यादि सम्मानसूचक उपाधियाँ देती है।

ताओ को चाहे उस विषय का ज्ञान न हो, किन्तु विश्वविद्यालय उन्हें किसी विशेष विषय में 'डाक्टर' की उपाधि देकर सम्मानित कर देते हैं।

जिस वंश में शताब्दियों से जनता द्वारा मान्य उपाधियाँ चली आ रही हैं, उन्हें एकदम मिटाया नहीं जा सकता।

ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई, रायसाहब, रायबहादुर आदि उपाधियाँ तो दासता की प्रतीक हैं अब वे सम्मान की वस्तु नहीं रही, फिर भी अब तक इनके प्राप्त कर्त्ताओ को इन उपाधियों के नाम से ही सम्बोधित किया जाता है।

प्रायः यह भी देखा जाता है कि किसी सम्मानित पद से अवकाश ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपने उसी पद के नाम से पुकारा जाता है। कलक्टर अवकाश ग्रहण करने पर भी कलक्टर ही कहलाता है, यद्यपि उसके पास अधिकार कलक्टरों के नहीं होते। जज न्याय का काम नहीं करता, फिर भी जज साहब ही कहलाता है, सेना के अफसर भी अवकाश ग्रहण करने पर मेजर, कप्तान, जनरल आदि अपने-अपने पदों के नाम से ही जनता में जाने पहचाने जाते हैं।

जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। जो जमींदार राजा कहलाते थे, उन्हें अब राजा कहलाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी जनता उनको राजा साहब ही कहती है। उनके बच्चे कुंवर साहब कहलाते हैं। अभी न जाने कब तक वे राजा साहब ही कहलायेंगे और उनका घराना, राजघराना कहलाता रहेगा। इस बात को कानून बना कर रोक नहीं जा सकता।

यदि नरेशों की यह उपाधियाँ, सधि तोड़ कर, सरकारी तौर पर हटा भी दी जायें, तो इनका हटाना केवल कागजी ही रहेगा। जनता तो उन्हें उसी नाम से पुकारेगी, वैसे ही श्रद्धा रखेगी।

प्रिवीपर्स

भारत सरकार ने नरेशों के प्रिवीपर्स रियासतों के क्षेत्रीय नेताओं व शासकों की सहमति से निश्चित किये थे। यह प्रिवीपर्स भारतीय अधिराज्य में विलय होने वाली 554 रियासतों में से केवल 284 रियासतों के लिए

निश्चित किये गये। पाप 270 छोटी छोटी रियासतों का, जो क्षेत्रफल की दृष्टि में बहुत छोटी तथा सीमित आय वाली थी, एक निश्चित धनराशि दे दी गई।

प्रिवीपस पाने वाला इन 284 रियासतों के मन्तव्यों में से 179 का एक लाख रुपये से कम, 78 को एक से पाँच लाख रुपये के बीच 13 को पाँच से दस लाख के बीच और 11 को दस लाख रुपये से ऊपर वार्षिक प्रिवीपस दिया जाता है।

प्रिवीपसों की अन्वयणी के लिये भारत सरकार ने रियासतों की कुल आय का 5 से लेकर 15 प्रतिशत तक देना निश्चित किया था। किन्तु वह दस लाख रुपये वार्षिक से अधिक किसी को देना नहीं चाहती थी। रियासतों में 11 रियासत ऐसी थी जो क्षेत्रफल में दस हजार वर्गमील से भी बड़ी थी और जिनकी आय भी बहुत अधिक थी। उन्हें 5 प्रतिशत प्रिवीपस भी दिया जाता था वह बहुत अधिक बँटता था। उनके व उनके परिवार वालों के पक्ष में बहुत अधिक था। तब इन ग्यारह रियासतों के लिए वहाँ के शासकों को मनाया एवं क्षेत्रीय नेताओं की राय से उनके लिये जो प्रिवीपस निश्चित किये गये उनका सम्मेलन यह रहा कि यह धनराशि इन रियासतों के केवल वर्तमान शासकों को ही मिलेगी। उत्तराधिकारी शासकों को एक के बाद दूसरे उत्तराधिकार के साथ यह प्रमश कम होती चली जायगी।

अधिक प्रिवीपस पाने वाले के ग्यारह शासक निम्नलिखित हैं —

- 1 हिज हाईनेस, निजाम हैदराबाद 50 लाख रुपये
- 2 हिज हाईनेस महाराजा बडौला 26 लाख 50 हजार
- 3 हिज हाईनेस महाराजा मयूर, 26 लाख
- 4 हिज हाईनेस महाराजा ग्वातिवर, 25 लाख
- 5 हिज हाईनेस महाराजा टावनकार, 18 लाख
- 6 हिज हाईनेस महाराजा जयपुर 18 लाख
- 7 हिज हाईनेस, महाराजा जायपुर 17 लाख 50 हजार
- 8 हिज हाईनेस महाराजा बीकानेर, 17 लाख 50 हजार
- 9 हिज हाईनेस महाराजा पटियाला, 17 लाख
- 10 हिज हाईनेस महाराजा इंदौर, 15 लाख

11 हिज हाईनेस, नवाब भूपाल, 11 लाख

इन रियासतों के विलयन के समय—सन् 1948 में नरेशों को प्रिवीपर्स के रूप में दी जाने वाली कुल धनराशि पाँच करोड़ सत्तर लाख रुपये वार्षिक थी।

इस समय उपरोक्त ग्यारह रियासतों के तत्कालीन शासकों में से अधोलिखित की मृत्यु हो जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी शासकों के प्रिवीपर्स की धनराशि कम कर दी गई है —

- 1 हिज हाईनेस, हैदराबाद, 50 लाख से घटाकर 20 लाख
- 2 हिज हाईनेस, बडौदा, 26 लाख 50 हजार से घटाकर 14 लाख 54 हजार।
- 3 हिज हाईनेस, ग्वालियर, 25 लाख से घटाकर 10 लाख
- 4 हिज हाईनेस, बीकानेर, 17 लाख 50 हजार से घटाकर 10 लाख
- 5 हिज हाईनेस, इन्दौर, 15 लाख से घटाकर 5 लाख
- 6 हिज हाईनेस, भूपाल, 11 लाख से घटाकर 6 लाख 70 हजार

प्रिवीपर्स पाने वाले 279 शासकों में से भी 100 से अधिक तो जागीरदार, ताल्लुक्दार आदि थे, उनमें कुछ तो कुछ सैकड़ों में ही प्रिवीपर्स पाते हैं, जैसे गुजरात में कटौदिया के राजा को, सबसे कम केवल 192 रुपये वार्षिक प्रिवीपर्स मिलता है। केवल 13 शासकों को पाँच लाख रुपये से अधिक मिलता है।

अनुबन्धों एवं प्रसविदाओं के अनुसार ग्यारह बड़ी रियासतों के शासकों को छोड़कर यद्यपि प्रिवीपर्स की धनराशि न तो घटाई जा सकती है और न बढ़ाई जा सकती है, फिर भी पाँच लाख में अधिक पाने वाले 24 नरेशों में से 9 की मृत्यु हो जाने के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने स्वयं ही प्रिवीपर्सों की धनराशि घटाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। यही घटी हुई धनराशि भी 81 लाख रुपये से अधिक है।

5 रियासतों के शासकों की मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी न होने से प्रिवीपर्स बन्द भी हो गया है।

इस प्रकार सन् 1948 में प्रिवीपर्स के रूप में दी जाने वाली पाँच करोड़ 70 लाख की वार्षिक धनराशि 1968 में घटकर चार करोड़ बयासी लाख रह गई है। इसी प्रकार यह शर्न शर्न कम होती चली जा रही है। और एक दिन ऐसा आयेगा कि पूरी तरह समाप्त हो जायेगी।

घरों भी भारत के 3000 करोड़ के बजट में दोन पाँच करोड़ की बचत की है महत्व नहीं रखती। जबकि इन बचत के दुष्परिणाम प्रकट हो समाज पर अपना गहरा प्रभाव डालेंगे।

जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है उच्च रतन गल्ले में बचत परियोजना का मुद्दा है और घटावर होता जा रहा है। धार धार व आम नागरिक जमा जीवन अपनाता जा रहा है। कुछ ने निजि व्यापार आरम्भ कर दिया है कुछ में उद्योग में समा गया है और कुछ ने कृषि पाम बना लिया है। इनमें जहाँ तक व्यक्तिगत व्यय की बात है व किसी न निमा प्रकार आन आन की परित्यक्तियाँ व अनुसंधान व्यय किया कर लगे।

किंतु हमारे तद्विधान के अनुसार वे धातु भी राजा महाराजा हैं। इसी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये उनका प्रिवीपत्तों का अधिकार भाग उन हजारों लोगों पर व्यय होता है जो उनका यहाँ सब भी काम पर लगे हुए हैं और जिन्हें उन्होंने रियासतों के विसीनीकरण के उपरान्त भी सेवा निवृत्त नहीं किया। इसमें नौकर खाकर खपराती बत्तक और आपातर सभी धनी के लोग हैं। उनकी रियासत के सबको लोग अब भी घर बैठे वेगन पा रहे हैं जिनका भुगतान प्रिवीपत्तों की धनराशि से ही होता है। प्रिवीपत्तों की समाप्ति इन सबको बेकार कर देगी। उन हजारों लोगों और उनके परिवारों का क्या होगा? क्या भारत सरकार उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगी? प्रिवीपत्तों की इस पीने पाँच करोड़ व्ययों का बचत से जो कुल बजट का 0.00 भाग से कम है क्या बजट में तो कोई लाभ नहीं होगा हाँ क्या वे बढ़ती हुई महंगाई और बेकारी के युग में हजारों परिवार अस्त व्यस्त अवश्य हो जायेंगे।

इस समय में जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनकी ओर सरकार ध्यान दे तो करोड़ों व्ययों की आय बढ़ सकती है—

आयकर का करोड़ों रुपया खिंचा लिया जाता है करोड़ों वसूल नहीं हो पाता। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुये 11 वर्ष हो गये धातु भी उसमें न जान कितनी अनियमितताये भरी पड़ी हैं जिनका दूर करने से करोड़ों का लाभ हो सकता है। अ. व. नो का भी यही हास है।

और फिर नरेशों को दी हुई धनराशि जाती कहाँ है?—चीन व पाकिस्तान से मुद्रा के समय नरेशों ने करोड़ों रुपया राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया। जब भी भारत सरकार या राज्य सरकारें ज्वला से श्रम लेन के लिये

‘बॉन्ड्स’ जारी करती हैं. नरेश करोड़ों रुपये के ‘बॉन्ड्स’ खरीद लेते हैं। क्या प्रिवीपर्स समाप्त हो जाने के बाद नरेशों के हृदय में इस तरह के योगदान का कोई उत्साह रह जायेगा ?

विशेषाधिकार

नरेशों के विशेषाधिकार की यद्यपि स्वाधीनता-प्राप्ति के पूर्व कोई पूर्ण सूची बनी नहीं थी और न ही ऐसा करना कभी श्रेय समझा गया था, किन्तु भारत सरकार ने प्रत्येक नरेश के साथ अलग अलग सविलयन प्रालेखों तथा सविलयन अनुबन्धों अथवा प्रसविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। इसीलिए शासकों के अधिकार भी अलग अलग हैं। एक रियासत में कुछ है तो दूसरी में कुछ। और इनका ‘उपयोग भी रियासत के भीतर व बाहर दोनों ही क्षेत्रों में किया जा सकता है। भारत सरकार के गृह मन्त्रालय से प्राप्त सूची के अनुसार उसका शीर्षक है ‘इलस्ट्रेटिव आफ पर्सनल प्रिविलेजेंज गारन्टीड टू रूलस आफ दि फार्मर इण्डियन स्टेट्स’ (भूतपूर्व भारतीय रियासतों के शासकों के प्रतिभूत व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की निदर्शी सूची)। इसके अन्तर्गत निम्न-लिखित 23 विशेषाधिकार सूचीबद्ध हैं

- 1 शासकों एवं उनके परिवारों के लिए सरकारी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था,
- 2 शासकों के अधिकारी निवासों पर सशस्त्र प्रामाद-रक्षकों की व्यवस्था,
- 3 अपेक्षित भुगतान करने पर यात्रा करते समय शासकों एवं उनके परिवारों को अगर्क्षक सुलभ कराने की व्यवस्था,
- 4 अपने निवासों, कारों तथा वायुयानों पर शासकों एवं उनके सहचरों को अपनी पताका फहराने का अधिकार,
5. भारतीय सशस्त्र अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत शासकों एवं उनके परिवारों को कुछ विशिष्ट छूट दी गई है अर्थात् वे कुछ विशिष्ट प्रकार के सशस्त्र बिना लाइसेंस के रख सकते हैं,

- 6 शासको का प्रिवीपग आयकर तथा अधिकर (अतिरिक्त आयकर) शीना करा से मुक्त रहेगा तथा उनकी गणना उनकी कुल आय एवं विदेश आय में नहीं की जाएगी
- 7 शासका के अधिकारी विद्यालयों की भांति राशि पर मरबन कर नहीं लगगा
- 8 मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत शासका को जिना गुल्म नियम अपनी कारों रजिस्टर कराने तथा अपने लिए ड्राइवर साइसत लेने का अधिकार होगा
- 9 स्थानीय कराधान से शासका को प्रमुक्ति (एट) देने का नियम सम्बन्धित प्रदेशों की सरकारें करेंगी जहाँ तक होगा वहाँ तक 15 अगस्त 1947 के पटन की स्थिति का चालू रखने का प्रयत्न किया जायेगा। प्रदेश सरकारों को यह निर्देश दे दिया गया है कि यदि भूतपक्ष विरासतों के लक्षों में भवन कर लगाया जाय तो शासका के निवासों का इससे मुक्त रखा जाए।
- 10 शासका की जागीरों तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति को करा से मुक्त रखने या न रखने का नियम सम्बन्धित प्रदेश सरकारें करेंगी। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में यह इच्छा भी व्यक्त कर दी है कि सामान्यतः ऐसे मामलों को भू राजस्व अधिनियम के अधीन सुलझाया जाए
- 11 शासका का अग्र सम्मानाधिकार 15 अगस्त 1947 के पहले के समान रहेगा
- 12 शासकों की अपनी कारों पर साल नम्बर प्लेटें लगाने का अधिकार होगा
- 13 दस या दस से अधिक तोपों की सलामी पाने वाले शासका के साथ जाने या जाने वाला सामान तथा उनीस या उनीस से अधिक तोपों की सलामी पाने वाले शासका के साथ या अलग से जाने या जाने वाला सामान आयात निर्यात कर से मुक्त होगा। उनीस या उनीस से अधिक तोपों की सलामी पाने वाले शासकों तथा उनके पारिवारिक समस्या के व्यक्तिगत उपयोग के लिए ली गई चीजों पर भी आयात निर्यात कर नहीं लगेगा। उनीस

या उन्नीस से अधिक तोपो की सलामी पाने वाले शासको द्वारा खरीदे गए पेट्रोल पर दिया जाने वाला उत्पादन शुल्क उन्हें वापस कर दिया जाएगा ,

- 14 किसी शासक के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने से पहले भारत सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा ,
15. शासको को उनकी मान्यता-प्राप्त उपाधियों से सम्बोधित किया जाएगा ,
- 16 शासको के मछली पकड़ने तथा शिकार करने के अधिकार सुरक्षित रहेंगे ,
- 17 सविलयन के पूर्व जो शासक भारतीय सेना की टुकडिया रखते थे, उनके या उनके सहचरो के या उनके युवराजो के अन्तिम सस्कार के समय उन्हें सैनिक सम्मान मिलेगा, बशर्ते कि इसका वहाँ तुरन्त प्रबन्ध हो सके ,
- 18 शासको की सहमति लिए बिना तथा बिना उनको उचित क्षतिपूर्ति दिये, उनके निवास के लिए उपयुक्त होने वाली उनकी भू-सम्पत्ति को न अधिग्रहीत किया जाएगा और न अभिग्रहीत ,
- 19 शासको से उनकी भूतपूर्व रियासतो मे स्थित हवाई अड्डो पर उनके हवाई जहज उतारने का कोई शुल्क नही लिया जायेगा ,
20. शासको की भूतपूर्व रियासतो मे स्थित उनके निवासो मे खर्च होने वाली विजली एंव पानी का मूल्य नही लिया जाएगा । यह छूट केवल कुछ शासको को ही मिलेगी ,
- 21 भूमि के अनिवार्य अभिग्रहण से प्रमुक्ति । यह प्रमुक्ति केवल कुछ शासको को ही है ,
- 22 भूतपूर्व रियासती क्षेत्रो मे शासको के जन्म-दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी । यह अधिकार भी केवल कुछ विशिष्ट शासको को ही प्राप्त होगा , तथा
- 23 कुछ विशिष्ट शासको को (यह वर्गीकरण तोपो की सलामी पर आधारित है) डाक-तार की विशिष्ट सुविधाएं जैसे नि शुल्क रेडियो-लाइसंस तथा तार देते समय प्राथमिकता मिलेगी ।

इन विशेषाधिकारो की जितनी चर्चा हो रही है, यदि इन्हे व्यवहार की

कसीटी पर कम कर देखा जाए तो इनमे ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस इतना तूल दिया जाता जरूरी हो। इस सदन में इन विधेयाधिकारों के स्वरूप पर चर्चा करना असम्भव न होगा। देखिये —

- 1 सरकारी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा—देश के प्रत्येक नागरिक का यह सुविधा प्राप्त है और भूतपूर्व नरेश भी देश के नागरिक है। तब इसमें विधेयाधिकार कहीं से घुस गया। दूसरे ऐसा कौन नरेश होगा जो इलाज क चक्कर में अस्पतालों क चक्कर काटता फिरगा।
- 2 अधिकारी निवास पर सशस्त्र रक्षक यह सुविधा भी प्रत्येक नागरिक को है। यदि किसी नागरिक का अपनी जान माल का खतरा महसूस होता हो तो वह नगर अधिकारियों से प्रायना करके अपने निवास पर सशस्त्र रक्षक तनात करा सकता है।
- 3 यात्रा के समय अगरदाक इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए नरेशों को भुगतान करना पड़ता है। जब भुगतान हो जाता है तब मर करारी अगरदाक क्या और गर सरकारी क्या।
- 4 यह सुविधा भी प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। आपका यह स्वतन्त्रता है कि आप राष्ट्रीय ध्वज अर्थात् तिरंगे झंडे के अनुरिक्त किसी भी प्रकार का ध्वज अपने निवास पर फहराए अपना कार पर फहराए और यदि वायुयान हो तो उस पर भी फहराए। 15 अगस्त के दिन आप राष्ट्रीय ध्वज भी फहरा सकते हैं। फिर उसम नरेशा का कौन सा विधेयाधिकार प्रदान किया गया है।
- 5 कुछ विविष्ट प्रकार के गस्त्र बिना लाइसंस के रखने का अधिकार अवश्य विधेय है, वस लाइसंस प्राप्त करके गस्त्र कोई भी रख सकता है।
- 6 आयकर एवं अधिकार स मुक्ति केवल प्रिवीपस के रूप में प्राप्त राशि पर है। नरेशा की गैर आय पर (यदि कुछ है तो) नही।
- 7 कोई विधेय राशि नहीं बनती।
- 8 नरेशों को मोटर गाड़ी अधिनियम की सभ्यत धाराओं का पालन तो एक सामान्य नागरिक के समान ही करना है बस कार रजिस्टर कराने या अपना ड्राइविंग लाइसंस लेने की फीस जहा देनी होगी। अर्थात् कुछ थोड़े-से रूपों की वधन है बस।

9. स्थानीय कराधान से नरेशों को छूट देना या न देना सम्बन्धित प्रदेश सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। यह नरेशों का अधिकार नहीं है। हाँ, उनके मुख्य आवास को हाउस-टैक्स से मुक्त करना जरूर एक सुविधा है। किन्तु यह भी आर्थिक लाभ है और वह भी कोई बहुत अधिक नहीं है।
10. जागीर एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति को करो से मुक्त करना या न करना प्रादेशिक सरकारों की इच्छा पर निर्भर है। नरेशों का अधिकार यह भी नहीं है। और भू-राजस्व अधिनियम तो फिर भी लागू है ही।
- 11 यह विशेषाधिकार केवल नाम का है। व्यवहार में इसका मूल्य नहीं है। आज उन नरेशों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ राष्ट्र की एकता के लिए त्याग दिया है, किसी अग्र-सम्मान की व्यवस्था नहीं है। सिक्किम, भूटान आदि भी तो रियासते ही हैं। यदि आज इनके नरेश दिल्ली पधारते हैं तो भारत के राष्ट्रपति उनके स्वागत के लिए पालम हवाई अड्डे पर पहुँचते हैं किन्तु, यदि भारत की भूतपूर्व रियासतों के नरेश नयी दिल्ली आते हैं तो उनका किसी को पता भी नहीं चलता। उनका दोष केवल इतना है कि उन्होंने अपनी रियासतों को भारत सघ में विलीन करके अपना प्रथक अस्तित्व समाप्त कर दिया है।
12. कार पर लाल नम्बर प्लेट लगाने से क्या अन्तर पड़ता है। और सब नरेश लाल प्लेट लगाते कहाँ हैं? यदि कभी अपनी भूतपूर्व रियासतों में जाते हैं तो भले ही इस अधिकार का उपयोग कर लेते हों।
13. इस कोटि में बहुत कम नरेश आते हैं। उन्नीस तोपों की सलामी लेने वाले नरेश केवल 6 हैं और इसके ऊपर 21 तोपों की सलामी लेने वाले केवल 5। दस तोपों से ऊपर वालों की भी कोई अधिक सख्या नहीं है।
- 14 यह कोई विशेषाधिकार नहीं है; वल्कि नरेशों को व्यर्थ के झमेलों से बचाने का उपाय मात्र है। नरेशों पर मुकद्दमा तो हर तरह का चलाया जा सकता है और कोई भी चला सकता है। शर्त केवल इतनी है कि उसके लिए केन्द्रीय सरकार से पहले अनुमति लेनी

हागी। यदि मामला उचित है और नरेग पर मुकद्मा चलाना "यायसगत" है तो भारत सरकार उसको तुरन्त अनुमति देती है और अतीत में देती भी रही है। इसलिए इस विन्याधिकार का यह अर्थ नहीं है कि नरेगा पर मुकद्मा नहीं चलाया जा सकता बल्कि इसका अर्थ यह है कि उन्हें व्यय में कोई भूख मुकद्मा चला कर परेशान न करे।

- 15 सिव सज्जन को सरगारजी, ब्राह्मण बधु को पंडितजी तथा मस्जिद के अधिष्ठाता को 'मौलवी' कह कर सम्बोधन करते हैं उसी प्रकार नरेश मण्डल के सदस्य का 'महाराज' कह कर सम्बोधन करते हैं। इसमें विन्याधिकार के हम तो कहीं दखल नहीं हुए।
- 16 आजकल नरेगो के पास इतना समय नहीं है कि वे मछली पकड़ने या शिकार खेलने में व्यस्त रहें। यह भी केवल कागज पर लिखा विन्याधिकार है।
- 17 प्रथम तो यह अधिकार सब नरेशों को प्राप्त नहीं है। दूसरे यदि उस समय "यवस्था" हो तो यह सम्मान दिया जा सकता है। यह विन्याधिकार कहीं रहा। यह तो उस क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर है। यदि उन अधिकारियों को सुविधा प्रतीत होगी तो यह अंतिम संस्कार के समय सनिक सम्मान की "यवस्था" कर देंगे।
- 18 यह कोई विन्याधिकार नहीं है। एक सामान्य नागरिक की जमीन को भी बिना उसकी सहमति लिए और बिना उसे मुआवजा दिये सरकार नहीं ले सकती जब तक कि उसकी आवश्यकता किसी सावजनिक कार्य के लिए न हो। और बने हुए मकान आदि को सावजनिक कार्य के लिए भी नहीं लिया जा सकता। नागरिक होने के नाते नरेगो को भी यह अधिकार प्राप्त है।
- 19 यह विन्याधिकार केवल कागज की शोभा बढ़ाने के लिए है। आज किसी नरेश के पास वायुयान है ही नहीं, फिर उसके उतारने का प्रश्न ही नहीं पड़ा होता।
- 20 निवास के लिए मुफ्त बिजली पानी कोई विशेषाधिकार नहीं है। सरकार के मन्त्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह सुविधा प्राप्त है और नरेगो की तुलना में अधिक प्राप्त है।

- 21 यह अधिकार भी सब नरेशों को प्राप्त नहीं है ।
- 22 पहली बात तो यह कि यह विशेषाधिकार सब नरेशों को प्राप्त नहीं है और दूसरी बात यह है कि किसी नरेश के जन्मदिन पर किसी रियासती क्षेत्र में छुट्टी होती ही नहीं इसलिए यह भी केवल कागजी विशेषाधिकार है ।
- 23 पहली बात तो यह विशेषाधिकार सब नरेशों को प्राप्त नहीं है तथा दूसरी बात यह है कि आज यह सुविधा सब मन्त्रियों को प्राप्त है और ससत्सदस्यों को प्राप्त होने जा रही है ।

इस तरह हम देखते हैं कि नरेशों के यह विशेषाधिकार केवल नाम के ही हैं । वह उन्हें कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं कराते जो उनके त्याग को देखते हुए बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जा सके । जिन्होंने अपना सब कुछ देश के चरणों में अर्पण कर दिया, वह भी तब जब आत्मनिर्णय की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी ।

प्रिवीपर्स एंव विशेषाधिकारों का औचित्य

(अ) कानूनी पक्ष

भारतीय सत्रिधान की दृष्टि में

भारतीय सत्रिधान की जिन धाराओं का ग्रासको क प्रिवीपर्स, स्पष्टिगत अधिकारों तथा विनेषाधिकारों से सम्बन्ध है व है धारा 291, धारा 362 धारा 363 तथा धारा 366 (अड 15 एंव 22) । तुर त स दम के लिए वे धाराए यह उदघृत हैं

'291 ग्रासको क प्रिवीपर्स की रागि—सत्रिधान क सागू होने के पटल किसी भी भारतीय रिग्रासत के ग्रासक व साय जो भी अनुव ध या प्रसविदा हुआ है और उसके अतगत भारतीय अधिराय को सरकार ने उस ग्रासक को जो भी प्रिवीपर्स देने की गारण्टी दी है—

(अ) उसकी रागि भारत की समेकित निधि स दी जायेंगी और

(आ) ग्रासक को दी जाने वाली यह रागि सब प्रकार व आयकर स मुक्त होगी ।

362 भारतीय रिग्रासतना व ग्रासको क अधिकार एंव विनेषाधिकार—
देश की ससद् या प्रदग की विधान सभा द्वारा विधान बनाते समय तथा

केन्द्रीय या प्रादेशिक कार्याग द्वारा उस विधान को लागू करते समय भारतीय रियासत के शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा उपाध-सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसकी कि धारा 291 में उल्लिखित प्रसविदा या अनुबन्ध में गारण्टी दी गई है।”

“363 विशिष्ट सन्धियों, अनुबन्धों आदि से सम्बन्धित विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर प्रतिबन्ध—

(1) इस सविधान में किसी व्यवस्था के न होने पर किन्तु धारा 143 की व्यवस्थाओं के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह इस सविधान के लागू होने के पहले हुए किसी भी भारतीय रियासत के शासक और भारतीय अधिराज्य की सरकार या उसकी पूर्वाधिकारी सरकार के बीच सन्धि, अनुबन्ध, प्रसविदा, समझौता, सदन या इसी कोटि के किसी अन्य प्रालेख की किसी व्यवस्था के सम्बन्धित किसी विवाद के उठ खड़े होने पर (अथवा) किसी ऐसी सन्धि, अनुबन्ध, प्रसविदा, समझौता सनद या इसी कोटि के किसी अन्य प्रालेख से सम्बन्धित इस सविधान की किसी व्यवस्था के विषय में किसी विवाद के उठ खड़े होने पर, किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सके।

(2) इस धारा में—

(अ) ‘भारतीय रियासत’ से अभिप्राय है वह कोई भी प्रदेश, जिसे इस सविधान के लागू होने के पहले इंग्लैंड के बादशाह द्वारा या भारतीय अधिराज्य की सरकार द्वारा रियासत स्वीकार किया गया हो, तथा—

(आ) ‘शासक’ से अभिप्राय है राजा-महाराजा, सरदार या वह व्यक्ति, जिसे इस सविधान के लागू होने के पहले इंग्लैंड के बादशाह ने या भारतीय अधिराज्य की सरकार ने किसी भारतीय रियासत का शासक माना हो।

“366 परिभाषाएँ— इस सविधान में, जब तक कि सन्दर्भ में दूसरा अर्थ न लगता हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों को इस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है—

○ ○ ○

(15) ‘भारतीय रियासत’ से अभिप्राय उस प्रदेश से है, जिसे भारतीय अधिराज्य की सरकार ने मान्यता प्रदान की हो,

○ ○ ○

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में

यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि भारतीय रियासतें पूर्णतः स्वतंत्र तथा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न थीं और यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता था कि वे भारत या पाकिस्तान किसा एक अधिराज्य में मिल जाएँ अथवा अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखें। सत्य यह है कि शुरू में कुछ रियासतों ने स्वतंत्र रहने की इच्छा भी व्यक्त की थी। किंतु सरदार वल्लभभाई पटेल और उनका सुयोग्य सचिव श्री वी० पी० मनन की कुशल वात्सल्य के फलस्वरूप 554 रियासतों ने भारत में मिलने का निश्चय किया तथा बाद में सविलयन अनुबंध तथा प्रसविदाआ पर हस्ताक्षर हुए। जसा कि सरदार पटेल ने संविधान सभा में व्यक्त यह दंत हुए कहा था कि प्रिवीपंस एवं विवेकाधिकार तो शासकों के सत्ता त्याग एवं अपनी रियासतों को भारत में मिलाने की क्षतिपूर्ति रूप में दिये गए हैं। सविलयन विषयक समस्त समझौते दो स्वतंत्र एवं सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्याः भारत अधिराज्य एवं भारतीय रियासत— में हुए हैं इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत भारत सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि वह समझौते की शर्तों का पूर्णरूपेण पालन करे। यह कैसे सम्भव है कि भारत सरकार सविलयन का लाभ तो उठाती रहे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त जाएँ? प्रिवीपंस देने एवं विवेकाधिकारों का सम्बन्ध में भारत सरकार की एकतरफा अस्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में अपनी प्रतिज्ञा का निर्वनीय उल्लंघन है।

इस विश्वासघात का क्षमा करने के लिए तर्क सा भी कारण नहीं है। गलत बीस वर्षों में एक भी घटना ऐसी नहीं घटी जिसमें बल पर इस प्रतिज्ञा का उचित ठहराया जा सके। उदाहरण के लिए यदि कोई शासक पकड़ में बरता पाया जाता या उसकी रियासत का मात्र सम बंधन कराने के बाद अनपूर्वक भारत अधिराज्य में मिलाया जाता और भारत सरकार उस विशिष्ट शासक को प्रिवीपंस देने से या उसके विवेकाधिकारों को मानने से मना करती तो उसके इस कदम को व्यासंग्य माना जा सकता था। कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की एकतरफा अस्वीकृति के लिए केवल सत्ताहट दल या राजनीतिज्ञों के नित्य परिवर्तित पथा और नीतियों का पर्याप्त नहीं माना जा सकता। यदि ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं का मूल्य बाजार के टुकड़ों से अधिक नहीं है।

सविलयन प्रालेख और सविलयन अनुबन्ध अथवा प्रसविदा परस्पर सूत्रबद्ध है और ये एक ही ऐतिहासिक एव सांविधानिक प्रसंग के सोपान हैं। इनका पृथक्-पृथक् कोई अस्तित्व नहीं है अपितु ये तो एक ही शृंखला की कड़ियाँ हैं। इसलिए, सविलयन प्रालेख और त्रिवीपर्स एव विशेषाधिकारों की गारण्टी देने वाले सविलयन अनुबन्ध या प्रसविदा को पृथक् करना सम्भव नहीं है।

यह सर्वस्वीकृत तथ्य है कि दो सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों के मध्य हुए किसी समझौते से सम्बन्धित किसी विवाद के उठ खड़े होने पर केवल उस सन्धि की धाराओं का अध्ययन-विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं है अपितु उस सन्धि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सन्धि के समय हुई वार्ताएँ, विचार-विमर्श, वाद-विवाद एव घोषणाएँ आदि भी महत्वपूर्ण हैं। साथ ही इस सन्धि विशेष की ऐतिहासिक शृंखला से सम्बन्धित पुराने कागजात भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ऑपेनहेम के ग्रन्थ 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून' (8वाँ संस्करण) से निम्नलिखित अवतरण महत्वपूर्ण है

"यदि सन्धि की किसी धारा का अर्थ आमक है तो उस सम्पूर्ण सन्धि पर विचार करना चाहिए। ऐसा करते समय सन्धि के केवल शब्दों पर ही ध्यान नहीं देना है बल्कि उसके उद्देश्य तथा उसके किये जाने के समय की परिस्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए।" —पृष्ठ 953

"अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिव्यूनलो में सुसंस्थापित नियम है कि किसी सन्धि की विवादास्पद धारा की व्याख्या करते समय वे अपने सामने सन्धि के होने में पहले की वार्ताओं का रिकार्ड, तत्सम्बन्धी समितियों की बैठकों की वातचीत तथा सन्धि के अन्तिम प्रारूप तक पहुँचने के पहले के प्रारूप आदि को रख लेते हैं तथा उनका अध्ययन-विश्लेषण करते हैं।"

—पृष्ठ 957

"सन्धि होने के पूर्व उससे सम्बन्धित जितनी वातचीत हुई है, जितना भी विचार-विमर्श हुआ है तथा जितना भी प्रचार हुआ है, उस सब का रिकार्ड इस दृष्टि से महत्वपूर्ण साक्ष्य है।"

—पृष्ठ 958

प्रदेश (भू क्षेत्र) के स्वत्व-त्याग से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुच्छेद भी इसी ग्रंथ में सुलभ है :

"स्वत्व-त्याग का लक्ष्य है किसी ऐसे प्रदेश पर प्रभुत्व पाना जो अब तक किसी अन्य राज्य की सीमा में था। जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में

यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि भारतीय रियासतें पूर्णतः स्वतंत्र तथा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न थीं और यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता था कि वे भारत या पाकिस्तान, किसी एक अधिराज्य में मिल जायें अथवा अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखें। सत्य यह है कि गुप्त में कुछ रियासतों ने स्वतंत्र रहने का इच्छा भी व्यक्त की थी। किंतु सरदार वल्लभभाई पटेल और उनका सुयोग्य सचिव या वी० पी० मनन का कुशल धाता क फलस्वरूप 554 रियासतों ने भारत में मिलने का निश्चय किया तथा बाद में सचिबलय अनुबंधों तथा प्रसविदाओं पर हस्ताक्षर हुए। जसा कि सरदार पटेल ने सचिबलय सभा में वक्तव्य दत्त हुए कहा था कि प्रिन्सिपल एवं विनोदाधिकार तो शासकों के सत्ता त्याग एवं अपनी रियासतों को भारत में मिलाने की क्षतिपूर्ति रूप में लिये गए हैं। सचिबलय विषयक समस्त समझौतों का स्वयं न एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्यो भारत अधिराज्य एवं भारतीय रियासतों में हुए हैं, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत भारत सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि वह समझौतों की शर्तों का पूर्णरूप से पालन करे। यह कहे सम्भव है कि भारत सरकार सचिबलय का लाभ तो उठाती रहे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त जाए? प्रिन्सिपल एवं विनोदाधिकारों के सम्बंध में भारत सरकार की एकतरफा अस्वीकृति अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में अपनी प्रतिज्ञा का निन्दनीय उल्लंघन है।

इस विश्वासघात का क्षमा करने के लिए तर्क सा भी कारण नहीं है। गत बीस वर्षों में एक भी घटना ऐसी नहीं घटी जिसमें इन पर हम प्रतिष्ठा रण को उचित ठहराया जा सका। उदाहरण के लिए यदि कोई शासक पद पर बरत पाया जाता या उसकी रियासत का राज्य सम्पन्न व्यवहार करने का बाद वरपूजक भारत अधिराज्य में मिलाया जाता और भारत सरकार उस विनिष्ट शासक को प्रिन्सिपल देने से या उसका विनोदाधिकारों को मान्यता में मना करती तो उसके इस कृत्य को योग्यमान माना जा सकता था। किंतु एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि की एकतरफा अस्वीकृति का निष्फल सत्ताहक दल या राजनीतिज्ञों के नित्य परिवर्तित पक्षों और नीतियों का पर्याप्त नही माना जा सकता। यदि ऐसा होता है तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठाओं का मूल्य बाजार के टुकड़ों से अधिक नहीं है।

सविलयन प्रालेख और सविलयन अनुबन्ध अथवा प्रसविदा परस्पर सूत्रबद्ध है और ये एक ही ऐतिहासिक एव सांविधानिक प्रसंग के सोपान हैं। इनका पृथक्-पृथक् कोई अस्तित्व नहीं है अपितु ये तो एक ही शृंखला की कड़ियाँ हैं। इसलिए, सविलयन प्रालेख और प्रिवीपर्स एव विशेषाधिकारों की गारण्टी देने वाले सविलयन अनुबन्ध या प्रसविदा को पृथक् करना सम्भव नहीं है।

यह सर्वस्वीकृत तथ्य है कि दो सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यों के मध्य हुए किसी समझौते से सम्बन्धित किसी विवाद के उठ खड़े होने पर केवल उस सन्धि की धाराओं का अध्ययन-विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं है अपितु उस सन्धि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सन्धि के समय हुई वार्ताएँ, विचार-विमर्श, वाद-विवाद एव घोषणाएँ आदि भी महत्त्वपूर्ण हैं। साथ ही इस सन्धि विशेष की ऐतिहासिक शृंखला से सम्बन्धित पुराने कागजात भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। ऑपेनहेम के ग्रन्थ 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून' (8वाँ संस्करण) से निम्न-लिखित अवतरण महत्त्वपूर्ण हैं।

“यदि सन्धि की किसी धारा का अर्थ आमक है तो उस सम्पूर्ण सन्धि पर विचार करना चाहिए। ऐसा करते समय सन्धि के केवल शब्दों पर ही ध्यान नहीं देना है बल्कि उसके उद्देश्य तथा उसके किये जाने के समय की परिस्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए।” —पृष्ठ 953

“अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिव्यूनलो में सुसंस्थापित नियम है कि किसी सन्धि की विवादास्पद धारा की व्याख्या करते समय वे अपने मामले सन्धि के होने से पहले की वार्ताओं का रिकार्ड, तत्सम्बन्धी समितियों की बैठकों की वातचीत तथा सन्धि के अन्तिम प्रारूप तक पहुँचने के पहले के प्रारूप आदि को रख लेते हैं तथा उनका अध्ययन-विश्लेषण करते हैं।”

—पृष्ठ 957

“सन्धि होने के पूर्व उससे सम्बन्धित जितनी वातचीत हुई है, जितना भी विचार-विमर्श हुआ है तथा जितना भी प्रचार हुआ है, उस सब का रिकार्ड इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण साक्ष्य है।” —पृष्ठ 958

प्रदेश (भू क्षेत्र) के स्वत्व-त्याग से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुच्छेद भी इसी ग्रंथ में सुलभ है :

“स्वत्व-त्याग का लक्ष्य है किसी ऐसे प्रदेश पर प्रभुत्व पाना जो अब तक किसी अन्य राज्य की सीमा में था। जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का

सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र व किसी प्रदेश व स्वत्वत्याग का अधिकार है, और यदि वह चाहे तो उसे दूसरे राज्य में पूर्णरूपण विलय हो जाने का भी अधिकार है ।”

—पृष्ठ 548

स्वत्व त्याग को प्रभावोत्पादक बनाने का एक ही रूप है कि अपरावर्त राज्य एवं अभिग्राही राज्य व बीच एक संधि हो जिसमें यह समझौता लिखित हो । यह संधि गतिपूर्ण संधि का पत्र भी हो सकती है और युद्ध का भी तथा स्वत्व त्याग क्षतिपूर्ति व बदल में भी हो सकती है और बिना क्षतिपूर्ति व भी ।

—पृष्ठ 548

वर्तमान प्रसंग में भारतीय रियासतों के स्वत्व त्याग की क्षतिपूर्ति प्रिंसीपलों के रूप में की गई । क्या एक सरकार को जितना एक सुनिश्चित क्षतिपूर्ति की गारंटी देकर दूसरी सरकार को प्रवेश के स्वत्व-त्याग को प्राप्त किया है वह कहने का अधिकार है कि अब वह अपने वचन का पालन करना नहीं चाहती ?

संविधान की धारा 291 जिस पर पिछले अध्याय में विचार किया गया है, प्रिंसीपल प्राप्त करने के शासका के अधिकार का पूर्ववर्ती मानता है । दूसरे शब्दों में प्रिंसीपल न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से ही सगत है अनितु उह सांविधानिक गारंटी भी प्राप्त है । इसी प्रकार, शासका के व्यक्तिगत अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को भी संविधान की धारा 362 में मान्यता दी गई है तथा संविधान अनुबंधों या प्रसविदाओं में उनकी गारंटी की गई है इसलिए बिना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किन्हीं उनको भी समाप्त नहीं किया जा सकता ।

यदि भारत सरकार शासकों को दिये गए अपने वचन को भंग करता है और भारतीय साम्राज्य इस अवस्था को रोकने में असमर्थ सिद्ध होते हैं तो दस बातें में तो कोई शक है ही नहीं कि भारत सरकार का यह प्रविण भंग करता सांविधानिक अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में तो अनुचित एवं अव्यापूण है ही ।

संविधान की धारा 51 में उल्लिखित राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांतों में एक यह है 'सुव्यवस्थित सोचा के साथ व्यवहार करते हुए राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं की गई संधि की शर्तों का सम्मान करना ।' प्रिंसीपल समाप्त करने का प्रस्ताव देने वाला को शायद यह धारा सूझ गई है ।

ध्यान देने की बात यह है कि लोकतन्त्र भारत का 47 प्रतिशत क्षेत्रफल भारतीय रियासतों की देन है। साथ ही यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि कुछ रियासतों—कश्मीर, कच्छ, त्रिपुरा—की सीमा भारत के सीमान्त काम करती है। कश्मीर एवं कच्छ के रण के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ चल रहे विवाद पर भारत के पक्ष में केवल यही तर्क है कि इन दोनों रियासतों के शासकों ने सविलयन प्रालेख पर हस्ताक्षर करके भारत में अपनी रियासतों का सविलयन स्वीकार किया है और कच्छ के शासक ने सविलयन अनुबन्ध पर भी हस्ताक्षर किये हैं। एक ओर तो भारत की क्षेत्रीय अखण्डता केवल सविलयन प्रालेखों एवं अनुबन्धों या प्रसवदाओं पर निर्भर करती है और भारत सरकार उनका इस दृष्टि से सम्पूर्ण लाभ उठाती है; दूसरी ओर उन्हीं अनुबन्धों या प्रसंविदाओं को एकतरफा खत्म करना चाहती है। इस प्रकार के सन्धि-उल्लंघन से सीमा-पार ताक में लगे हमारे शत्रुओं को हमारे विरुद्ध प्रचार-सामग्री मिलती है और वे आज की विपन्न परिस्थिति में हमारे लिए अनेक नयी समस्याएँ खड़ी कर सकते हैं।

नैतिक पक्ष

यद्यपि, भारतीय रियासतों और उनके शासकों के विषय में, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गये मन्त्रि—मंडलीय गिफ्ट मंडल के 12 मई 1946 के घोषित ज्ञापन से लेकर 3 जुलाई 1968 को केन्द्रीय मन्त्रिमंडल की आन्तरिक मामलों की समिति के निर्णय तक का इतिहास निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार नरेशों की शांति प्रियता का अनुचित लाभ उठाना चाहती है। फिर भी एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है—क्या भारत सरकार का यह पग केवल कानून की दृष्टि से ही अनुचित है या इसका कोई नैतिक मूल्य भी है ?

वास्तव में किसी भी कानून का व्यय समाज का नैतिक स्तर बनाये रखना ही होता है—समाज का कोई अंग (व्यक्ति या समूह) किसी हमारे अंग के अधिकारों का हनन न कर सके। समाज कुछ विशेष नियमों का पालन करता हुआ एक अनुशासन में चलता रहे

हमारी सविधान सभा न भी नरचा व प्रिवा एम एव विन्यास अधिकार का उनका अधिकार माना है इसीलिए उसने धारा 291, 362 व 363 को संवधानिक रूप देकर उन अधिकारों को सुरक्षित किया है।

सरकार भी समाज का एक अंग हो होती है सविधान में केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकारों पर यह अंकुश लगाया गया है कि वे 'नामको' को उन अधिकारों से वंचित न कर सकें।

कानून की व्यवस्था तो उन लोग व निय होती है जो नतिकता का मूल्य नहीं जानते। हमारी संस्कृति में वचन देकर उसका पालन करना नतिकता का अभिन्न अंग है। इस विषय में हम अपने देश के साधारण से साधारण एवं अधिक्षित 'यत्तियो तक' में इस प्रकार की वार्ताएँ नित्य सुनते हैं —

'भय्या' जवान से तो बेटा बेटा पराये हुए जात हैं मैं जवान दई है तो मैं अपने घर में नाहि हारंगे।

यह है आज हमारे जीवन दर्शन का हमारी संस्कृति का।

इसी निये हमारी सविधान सभा भारतीय सविधान का प्राप्ति तयार करत समय इस नतिकता में अनुप्राणित थी जिसका सभा के मनीष सदस्या ने अपने वक्तव्यों में स्पष्ट भी किया है —

स्वाधीनता मिलने के समय जो व्यक्ति सरकारी सेवा में पहले से ही थे उन सरकारी कर्मचारियों को जायदासन देने के लिए सविधान सभा के सभी सदस्यों ने एक एक करके छोड़े हाकर इस बात पर अपनी सहमति प्रकट की कि 'हमारे नेताओं द्वारा दी गई गारण्टियों को राष्ट्र हर कीमत पर पूरा करने।' (देखिए सविधान सभा की बहस 10 अक्टूबर 1949 भाग 10 सत्रा 3, पृष्ठ 38)

डॉक्टर पी० एम० देशमुख का तो भारतीय संस्कृति और उनकी परम्पराओं पर इतना अगाध विश्वास था कि उन्होंने सविधान में किसी प्रकार की गारंटी को लिखना ही यथ समर्थत हुए कहा —

यदि गारण्टी है यदि हमने वचन दिया है, तो हमारा वह वचन ही न केवल पौर-अधिसेवा एवं अन्य प्रतिश्रुत सेवाओं के लिए अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए पर्याप्त है। यदि हम अपने वचन का भूल्य नहीं जानते तब उसे सविधान की धारा के रूप में सिद्धन से न राष्ट्र को कोई लाभ है और न पौर अधिसेवा को।' (वही पृष्ठ 40)

भारतीय परम्परा में दिये गए वचनों का कितना बड़ा नैतिक मूल्य है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है ?

इसी विषय पर उसी दिन 10 अक्टूबर 1949 को सविधान सभा में श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद ने कहा, "उस राष्ट्र का जो प्राणमूलक सिद्धान्तों को भूल चुका है, जो अपने दिये वचन को पूरा नहीं करता, राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। मुझे यह नहीं मालूम कि भारत की भावी ससद में किस प्रकार के लोग आएंगे। किसी अतिवाद के जोश में या किसी पराकाष्ठावादी विचार धारा की वेदी पर, वे इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर देना चाहें जिन्हें कि हमने इस सविधान की धाराओं में बाँधा है हमारे नेताओं ने कुछ वायदे किए हैं। हम उनका समर्थन करते हैं। हम प्रभुत्व-सम्पन्न हैं, भावी ससद नहीं। कार्याग, न्यायाग अथवा ससद के विवेक पर हम अकुश लगा सकते हैं। यही वह उद्देश्य है जिसके लिए हम सविधान का प्रारूप तैयार कर रहे हैं।

"सदन को सर्वसम्मति से इस धारा (प्रतिश्रुत अधिकारियों की सेवा-विषयक विशिष्ट शर्तों की गारण्टी) का समर्थन करना चाहिए जिससे विदेशों में पता लगे कि हम अपने वचन का पालन करते हैं। यह तो केवल पहला कदम है — न मालूम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मामले में हमें कितने वायदे करने पड़ें। हमारा एक गलत कदम हमें विनाश के कगार पर पहुँचा देगा।"

—वही, पृष्ठ 45

कितने सुन्दर ढंग से स्पष्ट किया है कि दिये गए वचनों का पालन करना किमी भी राष्ट्र का मूल सिद्धांत तो होना ही चाहिए किन्तु राजनैतिक दृष्टि-कोण में भी उसका कितना महत्व है !

सविधान सभा और ससद के अधिकारों में क्या अन्तर है ? और सविधान का उद्देश्य क्या है ? यानी केवल सविधान सभा ही सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न थी, ससद प्रभुत्व-सम्पन्न नहीं है। सविधान सभा को अधिकार था कि वह भावी समद पर जो चाहे सो अकुश लगा सके। क्योंकि समद को शक्ति या अधिकार देने वाला तो सविधान सभा द्वारा बनाया गया सविधान ही है।

प्रतिश्रुत सेवाओं की अतीत में जो गारण्टियाँ दी गई थी, उनके सम्बन्ध में उसी दिन मरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा

"क्या आपने उस इतिहास को पढ़ा है ? या स्वयं इतिहास बनाना शुरू करने के बाद आप उस इतिहास की परवाह नहीं करते। यदि आप का

॥ वीर वर दें जिनमे हमारी जिम्मेदारी का उल्लेख हो। विश्व का नतिक भाग स्थापन करने की महत्वाकांक्षा रखने वाल हम सागा की अपने विषय में यह नहीं कहलवाना चाहिए कि हमें कीमत तो हर चीज की पता है किन्तु मूल्य किसी का नहीं पता।”

— भारतीय रियासतों का एकीकरण की कहानी पृष्ठ 467

इसमें सन्देह नहीं भारतीय नरेशों के इन त्यागों का राष्ट्र सदैव ऋणी रहूँगा। यदि संविधान की धारा 363 या अन्य धाराएँ नरेशों का पक्ष निश्चल भी बना दें तब भी राष्ट्र का नेता/रा द्वारा नरेशों को दिये गये वचनों एवं आश्वासनों को पूरा करना नतिक रूप से तो हमारा कर्तव्य है ही अतः राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है—हमें सत्कार की यह बात देना है, हम वस्तु की कीमत पर ध्यान न देकर उसके मूल्य का सम्मान करते हैं।

रियासतों के भारत में संविधान के समय नरेशों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने सुचाया था कि संविधान अनुबंधों को समुक्त राष्ट्रसंघ में रजिस्टर करा लिया जाय ताकि कालांतर में भारत इनका उत्तरदायित्व न कर सके। उत्तर में सरदार पटेल ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा था कि गोरी चमड़ी (अंग्रेजों) के गानों पर तो उन्होंने दो सौ वर्ष तक विश्वास किया कि तु अपनी चमड़ी (भारतीयों) के गानों पर उन्हें शुरू में ही अविश्वास होने लगा। नरेशों ने सरदार की बात मान ली और समुक्त राष्ट्र संघ में अनुबंधों के रजिस्टर कराने का विचार त्याग दिया।

नरेशों की आज्ञा निमूल्य नहीं थी, किन्तु सरदार का विश्वास सही नहीं रहा—गोरी चमड़ी जाने विदेशियों ने तो नरेशों के साथ अपने वचनों का पालन अतः समय तक करके नतिकता की रक्षा की। किन्तु काली चमड़ी वाले अपने ही भाई व धुं ध्वनिगत राग हृदय की भावना से प्रेरित केवल 20 वर्ष बाद ही नतिकता का ठुकरा कर विश्वासघात करने पर तुल रह गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काली गोरी चमड़ी की इस तुलना का प्रभाव केवल भारतवासियों के विरुद्ध ही नहीं, समूचे अफ्रीका व एशिया, दाना महाद्वीपों के निवासियों के विरुद्ध पड़ेगा।

17 अक्टूबर 1949 के दिन संविधान को अंतिम रूप दिए जाने के बाद

मारे वयोवृद्ध नेता आचार्य जे० बी० कृपलानी ने सविधान सभा में अपने
 इंगार प्रगट किये जो सदैव स्मरण रखने योग्य हैं :—

“मैं चाहता हूँ कि सदन इस बात का ध्यान रखे कि हमने जो कुछ
 यहाँ प्रतिपादित किया है, वे केवल कानूनी, साविधानिक तथा औप-
 चारिक सिद्धांत ही नहीं हैं बल्कि नैतिक सिद्धान्त हैं और जीवन नैतिक
 सिद्धान्तों के बल पर आगे बढ़ता है। जीवन में नैतिक सिद्धान्त अनिवार्य
 हैं चाहे वह जीवन व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो, वाणिज्यिक हो, राज-
 नीतिक हो अथवा प्रशासक का हो। उनको तो पूर्णरूपेण जीवन में
 घटाना पड़ता है। यदि हम सविधान की सफलता चाहते हैं तो हमें इन
 बातों को याद रखना होगा।”

सविधान सभा की वृहत्, भाग 10, सख्या 10, पृष्ठ 454

हमारे राष्ट्रीय नेता के इन शब्दों में केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि
 विश्व की सभी सरकारों एवं सम्पूर्ण मानव जाति के लिए एक संदेश है —

कोई भी समाज बिना नैतिक सिद्धान्तों के स्वस्थ नहीं रह सकता।
 नैतिकता का संचार तो समाजरूपी शरीर के अंग-अंग में रक्त की भाँति होते
 रहना चाहिये। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में रक्त का संचालन रुक
 जाने से वह अंग कार्यशील नहीं रहता। इसी प्रकार समाज के जिस भाग में
 नैतिक सिद्धान्तों की अवहेलना की जायेगी, उसी भाग की व्यवस्था शिथिल
 पड़ जायेगी।

राज्य व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो ? उसमें सरकार एवं कानून की
 आवश्यकता नैतिक सिद्धांतों को बनाये रखने के लिए ही होती है।

समाज रूढ़ी शरीर में शासक वर्ग मस्तिष्क सरकार हृदय एवं कानून
 रक्त वाहिनी नाडियाँ हैं। हृदय का कार्य तो दूषित रक्त को शुद्ध करके उसे
 शरीर में प्रवाहित करना है। यदि शरीर के राजा मस्तिष्क के किसी कार्य
 के कारण, हृदय से ही दूषित रक्त प्रवाहित होने लगे तो शरीर का क्या
 होगा ? एवं स्वयं मस्तिष्क की क्या दशा बनेगी ?

सविधान सभा, जिसके प्रति राष्ट्र की सम्पूर्ण जनता श्रद्धावान थी, जो
 सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न थी, जिसने अतीत एवं वर्तमान के आधार पर देश के
 उत्थान के लिए सविधान का प्रारूप तैयार किया था। उस प्रारूप में
 संसद की सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। उसी सभा के प्रमुख सदस्यों के

धन्य है। स विधान की आत्मा प्रतिबिम्बित हो रही है—स विधान द्वारा दो गर्द गारटिया का पूरा करा—राष्ट्रीय नवाग्रा द्वारा न्य गय आस्वागता एव पपना का पानन करा उनका विपरीत जाना ननिब मिट्टाना का गता घोटना एव गता का दुग्धयाग है आ दग व समाज क तित हानिकारक हाता ।

नरेगा न प्रिवातमो एव रिगपाधिकारा का समाप्न वगन का विचार हा, ननिब टिप्पि म एव वि वामपात है हमारो सस्टुति एव स विधान की आत्मा क बिम्ब है । दगन हमारो राष्ट्रीय गौरव का ता ठेम पदुचगी ही उन स्वर्गीय नवाग्रा का आत्मा का भा दुग्ध हाता जि हान इन माल नरगा का मोनि मोनि क आ वामन लिए थ ।

हमारी परम्पराएँ

प्राण और वचन

महाराजा दशरथ ने अपना प्रिय रानी ककई को दा वरदान देने का वचन दिया । ककयी ने एक म भरत को राज्य और दूसरे म राम को बनवास मागा तो महाराज दशरथ प्रिय पुत्र राम से 14 वर्षों क विवाह की कल्पना मात्र में हा कोप उठे उ होने कोष म भरकर ककयी को बहुत बुरा मला तक कह डाला । तब ककयी ने यथ्य करते हुये कहा था ता महाराज आप अपने वचना से फिर जाग्य ।

इसी "यथ्य क उत्तर म दशरथ जी ने अपने वृन् की रीति बतलाई थी —

‘रघुकुल रीति सदा धति आई । प्राण जाहुँ यह वचनु न जाई ॥

दशरथ अपने वचना से नहीं फिरे और उ हाने राम के वियोग मे प्राण त्याग दिय । कि तु राम ने केवल अपने पिता क वचनों का ही पालन नहीं किया बल्कि इस परम्परा को अपने जीवन एव व्यवहार मे इस सीमा तक डाला था कि उ हाने राजनीति म भी उसको सबसे अधिक महत्व दिया ।

जब उन्होंने विभीषण को लका का राजा बना देने का वचन दिया तो जामवन्त ने शका करते हुए राम से प्रश्न किया, “महाराज! यदि किसी कारण वश रावण भी आपकी शरण में आ गया तो आपके इन वचनों का क्या होगा ?”

राम ने बड़े सहज स्वभाव से उत्तर दिया “लका का राजा तो विभीषण ही होगा। रावण को मैं अयोध्या का राज दे दूँगा।”

“और आप ?”

“मैं अपना सारा जीवन इसी तरह जगलो में व्यतीत कर दूँगा।”

यह थी वचनों को पालन करने की हमारी परिपाटी और भावना।

सबसे अधिक मार्मिक स्थल लक्ष्मण शक्ति के समय का है—लक्ष्मण के प्राण वचन जाने की आशा धूमिल हो चली है, उस समय राम करुण विलाप करते हुए कहते हैं :—

“हे लक्ष्मण ! सीता रावण की कैद में है, अयोध्या में भरत व माताएं हम लोगों के वियोग में दुखी हैं, अयोध्या वासी भी अपने को अनाथ समझ रहे हैं। इस घोर विपत्ति में भी तू मुझे अकेला छोड़ कर जा रहा है। किंतु इन सब दुखों : से अधिक दुख तो मुझे इस बात का है— हमने विभीषण को लका का राजा बना देने का वचन दिया है, वह तेरे बिना पूरा हो सकेगा, इसमें मुझे सन्देह है।”

लक्ष्मण जैसे प्रिय भाई की मृत्यु के गाल में जाते हुए देखकर भी राम को दिए हुए वचनों का कितना ध्यान है ? उन्हें पूरा करने की कितनी लगन है ? उन्हें भाई की मृत्यु से भी अधिक वचन पूरा न हो पाने का दुख है।

राम के इस चरित्र में हमारी सत्कृति हमारी परम्पराएँ, हमारे पूर्वजों के चरित्र एवं उनके वचन पालन की झलक है। हमारी सामाजिक मर्यादा का दिग्दर्शन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए तो बापू ने भारत में राम राज्य लाने की कल्पना की थी।

इसी प्रकार महाभारत काल में राजनीतिज्ञों में शिरोमणि भगवान् कृष्ण के चरित्र में भी हम यही बात पाते हैं—उनका राजनैतिक जीवन सार्वजनिक हितों से भरा हुआ था। यद्यपि उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर कूटनीति को भी अपनाया था किन्तु दिये गए वचनों की पावन परम्परा को कभी भंग नहीं होने दिया। अपने बड़े भाई बलराम व कौरवों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह युद्ध में पाण्डवों को केवल अपनी राय देगे, कौरवों के वश शस्त्र नहीं उठायेगे।

युद्ध में ऐसे अनवरत अस्तर आय, जब श्रीकृष्ण के लिए कौरवों का विरुद्ध शस्त्र ग्रहण करना अनिवार्य सा ही था कि तु उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। यहाँ तक कि उनका सोलह वर्षीय भाई अश्विमेधु को सात महारथियों से निहत्था करने योग्य से मार डाला, फिर भी वह शांत ही रहे।

एक बार अवश्य ही भीष्म पितामह द्वारा पाण्डवों की सेना का बुरी तरह हनन किये जाने पर उन्होंने भी मरकर रथ का पहिया उठा लिया। भीष्म पितामह, श्रीकृष्ण की इस सामयिक से मनी भाँति परिचित थे कि वह रथ के पहिये का ही चक्र के रूप में प्रयोग करके कौरवों की सेना का बहुत सहारा कर सकते थे। पितामह ने दौड़ कर कृष्ण को उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाई और कृष्ण ने रथ का पहिया भूमि पर फँस लिया।

इस घटना का द्वारा श्री कृष्ण ने एक सदेश दिया है—युद्ध जैसा स्थल पर भी यदि किसी जादू में आकर मनुष्य अपने दिये हुए वचन का भंग करने के लिए तत्पर हो उठे तो भी उन वचनों की याद चाहे शत्रु द्वारा ही क्या न दिलाई जाए, उसे अपना वचन भंग नहीं करना चाहिए।

वचन निभाने की बात हमारे देश की केवल पौराणिक गाथायें ही नहीं हैं बल्कि ऐतिहासिक घटनाएँ भी हैं। सिकंदर के आक्रमण से लेकर वर्तमान काल तक का हमारा इतिहास ऐसी अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है—जिन हमने बड़ी बड़ी भूलिया उठाकर भी दिए गए वचनों का पालन किया है।

सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप की देश भक्ति और धर्म में प्रभावित होकर एक शाही फरमान निकाला था— 'महाराणा प्रताप की सेना युद्ध में एक क्षण के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से हटती, उस क्षेत्र पर शाही सेना फिर दूसरी बार आक्रमण नहीं करेगी।'।

सम्राट ने इस वचन का पूरी तरह पालन किया। भले ही महाराणा प्रताप अपने जीवन में मेवाड़ विजय न कर सके किंतु जितने क्षेत्र पर उन्होंने अधिकार किया था वह उनका व उनके वंशजों का स्वतंत्र राज्य समझा गया।

कच्छ के रत्न के विषय में 'कच्छ ट्रिब्यूनल' के फैसले के अनुसार पाकिस्तान का जब भूमि देने का प्रश्न उठा तो विरोधी दलों ने उसका डटकर विरोध किया। इस विरोध का उत्तर देते हुए हमारे उपप्रधान मंत्री मनमोहन शर्मा मुरारजी देसाई ने भी यही कहा था —

“रघुकुल रीति सदा चल आई।

प्राण जाहूँ बर वचन न जाई।”

हमने 'ट्रूवुनल' का फैपला मानने का वचन दिया है, इसलिए हमें उसके अनुसार काम करना ही चाहिए। कांग्रेस दल के सदस्यों ने हर्षध्वनि करके इसका समर्थन किया।

विभाजन के समय हमारा देश विकट आर्थिक संकट से ग्रस्त था, शरणार्थियों की समस्या भयानक रूप से मुँह वाये सामने खड़ी थी। किन्तु विभाजन के समझौते के अनुसार हमें पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना था। भारतीय नेता इस रुपये की देनदारी को टालना चाहते थे। किन्तु महात्मा गान्धी ने यह रुपया पाकिस्तान को दिलवाया। उनका कहना था, "शत्रु को भी दिए गए वचनों को भंग करना कभी भी और किसी भी दशा में उचित नहीं है।"

कैसी विडम्बना है ? शत्रु को तो भूमि और रुपया देने के लिए हम दिए गए वचनों का पालन करना अपना कर्तव्य और सांस्कृतिक परम्परा मानते हैं। किन्तु जिन नरेशों ने अपने राज्यों का पाँच लाख वर्ग मील का क्षेत्र सहज ही में राष्ट्र को समर्पित कर दिया, उन्हें दिए गए वचनों की हम अवहेलना करना चाहते हैं ?

विश्वास

प्राण देकर भी वचनों का पालन करना तो हमारी सांस्कृतिक परम्परा है ही। किन्तु एक पक्षीय विश्वास को पूरा करना भी हमारे चरित्र की एक विशेषता रही है।

विभीषण राम की शरण में इस विश्वास को लेकर आया था कि राम उसे अपना संरक्षण अवश्य प्रदान करेंगे। यह विभीषण का राम के प्रति एक पक्षीय विश्वास ही तो था। केवल वचन देकर उसे निभाने की नीति में तो राम उसे अपनी शरण में लेने के लिए बाध्य नहीं थे। किन्तु हमारे यहाँ शरणागत की रक्षा करना भी वचन—पालन के समान ही नैतिक एवं पवित्र कर्तव्य माना गया है। इसीलिए श्री राम ने, यह जानते हुए भी कि विभीषण उनके शत्रु रावण का छोटा भाई था, न केवल सस्नेह उमंगों अपना संरक्षण प्रदान किया अपितु उसे लका का राजा भी घोषित कर दिया।

इंद्र ने माचक के रूप में कण से उनके कवच और कुंडल मागे। इन दो वस्तुओं के कारण ही कण अजेय था। किंतु इंद्र भी एक पक्षीय विश्वास लेकर कण के पास गए थे। कर्ण ने यह जानते हुए भी कि कवच व कुंडल दे देने से मेरी मृत्यु अवश्यम्भावी है वे दोनों वस्तुएँ इंद्र को दे दी।

सत्यवाणी हरिश्चंद्र की कथा जिससे महात्मा गांधी अपने बचपन में ही बहुत प्रभावित हो चुके थे कौन नहीं जानता ?

चंद्र टर सूरज टर, टर जगत व्यवहार।

५ दंड हरिश्चंद्र को टर न सत्य विचार।।

राजस्थान का सा इतिहास ही बच्चों एवं प्रतिभाओं का इतिहास है। भागा और विश्वास का संकट रक्षा सूत्र का गाथाया स भरा पड़ा है। यदि किसी नारी ने किसी के पास राखी का एक डोरा भेज कर अपनी रक्षा की मांग कर ली तो राखी प्राप्त करने वाला उस नारी के भागा एवं विश्वास के कारण उसकी रक्षा के बचन में बंध गया। भले ही उसने अपने इस मुह बोली बहिन की सूरत भी न देखी हो उससे परिचित भी न हो किंतु उस ती बहिन की रक्षा में अपना तन मन, धन सब कुछ दांव पर लगा हा देना होता था।

भारत की इस परम्परा का केवल हिन्दुओं ने ही नहीं मुसलमानों ने भी निभाया। इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना रानी कणवती और हुमायूँ का है। रानी कणवती हुमायूँ के पिता बाबर के गुरु राणा सांगा की पत्नी थी। किंतु हुमायूँ ने रानी कणवती की राखी पाकर मुजरान के नवाब से सहाय्य की रक्षा की। इस प्रकार राखी के एक डोरे ने धार्मिक कट्टरता के पुरानी गठ्ठता के बंधन को तोड़ कर दा गुरुओं को भाई-बहिन बना दिया।

यदि रक्षा पूजन दिया जाये तो भारतीय रिवाजों के गविराज की घटना इन घटनाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय नेताओं ने समस्त भारतीय जनता की आर में एक भागा एवं विश्वास लेकर नरेगा में उनके राज्या एवं अधिकारों की मांगना का। भारतीय संसूति के उद्देश्य के संरक्षण नरेगा न स्वयं का गानवीर बन की परम्परा का रक्षण हुए इस मांग का स्वीकार करके अपना सब कुछ राष्ट्र को अर्पण कर दिया।

धा० वा० पी० मनन के द्वारा यह ज्ञात कि भारत ने स्वायत्त रियासतों के शासक शासक अनुबंध के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा कर चुके अर्थात्

उन्होंने तो अपनी रियासते एव शासन सत्ता भारत सरकार को सौंप दी । इस समय उनके पास मोल भाव करने की कोई ताकत नहीं बची है ।”

इतिहास की यह अपूर्व घटना है जब कि देने वाले ने [मांगने वाले पर विश्वास करके अपना सब कुछ उसके हाथों में दे दिया हो । किन्तु राष्ट्रीय नेताओं ने भी नरेशों के विश्वास को टूटने नहीं दिया, उन्होंने नरेशों से वात-चीत करके उनकी इच्छानुसार ही उनके प्रिन्सिपलों की घन राशि को निश्चित करके उनके विशेषाधिकारों को भी सुरक्षित रखा ।

श्री० वी० पी० मेनन ने आगे कहा है, “यदि ऋण दाता निर्बल हो जाये तो ऋणी को यह शोभा नहीं देता कि वह ऋण चुकाने से इन्कार कर दे ।”

राष्ट्र, नरेशों की राष्ट्रीय भावना एव उनके त्यागों का ऋणी है, अपने त्यागों के कारण ही तो वे आज इतने निर्बल हो गए हैं कि भारत सरकार उनके विरुद्ध अपनी मन मानी करने पर उतारू हो रही है ।

यदि सरकार प्रिन्सिपलों एव विशेषाधिकारों को समाप्त करने की अन्याय पूर्ण नीति में सफल हो गई तो इस से हमारे पुराणों की गौरव गाथाएँ एव वे ऐतिहासिक घटनाएँ, जिन पर हमें गर्व है, फीकी पड़ जायेगी ।

क्योंकि अपना आचरण ही यदि अपनी सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल न हो तो केवल पूर्वजों के सत्कार्यों पर गर्व करना भी कोई महत्व नहीं रखता ।

भूतपूर्व विधि मन्त्री श्री अशोक सेन ने उचित ही कहा है कि इस घटना का प्रभाव केवल वर्तमान पीढ़ी पर ही नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा । क्या हमारी भावी पीढ़ियाँ हमारे ऊपर उसी तरह गर्व कर सकेंगी, जिस तरह आज हम अपने पूर्वजों पर करते हैं ?

जब वे इतिहास में यह पढ़ेंगी की हमने अपने पूज्य नेताओं द्वारा दिये गये वचनों एव आश्वासनों को भग करके अन्याय पूर्ण कार्य किया था तो उनका मस्तक लज्जा से झुक जायेगा ।

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने कहा था, “यदि राणा सांगा और मेरे बीच में मेवाड़ की गद्दी पर और कोई राजा न हुआ होता तो आज मेवाड़ पराधीन न होता ।”

हमारी भावी पीढ़ियाँ यदि गांधी के आदर्शों पर चलने वाली हुई, उनमें नैतिक बल हुआ तो वे भी कहेगी, “भले ही हमारा देश नौ सौ वर्ष परतन्त्र

इंद्र ने माचक के हथ म वर्ण से उनका बचक और कु डल मागे । इन दो वस्तुओं के कारण हो कण अजय थ । किंतु इंद्र भी एक पत्नीय विरहास लेकर कण के पास गए थे । कण ने यह जानते हुए भी कि बचक व कु डल द दन से भरी मृत्यु अवश्यम्भावी है व दोनों वस्तुएं इंद्र को दे दी ।

मत्स्यवादी हरिश्चंद्र की कथा जिससे महात्मा गांधी अपने बचपन में ही बहुत प्रभावित हो चुके थे, कौन नहीं जानता ?

चंद्र टर मूरज टर, टर जगज 'यवहार ।

ये हउ हरिश्चंद्र को टर न सत्य विचार ॥

राजस्थान का ता इतिहास ही बचना एवं प्रतिभा का इतिहास है । माता और विरहास को लेकर रक्षा मूना की गायमा से भरा पहा है । यदि किसी नारी ने किसी के पास राखी का एक डोरा भेज कर अपना रंगा की योग कर ली ता राखी प्राप्त करने वाला उस नारी के माता एवं विरहास के कारण उसकी रक्षा के बचन में बंध गया । मने ही उसने अपनी इन मुह बोधी बहिन की मूरत भी न देखी हा । उससे परिचित भी न हा, किंतु उस तो बहिन की रक्षा में अपना तन मन धन सब कुछ दौव पर लगा हा दना हाता था ।

भारत की इस परम्परा का सबसे हिन्दुआ ने ही नगी मुसलमाना न भी निभाया । इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना रानी कणवती और हुमायूँ की है । रानी कणवती हुमायूँ के पिता बाबर के छत्र, राजा सता की पत्नी थी । किंतु हुमायूँ ने रानी कणवती की राखी पाकर गुजरात के नबाब से पनाह की रक्षा की । इस प्रकार राखी के एक डोरे ने धार्मिक कट्टरता व पुराना सत्रुता के बचन का तोड़ कर दो गज्रा की माई-बहिन बना दिया ।

यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय ता भारतीय रियासतों के गवियन की पत्नी एवं पत्नीमा से भी अधिक महत्वपूर्ण है ।

राष्ट्रीय नेताओं ने सम्पूर्ण भारतीय जनता का भार न एक आत्मा एक विरहास लेकर नरेगा स उनका राज्या एक अज्ञानता की याचना का । भारतीय मर्त्यता के उपायक व मरणा नरेगा न स्वयं के जानकार कण को परम्परा में रमन हुए हम यदि का स्वाकार करके अपना सब कुछ राज्य का भगत कर दिया ।

भा० पी० पी० मनन के हथ म 'यमा हि मरणा मे स्वीकार दिया वा हि राजा सत्रु अनुबध के अनुकर करना कर्माध्य पूरा कर कुछ अर्थात्

उन्होंने तो अपनी रियासते एवं शासन सत्ता भारत सरकार को सौंप दी । इस समय उनके पास मोल भाव करने की कोई ताकत नहीं बची है ।”

इतिहास की यह अपूर्व घटना है जब कि देने वाले ने [मागने वाले पर विश्वास करके अपना सब कुछ उसके हाथों में दे दिया हो । किन्तु राष्ट्रीय नेताओं ने भी नरेशों के विश्वास को टूटने नहीं दिया, उन्होंने नरेशों से बातचीत करके उनकी इच्छानुसार ही उनके प्रिवीपर्सों की घन राशि को निश्चित करके उनके विशेषाधिकारों को भी सुरक्षित रखा ।

श्री० वी० पी० मेनन ने आगे कहा है, “यदि ऋण दाता निर्बल हो जाये तो ऋणी को यह शोभा नहीं देता कि वह ऋण चुकाने से इन्कार कर दे ।”

राष्ट्र, नरेशों की राष्ट्रीय भावना एवं उनके त्यागों का ऋणी है, अपने त्यागों के कारण ही तो वे आज इतने निर्बल हो गए हैं कि भारत सरकार उनके विरुद्ध अपनी मन मानी करने पर उतारू हो रही है ।

यदि सरकार प्रिवी पर्सों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त करने की अन्याय पूर्ण नीति में सफल हो गई तो इस से हमारे पुराणों की गौरव गाथाएँ एवं वे ऐतिहासिक घटनाएँ, जिन पर हमें गर्व है, फीकी पड़ जायेगी ।

क्योंकि अपना आचरण ही यदि अपनी सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल न हो तो केवल पूर्वजों के सत्कार्यों पर गर्व करना भी कोई महत्व नहीं रखता ।

भूतपूर्व विधि मन्त्री श्री अशोक सेन ने उचित ही कहा है कि इस घटना का प्रभाव केवल वर्तमान पीढ़ी पर ही नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा । क्या हमारी भावी पीढ़ियाँ हमारे ऊपर उसी तरह गर्व कर सकेंगी, जिस तरह आज हम अपने पूर्वजों पर करते हैं ?

जब वे इतिहास में यह पढ़ेंगी की हमने अपने पूज्य नेताओं द्वारा दिये गये वचनों एवं आश्वासनों को भग करके अन्याय पूर्ण कार्य किया था तो उनका मस्तक लज्जा से झुक जायेगा ।

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने कहा था, “यदि राणा सांगा और मेरे बीच में मेवाड़ की गद्दी पर और कोई राजा न हुआ होता तो आज मेवाड़ पराधीन न होता ।”

हमारी भावी पीढ़ियाँ यदि गाँधी के आदर्शों पर चलने वाली हुईं, उनमें नैतिक बल हुआ तो वे भी कहेगी, “भले ही हमारा देश नौ सौ वर्ष परतन्त्र

रहा था किन्तु हमारी नतिकता का स्तर कभी नहीं गिरने पाया। यदि पड़ित नेहरू और सरदार पटेल की पीढ़ी व हमारी पीढ़ी के बीच में, पड़ित नेहरू के बाद वाली पीढ़ी न हुई होती, तो आज हमारे बचन पर किसी का सन्देह करने का साहस न होता।"

नरेशा व साथ किये गये समझौते को भंग करना पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है।

राजनैतिक

हमारी सोभाएँ

क्षत्रपत के विचार से हैनराबाद व कश्मीर सब से बड़ी रियासतें थी। अग्रे 552 रियासतों व भारतीय मध्य व ब्रितानी कारण व उपरान्त में इन दोनों रियासतों ने अपना अस्तित्व स्वयं-त ही बनाये रखा। हैनराबाद भारतीय मध्य व बीच में थी, इस लिए पाकिस्तान वहाँ अपने एजन्टा व द्वारा भारत व विरुद्ध चुपचा चुपचा कार्य कर रहा था। किन्तु जम्मू व कश्मीर की स्थिति कुछ दूसरी थी, इसका कारण और रूस, चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान व भारत की सीमाएँ इस परे हुए थीं। पाकिस्तान का रियासत की स्वतन्त्रता का अनुचित लाभ उठाने का अवसर हाथ आ गया उतने बखर बचावियों की उम्मीद कर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया।

हिज़ हार्दम महाराजा हरीमि ने अपनी जनता को पाकिस्तान व तानाशाही शासन से बचाने के लिए अपनी रियासत जम्मू व कश्मीर का भारत मध्य व अलग कर दिया। जिनसे 26 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार और महाराजा कश्मीर के बीच में एक समझौता हुआ जिसका एक प्रमुख जम्मू व कश्मीर राज्य एक प्रान्त के रूप में भारत में विभक्त हो गया। भारत की सेवा का करने इस प्रान्त की रक्षा के लिए सर्वप्रधानी मन्त्रालय भारत संघ हुआ और सर्वप्रधान की सेवा पीछे नष्ट दी गई।

इसी बीच अंग्रेजी कूटनीति के हम फिर शिकार हो गए। भारत के तत्कालीन सर्वोच्च जनरल लार्ड माउण्ट बैटन ने प्रयत्न करके दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा करा दी। जिस देश की सेनाएं जहाँ तक पहुँच सकी थी, वही युद्ध विराम की सीमा निर्धारित कर दी गई।

इस प्रकार हमारे इस सुन्दर प्रदेश के एक तिहाई भाग पर जिसमें गिलगित्त का महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है, पाकिस्तान ने अपना अनैतिक रूप से अधिकार जमा रखा है। किन्तु कश्मीर के शासक महाराजा हरीसिंह ने अपना राज्य भारत सरकार को समर्पित किया है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जम्मू कश्मीर का जो भाग हमारे पास है, वह तो हमारा है ही, किन्तु पाक-अधिकृत एक तिहाई भाग पर भी हमारा नैतिक व कानूनी अधिकार है।

भारतीय नरेशों के साथ हुए अनुबन्ध एवं प्रसविदाये समाप्त किए जाने पर जम्मू कश्मीर नरेश के साथ हुए अनुबन्ध एवं प्रसविदाये भी समाप्त हो जायेगी तब संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे विवाद पर हमारा पक्ष भी निर्बल पड़ जायेगा। यह समझ में नहीं आता कि सरकार नरेशों के 'प्रिवी पर्सों' एवं विशेषाधिकारों को समाप्त करने के अनैतिक कार्य करने की बजाय जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष श्रेणी प्रदान करने वाली सविधान की धारा 370 को समाप्त क्यों नहीं करती ?

सिक्किम के शासक महाराजा चोग्याल ने जब भारत सरकार से भारत और सिक्किम के बीच हुई सन्धि पर नये सिरे से पुनः विचार करने का आग्रह किया तो भारत सरकार ने उसे टाल दिया। निस्सन्देह सन्धि की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए सरकार का यह कदम उचित ही था किन्तु भारतीय नरेशों के साथ वचन भंग किये जाने का वहाँ के शासक एवं जनता पर बुरा प्रभाव पड़ना अनिवार्य ही है, उन्हें अपने साथ हुई सन्धि पर भी शका होने लगेगी जो हमारे लिए किसी प्रकार भी हितकर नहीं है।

कच्छ और त्रिपुरा की सीमान्त रियासतों के विषय में पहले ही लिखा जा चुका है। लका से भी कच्छा तिवू, जो हमारी एक भूत पूर्व रियासत का ही एक भाग है, के सम्बन्ध में विवाद ही है। इन सभी विवाद ग्रस्त क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता, हमारे पक्ष में, इन क्षेत्रों के नरेशों के साथ हुए सविलियन प्रालेखों, अनुबन्धों एवं प्रसविदायों पर ही निर्भर करती है।

इसके अतिरिक्त जिन विदेशियों की पूँजी विनियोग में लगी हुई है, भारत सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है—वे अपना लाभ अपने देश भेज सकते हैं तथा जब उनकी इच्छा हो वे अपनी पूँजी वापस ले जा सकते हैं।

क्या उन्हें सरकार के आश्वासनों पर भरोसा रह जाएगा ? क्या बिदगी सरकारें अपने कणों को चुकाए जाने के लिए हमारा विश्वास करेंगी ?

इसी तरह उन सरकारी बॉण्डों के भुगतान पर से भी जनता का विश्वास उठ जाएगा, जिस पर सरकार ने भविष्य में रुपया देना या दते रहने का वचन दे रखा है । क्या मान्य इस सरकार के बॉण्डों का भुगतान देने के लिए दूसरी सरकार मना कर दे ? क्या इसका ठरारनामिका वतमान सरकार पर नहीं होगा, जो नरेशों के प्रिवीपस बना करके इस अन्यायता का माया खोलने जा रही है ?

नरेशों की लोकप्रियता

नरेश और चुनाव

चुनाव लोकतन्त्र का मूलाधार होते हैं और किसी भी विजयी प्रत्याशी की लोक-प्रियता का परिचायक कहे जा सकते हैं। किन्तु उल्टे-सीधे हथकण्डो और 'स्टंटो' के बल पर सफलता पा लेने को ही लोक-प्रियता की सजा नहीं दी जा सकती। लोक-प्रियता तो वह है, चुनाव 'स्टंटो' और भारी चुनाव प्रचारों के बिना ही प्रत्याशी स्वयं तो हजारों-लाखों मतों से विजयी हो ही जाये किन्तु जिस किसी दूसरे प्रत्याशी की ओर अपने समर्थन का संकेत भर कर दे, विजय श्री उसी के गले में माला पहिना दे।

एक समय था जब भारत में कांग्रेस के अतिरिक्त कोई दूसरा राजनैतिक दल नहीं था, उन दिनों गांधी और नेहरू की लोक-प्रियता के बल पर मत वटोर कर, सम्पूर्ण कांग्रेस दल की लोक प्रियता का ढिंढोरा पीटा जाता था। कुछ तो सकुचित मनोवृत्ति के लोग यहाँ तक दम्भ भरते पाये गये कि यदि कांग्रेस किसी बन्दर को भी खड़ा कर दे तो वह भी चुनाव में जीत जाएगा।

'भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसार ब्रिटिश भारतीय जनता को प्रान्तीय स्वराज्य का अधिकार दिये जाने पर भारत में सब से पहला चुनाव 1937 में हुआ था।

इस चुनाव में मत देने के दो तरीके व्यवहार में लाये गये थे — एक तो पढ़े लिखे लोग मत पत्र पर प्रत्याशी के नाम के आगे चिन्ह लगा कर मतदान पेट्टी में डाल देते थे। दूसरा मतदाता से पूछ कर चुनाव अफसर स्वयं मत पत्र पर उसके बतलाये प्रत्याशी के नाम के सम्मुख चिन्ह लगा देते थे। जब मत-

दाता से पूछा जाता था कि वह किस अपना मत देना चाहता है ? तो कांग्रेस प्रत्याशी व समर्थन करने वाला मे से अधिकांश क उत्तर थे - गांधी बाबा को जवाहरलाल नेहरू को भारत माता को, तिरये झंडे को । स्पष्ट है, मतदाता प्रत्याशा से या उसके नाम तक से परिचित नहीं था । कांग्रेस ने भी ब्रिटिश सरकार से यह सय कर लिया था—क्योंकि देश में यह पहला चुनाव है मत दाता, मतदान से परिचित नहीं है, इसलिए कोई भी सचेत जो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जाता हो सही माना जाये और मत खारिज न किया जाये । यद्यपि इस चुनाव में अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस की ही विजय हुई, 11 प्रांत में कांग्रेस मतिमंडल बना । और यह विजय केवल गांधी और जवाहरलाल की लोक प्रियता की ही विजय थी । फिर भी कांग्रेस को कई स्थानों पर उल्टे-सीध हथकड़ा और 'कूटा' का सहारा लेना पड़ा । उत्तर प्रदेश के एटा क्षत्र से लीडर पत्र व सम्पादक श्री० सी० बाई० बितामणि जो उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में गिना सदस्य (गिना मंत्री) रह चुके थे, जिन्हें अबागढ़ व राजा साहब सूपपाल सिंह (उत्तर प्रदेश का एक बंग बड़े जमींदार) का पूरा समर्थन प्राप्त था केवल एक हथकड़ी और स्ट । के कारण ही एक सामान्य कांग्रेसी प्रत्याशी से पराजित हो गये थे ।

स्वतंत्रता प्राप्ति और रियासतों के भारतीय मध्य में मजबूतियत हो जाने के बाद भारतीय नरेशों ने चुनाव क्षत्र में उत्तरदायित्व स्वीकार कर लोक प्रियता का एक दूसरा नमूना प्रस्तुत कर दिया । दूसरा नमूना यह कि वे नरेश न तो महारानी गांधी व श्री जवाहर लाल नेहरू की मानि नता हैं वे और न उन्होंने प्रत्येक रूप में कोई जन सेवा का ही कार्य किया था और राज्य व अपने छोटे ही चुके थे । इसलिए उनकी लोकप्रियता का अधिकांश श्रेय उनकी बगानुगत प्रतिष्ठा एवं सम्मान की ही है । आसक्ती है । व चुनाव में जिस प्राणियों के विरुद्ध छड़े हुये हजारों मानव मना न उन्होंने विजय प्राप्त की । उनकी विजय किसी राजनतिक दल व कारण नहीं थी बल्कि व जिस दल की आर म छड़े हुये उस दल को जनम गति मिली ।

मई 1962 के आम चुनाव में नरसिंह गड़ (मध्य प्रदेश) व महाराष्ट्र जो इस समय कांग्रेस दल से एम० पी० और केंद्रीय सरकार में शामिल हैं, एम० पी० व एम० एम० ए० (दोना ही स्थानों के लिए) के चुनाव के लिए छड़े हुए थे और दोनों ही स्थानों पर बंग बड़े बट्टमन न विजयी हुए । उन्होंने एम० एम० ए० के पक्ष से ग्याय पत्र दे दिया । मध्य प्रदेश के मुख्य

मन्त्री डाक्टर कैलाश नाथ काटजू जो अपने घर के क्षेत्र में ही इस चुनाव में पराजित हो चुके थे, उन्हें महाराजा नरसिंह गढ़ ने अपने स्थान जओरा क्षेत्र से पुनः खड़ा करके अपना समर्थन दिया। डाक्टर काटजू एक बार भी जओरा क्षेत्र में नहीं गये, किन्तु यह महाराजा साहब की ही लोकप्रियता थी कि उनके सकेत मात्र से ही वह चुन लिये गये।

पिछले आम चुनाव में गुजरात में, धांगध्रा नरेश जो लोक सभा की सदस्यता के लिये स्वतन्त्र दल की ओरसे खड़े हुए कांग्रेस द्वारा अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विरोध करने पर भी जनता ने अपने भूतपूर्व महाराजा के इस निर्णय का हृदय से स्वागत किया। महाराजा साहब के प्रभाव से चकित होकर कांग्रेस पत्र फूलछाव के सम्पादक ने उनसे साक्षात्कार प्राप्त करके प्रश्न किया, “भूतपूर्व देशी रियासतो की जनता अब भी इतनी पिछड़ी हुई और अन्ध-विश्वासी क्यों है, कि वह अपने राजाओ-महाराजाओ के प्रति ऐसी श्रद्धा रखती है ?

महाराजा साहब ने कहा, “मैं इस बात का उत्तर तब ही दूंगा, जबकि तुम यह वचन दो कि मेरे उत्तर को अपने पत्र में तदनुरूप प्रकाशित करोगे।”

सवाददाता ने उत्तर प्रकाशित करने का वचन दिया।

धांगध्रा नरेश ने कटाक्ष करते हुए कहा, “देशी रियासतो की जनता अपने राजा-महाराजाओ के द्वारा किए गए अत्याचारों की चक्की में सैकड़ों वर्ष तक पिसती रही, असुविधाओं को धैर्यपूर्वक सहन करती रही। उसके बाद रियासतों के भारत में सविलयन हो जाने पर वर्तमान शासन ने उसे स्वतन्त्रता दी, सुविधायें दी, प्यार दिया, किन्तु इन पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस द्वारा दिये गये प्यार, सुविधाओं व स्वतन्त्रता से यह भगा गई है, अतएव उस अन्याय व अत्याचार को याद करके वह हमारा स्वागत कर रही है।”

सवाददाता महोदय इस व्यगात्मक उत्तर और दृग्गामी सचाई का अनुभव करके दग रह गये, उन्होंने महाराजा साहब के इस उत्तर को अपने पत्र में प्रकाशित भी किया।

धांगध्रा नरेश चुनाव में लाखों मतों से विजयी हुये। उसके बाद एक उप चुनाव में महाराजा साहब ने भूतपूर्व सचिव श्री एच० एम० पटेल का कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध समर्थन किया, कांग्रेस की पूरी शक्ति लग जाने के बावजूद भी श्री पटेल 18000 मतों से चुनाव जीते।

टिहरी गढवाल के हिज हार्डनस भले ही कांग्रेस दल की ओर से लोक-समा के सन्मुख हैं किन्तु जनता में उनकी अपनी लोक-प्रियता है। बीवानेर के हिज हार्डनस महाराजा कर्णसिंह व विषय में कुमारी मणि बेन पटेल का राज्य-समा में दिया गया वक्तव्य उनकी लोक-प्रियता बताने के लिये ब्याप्यार्थ नहीं है। स्वातंत्र्य की राजमाता महारानी विजय राजे मिथिया व जयपुर की महारानी मायत्री देवी की लोकप्रियता से बीन परिवर्तित नहीं है ?

महाराजा छतरपुर को मैंने बहुत समीप से देखा है। महाराजा होने का उनमें कोई गव नहा, रहन सहन बहुत सादा तथा बातचीत का ढंग बड़ा मधुर व आकर्षक है। राजनीति से दूर रहते हुए भी हर एक से मिलते हैं उसके दुःख-दद की सहानुभूति पूषक सुनते हैं और यथा शक्ति सहायता करने की भी तत्पर रहते हैं। जनता के हृदय में उनका प्रति धृष्टा और सम्मान किसी भय के कारण नहीं बल्कि उनके गुणों के कारण है। बहुधा लोग को यह कहत सुना जाता है 'हमारे महाराजा तो सत है।'

इन राजाओं महाराजाओं व महारानियों की लोक-प्रियता भले ही महारानी गांधी और पंडित नेहरू के समान अग्नि-भारतीय-स्तर की न हो किन्तु अपने अपने क्षेत्र में ये लोकप्रियता के सुष हैं वहाँ उनके सामने किसी राजनैतिक दल के बड़े बड़े सिंगल तक टिक नहीं सकते।

नरेशों का प्रभाव

मान लो कि के मुस्लिम काल और दो ती वष के अथवा सामन में रह कर भी भारतीय नरेशों ने अपने नियमा-रीति-रिवाजों व परम्पराओं की निजान हुए भारतीय संस्कृति को अशुण बनाय रखा है। जगत् प्रभाव उनकी जनता पर भी भरपूर रहा है।—यही कारण है—अंगरेजियन जिनकी ब्रिटिश भारत में पनपा व पना, उनका यह सिद्धान्तों व करना प्रभाव न जमा सकी। यह भारतीय नरेशों की राष्ट्र का बहुत बड़ी दन है।

भय ही कुछ नरेशों में व्यक्तिगत दान रह हो किन्तु उनके सामन काल में जनता की महंगाई-मुश्किली, बेकारी और भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पडा। यदि आज भूतदुव दाना रा-दों की जनता से दुष्टा जाता है तो

अधिकांश लोग यही कहते पाये जाते हैं," अब से तो हम लोग अपने राजाओं के समय में अधिक सुखी थे। राजाओं ने रियासतें छोड़ कर अच्छा नहीं किया।"

फिर भी नरेशों ने अपनी दुर्बलताओं पर कभी पर्दा नहीं डाला। अच्छाईयों और गुणों के ढोल नहीं पिटवाये, प्रचार नहीं कराया।

इधर कांग्रेस के शासन में नारे तो भारतीयता के लगाये जा रहे हैं। किन्तु प्रसार अंग्रेजियत का हो रहा है। स्वयं कांग्रेसी नेताओं का लिबास भले ही खादी और भारतीयता का है, किन्तु रहन-सहन, आचार-विचार, यहाँ तक कि बहुत सो का तो खान पान भी विशुद्ध अंग्रेजी ढंग का हो गया है।

अब स्वतन्त्र भारत में अंग्रेजियत, अंग्रेजों के समय से कहीं अधिक फैल चुकी है, और फैलती जा रही है। भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है।

जहाँ तक व्यक्तिगत दोषों का प्रश्न है, जिन दोषों की नरेशों में केवल कल्पना मात्र ही की जा सकती थी, वे सारे दोष बहुत से नेताओं में भरपूर पाये जा रहे हैं। उनका जनता पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है—वह समझ रही है—यदि बीस वर्ष की सत्ता का मद्द इतना अधिक हो सकता है कि सत्तारूढ़ि व्यक्ति अपने दुर्गुणों को अपना अधिकार समझने लगे, तो जिनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी से सत्ता थी, यदि उन नरेशों में कुछ व्यक्तिगत दोष थे भी तो अन होनी बात क्या थी ?

सच तो यह है, नरेशों और जनता के बीच में एक मजबूत कड़ी है जो एक दूसरे से सम्बन्ध तो बनाये हुए हैं किन्तु न तो जनता ही उस कड़ी की भावना को समझ रही है और न नरेशों ने ही कभी इस ओर ध्यान दिया है। दोनों ही यह समझ रहे हैं—वे उसके भूतपूर्व नरेश हैं और वह उनकी भूतपूर्व प्रजा है। उन पुराने सम्बन्धों की जान तो निकल गई, केवल मुर्दा शेष रह गया है।

कांग्रेस भी यह समझ रही है कि वह प्रिवीपर्स और विरोधाधिकारों की समाप्ति के रूप में मुर्दों को दफना कर इस रही सही कड़ी को भी समाप्त कर सकती है।

इस में सन्देह भी नहीं, इस कड़ी का वाहरी रूप तो यही है, किन्तु इस मुर्दों में अभी प्राण शेष है, इसकी आत्मा अभी मरी नहीं केवल सोई हुई है। मुर्दों को दफना कर भी आत्मा नहीं दफनाई जा सकेगी।

सही रूप में हम बड़ी बड़ भारमा या हम का माबारमक रूप यह है— जनता का बचन बचिस ही नहीं, किसी भी राजनतिक दल पर भारता महा है, उते वर्तमान नेतामीरी स डर लग गया है। इसलिये वह अपने भूतपूर्व नरेशों से पय प्रशंसों को आता करती है। यह कारण है नरेश चुनाव में जिस प्रायागी का समर्थन करत हैं बहुधा वही विजयी हो जाता है।

पय प्रशंसों को ही दूसरे दालों में नेतृत्व कहत है। हम प्रकार नरेश जनता का नेतृत्व करत हुए भा नया मीरी का जामा नहीं पहिनत और जनता उन्हें अपना नेता समझत हुए भी, नेता नाम से नहीं मानती।



बापू

बापू और समाजवाद

जिस समाजवादी समाज के नाम पर हमारी सरकार, नैतिक सिद्धांतों के विपरीत, प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त करने का बहाना ले रही है, उसी के विषय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार भी यहाँ दे देना अप्रसंगिक न होगा।

बापू से एक बार प्रश्न किया गया—“कांग्रेस समाजवादी दल ने कांग्रेस के लिये जो कार्यक्रम पेश किया है, उसके बारे में आपकी सामान्य टीका क्या है ?”

बापू का उत्तर था —

“वह मानव स्वभाव में अविश्वास प्रगट करता है। उसकी सारी भूमिका ही गलत है।”

13 जुलाई मई 1947 के हरिजन में बापू ने—“समाजवादी कौन ?” नामक शीर्षक से एक लेख लिखा था। लेख काफी बड़ा है इस लिए इस की कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें ही यहाँ लिखी गई हैं.—

“समाजवाद एक सुन्दर शब्द है और जहाँ तक मुझे मान्य है, समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं।”

इसी बात को कुछ उदाहरण दे कर, अधिक स्पष्ट करके उन्होंने आगे लिखा है :—

“इस अवस्था तक पहुँचने के लिए हम एक दूसरे की तरफ देखते नहीं रह

सहा रूप में दण बड़ी की आत्मा या दण का भावात्मक रूप यह है— जनता को बचत कायेस ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल पर मरसा नहीं है, उसी वर्तमान नेतामीरी से दूर लग गया है। दमतिण वह अपने भूतपूर्व नरेणों से पय प्रगन को आगा करती है। यही कारण है नरेण चुनाव में त्रिग प्रयागी का गमयन करते हैं बहुतया वही विजयी हो जाता है।

पय प्रगन को ही दूसरे दानों में गैतृव कहते हैं। इस प्रकार नरेण जनता का ननुर्य करत हुए मा नचा गारा का आमा नहीं पहिनते और जनता उन्हें अपना नेता सम्भवत हुए भी, नेता नाम से नहा मानती।



बापू

बापू और समाजवाद

जिस समाजवादी समाज के नाम पर हमारी सरकार, नैतिक सिद्धांतों के विपरीत, प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त करने का वहाना ले रही है, उसी के विषय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार भी यहाँ दे देना अप्रसंगिक न होगा।

बापू से एक बार प्रश्न किया गया—“कांग्रेस समाजवादी दल ने कांग्रेस के लिये जो कार्यक्रम पेश किया है, उसके बारे में आपकी सामान्य टीका क्या है?”

बापू का उत्तर था —

“वह मानव स्वभाव में अविश्वास प्रगट करता है। उसकी सारी भूमिका ही गलत है।”

13 जुलाई सन् 1947 के हरिजन में बापू ने—“समाजवादी कौन?” नामक शीर्षक से एक लेख लिखा था। लेख काफी बड़ा है इसलिए इस की कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें ही यहाँ लिखी गई हैं :—

“समाजवाद एक सुन्दर गद्द है और जहाँ तक मुझे मालूम है, समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं।” इसी बात को कुछ उदाहरण दे कर, अधिक स्पष्ट करके उन्होंने आगे लिखा है —

“इस अवस्था तक पहुँचने के लिए हम एक दूसरे की तरफ देखते नहीं रह

सकते। जब तक सारे लोग समाजवाद न बन जायें तब तक हम कोई हल चल न करें। जीवन में कोई फेर फार न करके मायण दत रहें और काम पत्नी की तरह जहाँ गिकार मिल जाये वहाँ उस पर झपट पड। यह समाजवाद नहीं है। समाजवाद जहाँ शान्ति और धीरे धीरे मारने में हम से दूर जाने वाली है।)

(समाजवाद आरम्भ करने के विषय में उनके विचार)

समाजवाद पहले समाजवादी में शुरू होता है। यदि आरम्भ करने वाला स्वयं ही शूय होना परिणाम भी जय ही होगा।"

(समाजवाद क्या है और कस आये ? इस विषय में उनके विचार)

'यह समाजवाद स्पष्टिक की तरह शुद्ध है। इस लिये सिद्ध करने के साधन भी शब्द होने चाहिए। अगुद्ध साधनों में प्राप्त होने वाला माध्य भी अशुद्ध ही होता है। इसलिये राजा का मिर काट डालने से राजा और प्रजा बराबर नहीं हो जायेंगे। और न मालिक का सिर काटने से मालिक और मजदूर बराबर हो जायेंगे। हम अमत्य से मत्य का प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य आचरण द्वारा ही सत्य का प्राप्त किया जा सकता है।

अतः मैं उन्हीं लिखा है —

"मत्य परायण, अहिंसक और गुड हूँ मैं समाजवादी ही भारत और सत्तार में समाजवादी समाज स्थापित कर सकूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ सत्तार में कोई भी दण ऐसा नहीं है जो गुड समाजवादी हो उपरोक्त मायना के बिना ऐसे समाज का अस्तित्व में आना असम्भव है।

बापू के इस अमर से देश में समाजवाद लाने वालों के लिए एक चुनौती है—यदि उन्होंने समाजवाद को अपने जीवन में दास कर मत्यपरायण अहिंसक और गुड हूँ मैं से नरेगी के साधने प्रिथीपनों एन विरोधाधिकारों का समाप्त करने का विचार रखा होता तो वे अवश्य इस पर विचार करते। किंतु यह तो बाज प से की तरह गिकार पर झपट मारने जमा बात है जो हम समाजवाद से दूर त जाने वाली है।

बापू और नरेश

सन् 1933 का संविन्ध कानून भग आन्दोलन, महात्मा गाँधी द्वारा, स्थगित किये जाने के बाद कांग्रेस में समाजवादी दल का उदय हुआ। कुछ नेताओं ने महात्मा जी से समाजवाद के विषय में विभिन्न प्रश्न किये। उनमें से एक प्रश्न था .—

“भारत के राजा—महाराजाओं के शासन का अन्त करने की समाजवादी दल की जो माँग है, उसके बारे में आपकी क्या राय है ?”

महात्मा जी ने उत्तर दिया था, “मिट्टान्त की दृष्टि में मैं राजाओं महाराजाओं के शासन का अन्त करने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा विश्वास यह था कि लोकतन्त्र की सच्ची भावना के अनुसार उनके शासन में सुधार किया जाये।”

श्री जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी के पास समाजवाद के विषय में एक प्रस्ताव का मसविदा बना कर, रामगढ़ में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति के मामने रखने के लिए भेजा था, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त, राजा-महाराजाओं को समाप्त करने की भी बात कही गई थी। उस प्रस्ताव पर टिप्पणी करने हुये, भारतीय नरेशों के विषय में महात्मा जी ने कहा था .—

“मैं राजाओं सम्बन्धी उनकी सूचना का समर्थन नहीं करता। कानून की दृष्टि से वे स्वतन्त्र हैं। यह सच है, उनकी स्वतन्त्रता का कोई विशेष मूल्य नहीं है, क्योंकि एक प्रबल शक्ति उनका संरक्षण करती है, लेकिन वे अपनी स्वतन्त्रता का दावा कर सकते हैं जबकि हम नहीं कर सकते। श्री जयप्रकाश की प्रस्तावित सूचनाओं में जो बातें कही गई हैं उनके अनुसार अगर अहिंसात्मक साधनों द्वारा हम स्वतन्त्र हो जायें, तो उस हालत में, मैं ऐसी कोई समझौते की कल्पना नहीं कर सकता, जिसमें राजा लोग अपने को खुद ही मिटाने के लिए तैयार होंगे।

समझौता किसी भी प्रकार का क्यों न हो, राष्ट्र को उसका पूरा-पूरा पालन करना ही होगा। इसलिये मैं तो सिर्फ ऐसे समझौते की कल्पना कर सकता हूँ, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें अपने दर्जे को कायम रखेंगी। एक तरह से वह चीज आज की स्थिति से बढ़कर होगी, लेकिन दूसरी दृष्टि में राजाओं की सत्ता इतनी सीमित रह जायेगी कि देशी रियासतों की प्रजा को अपनी रियासतों में स्वायत्त शासन के वे ही

अधिकार प्राप्त रहेंगे जो हि दुस्मान के दुमरे हिस्से की जनता को प्राप्त रहेंगे । उनको माफग लखन तथा मुग्ध का स्वतन्त्रता और गुड चाप प्राप्त रहेगा ।

भायद श्री जयप्रकाश का यह विश्वास नही है कि राजा लोग स्वच्छा से अपनी निरकुशता को त्याग देंगे । मुझे यह विश्वास है एक तो हमनिये कि वे भी हमारी ही तरह भले आदमी हैं और दूसरे इसलिए कि मेरा गुड अहिंसा की अमोघ शक्ति में सम्पूर्ण विश्वास है । अतः अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या राजा महाराजा और दूसरे लोग सभी सच्चे और अनुत्तम बन जायेंगे ? तब हम खुद अपने प्रति—यदि हम में थड़ा है—और राष्ट्र के प्रति सच्चे बनेंगे । अधकचरी थड़ा से लय कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता । अहिंसा का आरम्भ और अतः आत्म निरीक्षण में होगा है ।'

पूज्य चापू के आत्म विश्वास के अनुसार राजा महाराजाओं ने तो, समय आने पर, स्वच्छा से सब निरकुशता का ही नहीं अपनी सत्ता का भी त्याग कर दिया । अब तो राष्ट्र का ही यह कर्तव्य रह जाता है कि वह राष्ट्रपिता की आशा राष्ट्रीय नेताओं के बचन एवं नतिष्ठ दुष्टि बाण के अनुसार समयों का परा पूरा पालन करे ।

विशेष रूप से जब कि हम 2 अक्टूबर 1968 से सारे विश्व में अपने पूज्य राष्ट्रपिता की जयन्ती मनाते जा रहे हैं—क्या राष्ट्र उस महामानव के बचन का धन्यवना करके उसका अन्त में भी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेगा ? क्या हम विश्व में यह कह सकेंगे कि राष्ट्र, जिन गांधी के मित्रों की ओर विश्व का जनमन आदर दारण विश्व शांति का आशा कर रहा है जिन गांधी का भारत गांधी के बचन की धन्यवना कर रहा है ?

प्रस्ताव की प्रतिक्रिया

समाचार पत्र और नरेश

हमारे देश के समाचार पत्रों ने भी नरेशों के प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारों के विषय में पर्याप्त रुचि ली है। कुछ प्रमुख पत्रों के मत बहुत सक्षिप्त रूप में निम्न हैं :—

—द हिन्दुस्तान टाइम्स नई-दिल्ली

जून 26, 1967

प्रिवीपर्स नरेशों के राज्यों का एकीकरण निर्विघ्न बनाने और भारतीय सभ में एक रूपता का जडाव करने के लिये कांग्रेस सरकार द्वारा किये गए पवित्र समझौते का अंग है। जो मूल्य चुकाने का समझौता हुआ था, वह उस पूरे होने वाले कार्य के महत्व की तुलना में कुछ भी नहीं था, जिसे मरदार पटेल ने पूरी तरह से समझा था।

— — —

—द मेल, मद्रास

जून 26, 1967

कोई सरकार अपनी पवित्रता को हानि पहुँचाये बिना जनता के निम्नी नी भाग के साथ अपना वचन भंग नहीं कर सकती। दल की चुनाव सम्बन्धी दलित वेदी के लिये बलिदान के बदले प्राप्त करने का प्रयास उसे स्वयं पीछे हटा देगा। सरकार ने किमी को जो कुछ देने का समझौता दिया है, उसे उनसे दन्त कर देने से कांग्रेस का समाजवाद सिद्ध नहीं होता और भूतपूर्व नरेशों

के प्रिवीपसों एवं विनापाधिकारों के सम्मूहन से कांग्रेस को एक भी अतिरिक्त मत (वोट) का लाभ नहीं हाया।

—द इंडियन नेशन, पटना

जून 26, 1967

आज प्रिवीपस समाप्त किये जा रहे हैं। कल को सरकारों को इस और प्रमाण पत्र (सर्टीफिकेट्स) में जमा धन भी जमा हो जायेगा। क्या रुपये का अवमूल्यन 'पाकिट मारो' नहीं थी? किन्तु जनता क्या कर सकती? सरकार को यह अब भी सिद्ध करना है कि यह जनता के हित में किया गया था। साम्यवादी उचित परिणाम के लिए उचित मार्ग गृहण करने का बहाना नहीं करते। किन्तु कांग्रेस तो राजनीति में नतिकता का आवश्यकता पर बल देती रही है। यदि कांग्रेस अपने ध्वजा का पालन नहीं कर सकती तो नतिकता कहाँ रही? तब कांग्रेस और साम्यवादी दल में अंतर ही क्या रहा?

—द लीडर इलाहाबाद

जून 29 1967

क्या किसी सदन के लिये नरेशों के प्रिवीपसों सम्बन्धी धाराओं में परिवर्तन करना जमा कि मविध्य में होने जा रहा है सम्भव होगा? सत्य तो यह है जो कांग्रेस का मानना पड़ेगा—कई राज्यों में यह बहुमत प्राप्त करने में असफल रही है क्योंकि मत दाताओं में बहुत बड़े भाग में उमर शासन का अयोग्य और भ्रष्ट समझा। लोग लाला मुरादा और कपटे उच्च मूल्य पर चाहते हैं। मुख्य समस्या है जिस पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए।

—द मेल, मद्रास

जुलाई 16 1967

मिस्टर फव अचानी ने लोर समा में सबन किया है उन्होंने कहा "भूदान और सिक्कम की रियासतों का स्थिति उन रियासतों के समान ही है, जिन्होंने सविलयन पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। यदि हम एक बात में निराश कर लें, हम हमारे भाषता में उन्हें पक्ष लेते। जबल यही दो रियासतें नहीं हैं

जो कि यह शका करेंगी कि भारत सरकार का कहाँ तक विश्वास किया जाये? भारत सरकार उधार लेने की आदी है, बहुत से देशों की ऋणी है इस का कोई भरोसा नहीं है कि एक समझौता तोड़ दिया गया है तो दूसरे रखे जायेंगे। नरेशों को दिये जाने वाले तुच्छ धन का, सरकार की प्रतिष्ठा के विचार से कोई मूल्य नहीं है।”

— द हिन्दू, मद्रास

जुलाई 28, 1967

बहुत से कांग्रेसी नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पिछले माह की सम्मति को दल का आदेश बतला कर और इसे सरकार पर दबाव देने की पवित्रता का आधार बतला कर, सरकार को इस मामले में निर्णय करने के लिये धकेल से रहे हैं।

घटनाओं का एक विभाजन— जिसमें श्री मोहन धारिया का प्रिवीपर्सों की समिति के लिये सशोधन पास होना बतलाता है कि उस माँग को अधिकार पूर्वक बहुत बड़े लोकमत का सहारा कहना, एक बहुत बड़ी धृष्टता है। सशोधन (श्री० एस० के० पाटिल के अनुसार) चार के विरुद्ध सत्तरह मतों से पास हुआ। जिसका अर्थ है, मतदान में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुल सदस्यों की संख्या के $\frac{1}{3}$ भाग से भी कम लोगों ने भाग लिया।

संविधान की पवित्र धाराओं और पूर्वं ऐतिहासिक घटनाओं का, जिनके फलस्वरूप भारतीय सघ में नरेशों की रियासतों का सविलयन हुआ, आदर किये बिना अधिकार पूर्वक यह कहना कि इस तरह का नियम विरुद्ध निर्णय सरकार को बाध्य करता है, (दल के पिछले भाग पर) दल की दुम पर सरकार व मसद को आज्ञा देने का अधिकार प्रतिपादन करता है।

— वीकेन्ड रिव्यू, नई दिल्ली

जुलाई 29, 1967

जब सिक्कम के चोग्याल की, भारत—सिक्कम संधि के पुनः सशोधन के लिए बार-बार प्रार्थनाओं का सामना करना पड़ा, भारत ने बहुत उचित रूपसे निवेदन किया कि चोग्याल संधि की धाराओं का सम्मान करते हैं। इस विषय में वह (भारत) विनोत नहीं हुआ। भारत का सिक्कम के प्रति अपने सिद्धांत पर जमे रहना बहुत निर्बल हो जायेगा, यदि उसने पहले के “प्रिंसैज चैम्बर”

के सदस्यों के साथ हुये, समझौते को उनकी स्पष्ट महमति के बिना बदलने का इरादा किया।

—द मेल, मद्रास

जुलाई 31 1967

वास्तव में विधि मंत्रालय का सम्बन्ध इस विषय में केवल वाचनी दृष्टि कोण से है, उसका नतिवता से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु कोई सरकार बिना गम्भीर हानि दिये हुए, नतिव वक्त्यों का त्याग नहीं कर सकती।

—द लीडर, इलाहाबाद

अगस्त 3, 1967

यदि हर समय दिये हुये वचना को सपेटा गया तो राजनीतिज्ञ राज नतिक साधना को नतिक सिद्धांतों से अधिक आवश्यक बना दें और वचना की पवित्रता जिसकी कि निश्चय पूर्वक कल्पना की गई है 'सारभूत नैतिकता' का नाम लिया गया है, किसी प्रकार के भी समझौते कागज के टुकड़ा के अति रिक्त कुछ नहीं रह जायेंगे, जिनको कि वे काम निकल जाने पर फेंक देंगे।

श्री० सी० राजगोपालाचारी

—स्वराज्य, मद्रास

अगस्त 5, 1967

जिस सरकार ने वाणिज्य का अतिरिक्त अभिनय ग्रहण लिया है और अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के आधीन हो गई हो, वह अपने मुकुट पर से इस जादू का वाक्य—सत्यमेव जयते सत्यम्—की वचन एवं काय में, ईमादारी के साथ उल्लेख नहीं कर सकती।

द कैपीटल, कलकत्ता

अगस्त 10 1967

यह बड़ी मनोरंजक बात है जिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सामने शासका की समस्या है वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। मध्य पदम में कांग्रेस मंत्रिमंडल के साथ होने के पहले भी, मुख्य मंत्री द्वारा प्रसाद मिथा इसके विरोध में थे। यही बात गुजरात के मुख्य मंत्री श्री हिते द दसाई की है। राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री सुखादिया को शय है—कि यह बदम उनके सख्खदाते मंत्रिमंडल को वहीं उलट ही न दे। यह स्वीकृत सत्य है कि कांग्रेस के उच्च अंशों के नेता

प्रिवीपर्स के उन्मूलन के विषय में उत्सुक नहीं थे, वे तो इस घमकी के द्वारा शासको को केवल भुक्ताना चाहते थे। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी यह नीति निशाने पर सही नहीं बैठी।

द हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली

अगस्त 12, 1967

कांग्रेस की वर्तमान चित्त वृत्ति के अनुसार उसके विषय में वचन और प्रतिज्ञाओं के पालन की बात करना ही व्यर्थ है। यहाँ तक कि श्री चट्टाण भी, जो प्रिवीपर्स के उन्मूलन का कदम उठा रहे हैं, किसी तरह से घुमा फिरा कर यह स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस ने शासको से वायदा किया है जो कानूनी और नैतिक रूप से सही है। किन्तु उनका तर्क यह है कि कांग्रेस ने विशाल जनता से भी तो वायदा किया है जिसकी सख्या राजाओं से दस लाख गुनी है।

यह सही है। किन्तु जनता से किया गया वायदा क्या है? श्री चट्टाण ने यह नहीं स्पष्ट किया, किन्तु इस विषय में उनके मस्तिष्क में जो बात स्पष्ट है वह यह है, कि कांग्रेस ने उस जनता के जीवन स्तर को कुछ सरल बनाने का वायदा किया है, जो कि कांग्रेस के 20 वर्ष के शासन में अब तक गरीबी की चक्की में पिसती हुई कराह रही है। गणना के अनुसार वास्तव में उसकी स्थिति इन 20 वर्षों में और अधिक खराब हो गई है।

किसी भी विचार से यह स्थिति बड़ी अपमानजनक है। मुझे आश्चर्य है, क्या श्री चट्टाण भी यह विश्वास करते हैं कि उनके दल द्वारा राजाओं के प्रति कर्तव्य पालन न करने का जो आचरण आरम्भ किया जा रहा है, उससे चार करोड़ रुपये वार्षिक की वचत जनता से किए गए वायदे को पूरा करा सकेगी?

द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली

अगस्त 15, 1967

कांग्रेस के सभी नेता प्रिवीपर्स के उन्मूलन के पक्ष में नहीं हैं। उदाहरण के लिये, श्री मुखरजी देसाई ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। यद्यपि कांग्रेसी होने के नाते, वह अपने आपको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय को मानने के लिए बाध्य समझते हैं। तब भी यह अस्वीकार्य विवक्षित

है कि यह नियम समुचित सावधि विचार कर नहीं किया गया था, बल्कि यह तो कुछ चलते फिरते मता के फल स्वरूप ही है। कांग्रेस दल के निजी दृष्टि कोण से भी उस पर पुनर्विचार की अत्यन्त आवश्यकता है। श्री देसाई और अन्य कांग्रेसी नेताओं को जो उन्हीं के जमे विचारों वाले हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अपनी आगामी बैठक में इस समस्या पर अधिक विचार करने का जोर देना चाहिए। यह सम्भव है यदि इस मामले को फिर से उठाया जाये तो दिल्ली की सभा में शीघ्रता से पारित हुआ प्रस्ताव सम्पात कर दिया जाये। ऐसी बहुत सी अन्य समस्याएँ हैं जिन पर सरकार व दल को शीघ्र ही ध्यान देना चाहिए। यह सत्य है कि प्रिवीपस का रहना या न रहना, जिसकी कुल राशि पाँच करोड़ वार्षिक है उन प्रमुख समस्याओं में से नहीं है।

द हिन्दू, मद्रास

अगस्त 17 1967

अनेक कांग्रेसी संसद सदस्यों द्वारा अपने हित में महत्वपूर्ण समर्थन पाने पर भी (जिस कि संसद में हुए अभी हाल ही के वान विवादों से स्पष्ट है) यह आश्चर्य की बात नहीं है कि नरेश ने स्वयं एक सावधानी बर्ती है और अपने प्रिवीपसों एवं विशेषाधिकारों के लिए दी जाने वाली धमकी के विरोध में कोई सघन भी सहा नहीं किया है। इसमें संदेह नहीं उठाने एक समिति बनाई है जो कि उनके भूतकालीन नरेश मंडल (चम्बर आफ प्रिंसज) के समान ही हो सकता है कि तु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से अपन इस नियम पर पुन विचार करने के लिए उद्देश्य अतीत बहुत सोच विचार कर बड़े समयित सभा में का है। 600 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की घोषणा 4 नवम्बर 17 मतों द्वारा अधिवेशन के अंतिम दिन जिस नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की गई है उसके गुण व दोषों पर पुनर्विचार करके अधिक स्वस्थ नियम लिया जा सकता है।

द मेल, मद्रास

अगस्त 22 1967

यह मेली भाँति विदित है, नरेश द्वारा राष्ट्रीय एकता के हित में अपना सत्ता, अधिकार एवं राजस्व त्यागने के भूत का प्रिवीपसों के रूप में सरकार ने बहुत बड़ा समझा था।

यदि उस समय वह (सरदार) सविधान मे ऐसी धारा चाहते थे, जिसके अनुसार नरेशो के साथ किए गये समझौते न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे तो उसका कारण यही था कि उन्हें यह तनिक भी पसद नहीं था कि भावी सरकार या कोई नागरिक नरेशो को कानूनी मुकद्दमो मे फसा कर तग करे। किन्तु विधि मन्त्रालय ने इस धारा की जो व्याख्या की है वह बिल्कुल उससे उल्टी है जो वास्तव मे सरदार पटेल ने इस धारा के विषय मे सोचा था। विधि मंत्री चकित करने वाले वक्तव्य देते रहते है, “रियासतो के लिए सघ में मिलने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं था और इसका प्रिवीपर्स से कोई सम्बन्ध नहीं है।” इसके विपरीत इसका (प्रिवीपर्सों) उनसे (सघ मे विलय से) पूरा सम्बन्ध है। विलीनीकरण तो प्रिवीपर्सों एव विशेषाधिकारो के बदले में किया गया था और इनके लिए नरेशो को गारण्टी दी गई थी। चूंकि अब नरेश शक्ति हीन है, इसलिए सरकार इन समझौतो को तोड़ सकती है क्योंकि उसके इस कार्य के लिये उसे कोई दण्ड नहीं दे सकता। किन्तु बुद्धिमानी तो इसी मे है कि कानून और नैतिकता का अभिमिश्रित न किया जाये क्योंकि ये दोनो पूर्ण रूप से नरेशो के पक्ष मे है।

द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली

अगस्त 23, 1967

श्री मैनन ने अपने विचार प्रकट किए है कि नरेशो के साथ हुए समझौते एव प्रसविदाये सविधान लागू होते ही प्रभाव हीन हो गई। केन्द्रीय विधि मंत्री के लिए सबसे उचित बात तो यह है कि वह शीघ्र से शीघ्र इस बात को समझ ले कि उनका यह कहना बड़ी गम्भीर उलझने उत्पन्न करने वाला है।

अगर श्री मैनन का यह कहना सही है, प्रसविदाय और समझौते 26 जनवरी 1950 को प्रभावहीन हो गये तो पाकिस्तान व अन्य देश इस बात को बड़ी खुशी से ग्रहण करेंगे—तब वे इस पर वाद-विवाद कर सकेंगे कि जम्मू व कश्मीर के महाराजा हरीसिंह ने जिस सविलयन पत्र पर हस्ताक्षर किए है वह सविलयन पत्र अपना महत्त्व 17 वर्ष पूर्व ही खो चुका है। वास्तव मे यह मामला इतना सरल नहीं जितना कि विधि मंत्री समझ रहे है। जो कुछ श्री मैनन ने सोमवार को कहा है उसका विवेचन इतनी उलझने उत्पन्न करने वाला है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल को कि इस प्रश्न के रूप

पर अपना सम्मिलित मस्तिष्क लगाने में मग्न नहीं होता चाहिये। भारत सरकार के लिए उस सिद्धान्त पर अमल करना अनुत्तरदायित्वपूर्ण और अपमानकारक हो सकता है जिसने बल पर कश्मीर का भारतीय संघ में सम्मिलन एवं कानूनी अधिकार टिक रहा है।

द पायोनियर, लखनऊ

जगस्त 24, 1967

यदि सरकार प्रिवीपटों के उम्मीदों के लिए कानूनी विजय प्राप्त कर लेती है तो भी ऐसा करना क्या उचित है? मुख्य विषय कानूनी नहीं है बल्कि सम्मान और इमानदारी का है। सरकार ने जो वचन दिए हैं उन्हें पूरा करने के कलम में वह धड़ी हुई है। वास्तव में देश के संविधान का निर्माण कुछ विंगप प्रकार के पवित्र वचन पर ही आधारित है एक वचन धार्मिक अल्पमध्यमका को दिया गया था और यह घोषित किया गया था कि भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं होगा। सरकार ने दूसरा वचन पौर नेषा कमचारिया को उनका सुविधा के लिए दिया था। तीसरा वचन नरेगा को दिया गया था। क्या सरकार के लिए 20 वर्ष बाद इन पवित्र वचन में से किसी को तोड़ना उचित है? यह तब कि सरकार का समाजवाद से गठबंधन हो चुका है इसलिए नरेगा के विशेषाधिकार छान लेने चाहिए कोई अच्छा तब नहीं है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक की बात है कि सरकार 20 वर्षों तक तो इस विषय में चुप रहा और अचानक ही उसने यह अनुभव कर लिया कि नरेगा के विशेषाधिकार सत्ता धारी दल के समाजवादी सिद्धान्त के विरुद्ध हैं।

समाचार पत्र (विपक्ष में)

प्रिवीपटों एवं विशेषाधिकारों को कबल भारत सरकार की आगता सम्मान देने, कम पड़े लोगों को तो बट ही क्या? हमारे यहां के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों का यह हान है। कभी कभी तो इन पत्रों की मूल धूम पर न्या आती है—बिना सोचे समझे नरेगा के विरुद्ध कुछ न कुछ ऊल जलून लिखते रहकर ही वे अपने "विचारों" की प्रगति नीतियों का सिक्का जमाना

चाहते हैं :—

दिल्ली के एक हिन्दी दैनिक ने अपने मई 1968 के किसी अंक में एक कार्टून छापा था, जिसमें भारतीय नरेशों को अपने अपने हाथों में शिक्षा पात्र लिये हुए गृह मंत्री के सम्मुख प्रिवीपर्स की शिक्षा माँगते दिखलाया गया था।

इस कार्टून के विषय में स्वयं इस पत्र के पाठकों ने इसकी निन्दा की है एवं इसे अमंगल तथा अविवेकपूर्ण कहा है।—

इसी पत्र ने 22 जुलाई 1968 के पत्र में अपने 'विचार प्रवाह' कालम के अन्तर्गत, राजाओं की अपील नामक शीर्षक से इस विषय में अपने विचार प्रगट किये।

इन पंक्तियों को पढ़कर यह समझ में नहीं आता— हम इसे पत्र की इस विषय में अनभिज्ञता समझे ? भ्रम समझे ? या जान बूझ कर पाठकों को वहकाने का प्रयास समझे ?

इसका निर्णय, विचार प्रवाह की पंक्तियों और उनके यहाँ दिये गये उत्तरों को पढ़कर, पाठक स्वयं कर लें :—

राजाओं की अपील

राजाओं की ओर से एक बार फिर यह अपील की गई है कि भारत सरकार प्रिवीपर्स और विधेयाधिकारों के सम्बन्ध में अपने वचनों और आश्वासनों का पालन करे, कोई शक नहीं कि सरकार ने वचन और आश्वासन दिये थे, परन्तु कोई क्या इसका यह अर्थ ले सकता है कि वे शाश्वत काल के लिये थे ? यह बात भूलने की नहीं कि जिस सरकार ने यह वचन दिये थे उसने अपना लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना नहीं स्थिर किया था, तब परिस्थितियाँ और थी और जमाने के साथ वे निरन्तर बदल रही हैं, ऐसी मूर्त में नयी परिस्थितियों में वे पुरानी बातें कैसे कायम रखी जा सकती हैं जो असमानता और सामंत शाही की प्रतीक हैं, इसलिये राजाओं ने सभ्य समाज का नाम लेकर सरकार के वचनों और आश्वासनों की जो दुहाई दी है उसका कोई अर्थ नहीं है।

फिर उनका यह कहना तो और भी विचित्र लगता है कि भारत को एक बनाने के लिये उन्होंने जो सहयोग दिया उसके महत्व को नहीं समझा जा रहा। क्या वे समझते हैं कि उन्होंने ऐसा करके बहुत अहसान किया ? उस समय जो परिस्थितियाँ थी उनमें क्या वे इसके विपरीत आचरण कर सकते

विशेषाधिकारों की समाप्ति से यह एक दम आकाश से उतर कर हमारे सामने पड़ा हो जाएगा ?

समाजवादी समाज का ढोल पीटने वाले पहले स्वयं की तो समाजवादी सिद्धांतों के अनुकूल ढाल कर दिखताएँ ।

परम पूज्य बापू के शब्दों में —

‘ समाजवाद पहले समाजवादी से शुरू होता है । यदि आरम्भ करने वाला स्वयं ही गूँथ हो तो परिणाम भी गूँथ ही होगा ।

फिर उन क्षतिपूर्ति देती रही ।

ऐसा प्रतीत होता है, पत्रकार महोदय ने सविधान सम्मेलन में गए बकरवा के द्वारा सरदार पटेल आदि नेताओं के विचार नहीं पढ़े और न उ होने उस समय की परिस्थितियों पर ही कभी चिन्ता किया है नहीं तो वह नरत्ना के इस विरह प्रकार की भाषा का प्रयोग कदापि न करत ।

यदि नरेश चाहते तो वे भी मुस्लिम लीग की तरह अंग्रेजों से भारत के पाकिस्तान से पपक, राजस्थान की माँग कर सकते थे । और अंग्रेजों का नृतिव दृष्टि से यह मानना ही पड़ता । कंगवित अंग्रेज चाहते भी मंता थे ।

प्रियापत्तों एवं विशेषाधिकारों को भारत सरकार की उत्तरदायित्व देने वाले केवल उसकी कीमत ही जानते हैं इसका वे मूल्य नहीं समझते ।

यह भी छीन लेती ।

यह कोई तर्क संगत बात नहीं मालूम पड़ती । क्या इनके उत्तर में यह नहीं कहा जा सका कि अंग्रेजों ने जिन भारतीय राजाओं के नवाबा के राज्य लिये यदि वे उनका बग़ावत को ही राज्य वापस कर जाते तो क्या होता ?

सबसे बड़ी सन्तुष्ट रहना चाहिये ।

यह भी समझने का भूल है यह प्रश्न क्यों प्रियापत्तों एवं विशेषाधिकारों का ही नहीं — प्रश्न है सिद्धांतों का विश्वास—अविश्वास का नृतिवता—अनैतिकता का आचार आचार का भारत सरकार ने प्रियापत्तों एवं विशेषाधिकारों की समाप्ति करने का जो स्वयं अपनाया है, वह अनृतिव एवं तानाशाही का माग है । यह तो लोकतन्त्र के लिए मायन ग्राही से बड़ी अधिक भयंकर है ।

अहिंसा कांग्रेस का मूल सिद्धांत था, किन्तु उसने गान्धेय का बागडार हाथ में लते ही अहिंसा को केवल नीति के रूप में प्रयोग करना आरम्भ कर

दिया था। किन्तु अब तो ऐसा प्रतीत होता है, वह अहिंसा को नीति रूप में भी प्रयोग करना नहीं चाहती, अब तो वह केवल हिंसा के द्वारा ही अपनी सत्ता को अटल बनाये रखने पर उतारू हो चुकी है।

किसी लोकप्रिय पत्र में ऐसे एक पक्षीय एवं उथले विचार पढ़कर आश्चर्य व दुःख होता है।

समाचार पत्र लोक तन्त्र की रीढ़ होते हैं। उन्हें अपने विचार प्रकट करते समय केवल सरकारी नीतियों का भुँह नहीं ताकना चाहिए, और न किसी दल विरोध से ही कोई लगाव रखना चाहिए। उनका उद्देश्य तो निष्पक्ष और निर्भय हो कर जनता का हित व उसकी रुचि स्पष्ट करने का होना चाहिए।

आज जन साधारण को नरेशों के प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारों की समाप्ति में कोई रुचि नहीं है। और न वे उसमें अपना कोई विशेष हित ही देखते हैं। वास्तव में सरकार को यदि समाजवादी समाज की स्थापना करना ही है और वह उसके लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहती है तो वह अपनी शक्ति और अधिकारों का प्रयोग सबसे पहले समाज की नस-नस में व्याप्त होते जा रहे भ्रष्टाचार के विष को समाप्त करने में क्यों नहीं करती? यही विष घूस खोरी, जमा खोरी, काला बाजार, तस्करी व्यापार एवं अनुशासनहीनता आदि अनेक रूपों में अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। समाज निर्बल होकर समाजवादी समाज से कोसों दूर भागता चला जा रहा है।

राजनीतिज्ञ

संसद के बाहर

श्री कन्हैयालाल माणिक लाल मुन्शी

प्राण जाहूँ बर वचन न जाई

गांधीजी की तुलसी की निम्नलिखित दो पक्तियों से विशेष अनुराग था और वह उन्हें आम तौर से दोहराते रहते थे।

रघुनुत रीति सदा चरति आई ।

प्राण जाहू बर बचनु न आई ॥

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद संविधान सभा (कॉन्स्टीट्यूट असेम्बली) ने स्वदेशवासियों का प्रतिनिधि सभा के रूप में अपने देश के संविधान का निर्माण किया और उसकी आधारशिला को दृढ़ करने के लिए स्वदेशवासियों को कुछ वचन दिये । प्रथम विविध धर्मों के अल्पसंख्यक अनुयायियों को यह वचन दिया गया कि भारतवर्ष किसी एक विनिष्ट धर्म में आस्था नहीं रखेगा तथा कि-ही दो धर्मों में कोई अंतर नहीं मानेगा अर्थात् यह धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा और सब धर्मों को समान सम्मान देगा । संविधान सभा द्वारा नियत हुए इस आश्वासन का संविधान में लिख कर अटल बना दिया गया । द्वितीय सिविल सेवा के सदस्यों को जिन्होंने स्वाधीन भारत के काम काज दायित्व चलाने का दायित्व उठाया था विश्वास दिलाया गया कि उनकी सेवा नियमावलि में कोई भंग नहीं किया जाएगा तथा उनके बतन आदि में कोई कटौती नहीं की जाएगी । तृतीय भारत में फली सफाई रिमासता के तत्कालीन नासकों का यह वचन दिया गया कि उन्हें प्रिवी-एस मिलती रहेंगी तथा उनके विभागीय अधिकार सुरक्षित रहेंगे ।

भारत की इन सैकड़ विधियों रिमासता का भारत गणराज्य में प्रथम अर्थात् भारत की इस अद्वितीय गवता के लिए तीन चीजें जिम्मेदार हैं—(1) सरदार पटेल की तीव्र बुद्धि और सामान्य मध्य-वृत्त 2 बी० पी० मनन का व्यवहार कुशलता तथा 3 इन रिमासता के नासकों की देशभक्ति उत्तारता और दूरदर्शिता । उस समय इन नासकों का न जान वाली प्रिवी एस की राशि छ करोड़ रुपये में भी कम बनी थी जो प्रत्येक नासक के मरने के साथ कम होनी जानी थी । इस प्रकार यह राशि घट कर पांच करोड़ रुपए तथा अब और भी घट गई अब तीन करोड़ से कुछ ज्यादा है । अर्थात् यह राशि विभागीय सरकारी छव में नागरिक मूद के समान है ।

इस प्रश्न के आधिकार पहलू का छोड़ दीजिए जो कम महत्वपूर्ण है । हमारे दूसरे पहलू की देखिए जो भारत की प्रतिष्ठा की दृष्टि में भारत के लिए जीवन मरण का प्रश्न है । प्रिवी-एस हमारे राष्ट्र के संविधान की नींव में रगी हुई अनेकों इन्त में एक स्त है जिसने निकाल देने से हमारे संविधान के भवन के मकबरा कर गिर जाने की आशंका है— तुरन्त नहीं, कुछ समय बाद । प्रिवी-एस के उन्मूलन प्रस्ताव की स्वीकार कर देने से भारत की प्रतिष्ठा मिट्टी

मे मिल जाती है, भारत के वचन का महत्व दो कौड़ी रह जाना है। सब पूछो तो यह कदम भारत के जीवन वृक्ष की जड़ को खोदने के बराबर है।

जो लोग आज इस प्रस्ताव के जन्म दाता एवं पोषण कर्ता हैं, वे एक बात भूल जाते हैं कि 1947 में ऐसी अनेक शक्तियाँ थी जो भारत को एक संगठित एवं विस्तृत राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहती थी, जो इस दिशा में किए गए भारत के प्रत्येक कदम को विफल करने के लिए रात-दिन प्रयत्नशील थी।
.....

[उस समय प्रत्येक भारतीय रियासत को छूट थी कि वह चाहे भारत में मिले और चाहे पाकिस्तान में।]

सरदार पटेल ने जब सब रियासतों को भारतीय गणराज्य में मिला लिया और उन रियासतों के भूतपूर्व शासकों को प्रिवीपर्सों मिलनी शुरू हो गईं तो कांग्रेस दल के अनेक सदस्यों ने सरदार से इस विषय पर चर्चा की, कि प्रिवीपर्सों को वन्द कर दिया जाए क्योंकि रियासतें तो भारत में मिल चुकी थी और उनके वापस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। सरदार पटेल ने इन आपत्ति उठाने वालों को शान्तिपूर्वक सुना और अचानक उनसे प्रश्न किया, “क्या आपको स्वराज मिला? क्या आपने रियासतों की प्रभुसत्ता को समाप्त किया?”

क्या आपने इन भूतपूर्व शासकों को कुछ वचन दिये और उन्हें सविधान में लिखा? मुझे यह नहीं मालूम कि अन्य लोग जिन्होंने यह वचन दिये थे, आज क्या सोचते हैं। आप चाहें तो उनके पास जा सकते हैं। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इन दिये वचनों का पूरी तरह पालन करूँगा।”

आज दुर्भाग्य से सरदार पटेल नहीं हैं जो दिये वचन से मुकरने वाले इन लोगों को डाँट कर चुप करा देते। आज जवाहरलाल भी नहीं हैं जिनका अन्तर्मन इस प्रकार के विश्वासघात से आतंकित हो उठता। आज गाँधीजी भी नहीं हैं जो हमें समझाते कि अपने वचन से मुकरना और आध्यात्मिक मृत्यु में कोई अन्तर नहीं है।

यदि आज के निरकुश शासक, लोकतन्त्र को जीवित रखना चाहते हैं तो उन्हें धर्म और कानून के बीच भयंकर गड़बड़े को पहचानना होगा और इसमें

गिरने से बचना होगा। सरदार पटेल को भी 'निरकुश शासक' कहा जाता है। सोह पुष्प कहकर सम्बाधित किया जाता है तथा बहुत निमम और कठोर बतलाया जाता है किन्तु उनका माने का धात्र क निरकुश शासक ने गंगा से सातिय और पहचानिय। सरदार पटेल को इस बात का ज्ञान था कि राष्ट्र का सुस्थिरता की आधारगिता घम है न कि विधेयक प्रतिवन्त या काननी मत। हमार दा राष्ट्रिय महाकाव्य रामायण और महाभारत जीवन के विविध पक्ष का निरूपण करत है और उनका आदर्श रूप प्रस्तुत करत है। किन्तु उनका मूल तत्त्व यही है कि अपन जिसे बचन का हर बीमत्त पर पालन करत चाहिए। अपने बचन का रक्षा के लिए राज्य सिंहासनो को छोड़ दिया गया तथा बनवास भी स्वीकार किया गया। आज हम उस नतिक स्तर का सामन रखत है जिसका हमने 1947 में प्रदर्शन किया था। उस नतिक पक्ष का भूलने के कारण हम काफी गुरुमान सहता पडा है किन्तु अब भी समय है कि हम अपने में अपक्षित सुधार कर ल तथा और भवानक गलतियाँ न करें।

संविधान की धारा 362 की अवहचना करना, उसके विपरीत कार्य करना तथा धारा 363 की गारण लेना मात्र एक कानूनी छलना है प्रयचना है, आत्मघात है। कितने आश्चर्य की बात है कि विधि मंत्री ने भी प्रिवी पर्सों के उ मूलन के पक्ष में संविधान की धारा 362 को ताड़ने मरोडने का आग्रह रचा है। यह ठीक है कि पक्ष समझौते की किसी धारा के विषय में मतभेद होन पर पक्ष का निर्णय मा म होता है तथा उस मतभेद का अदालत में नहीं से जाया जा सकता, किन्तु यदि पक्ष समझौता ही किसी पक्ष द्वारा रद्द कर दिया जाए तो अदालतों को पूरा पूरा अविचार है कि वे उस समझौते पर विचार कर और अपना निष्पक्ष निर्णय दें।



चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी।

**नरेशों के साथ किए गए समझौते
कागज के टुकड़े नहीं, पावन प्रतिज्ञा-पत्र हैं**

अपना अयध्यवस्था को सुदृढता एवं सुस्थिरता प्रदान करना हमारा प्रथम धर्म है। इसके लिए हमें अपने राष्ट्रीय व्यय में प्रत्येक सम्भव कटौती तथा अपने राष्ट्रीय उत्पादन में प्रत्येक सम्भव वृद्धि करनी चाहिए। सावजनिक

व्यय के अनावश्यक पक्षों को समाप्त करना, सैनिक व्यय को कम करने के लिए प्रबुद्ध विदेश नीति का निर्धारण करना, राजकीय उद्यमों से लाभपूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के लिए उनमें सुप्रवन्धता एवं कार्यकुशलता प्रविष्ट करना आदि अनेक मार्गों के अनुसरण से हम उपरिर्वर्णित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। किन्तु इसके लिए नरेशों के 'प्रिवीपर्स' वन्द करना अर्थात् अपने दिये वचन को तोड़ना किसी भी दृष्टि से सगत नहीं है।

जीवन में वचन की पावनता सर्वोपरि है। उसको किसी भी रूप में भग करना जघन्य पाप है। इससे न केवल अपने हृदय की सात्त्विकता विनष्ट होती है अपितु दूसरों की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार समझौता दो पक्षों के बीच हुआ ऐसा पावन सम्बन्ध है जिसकी मर्यादा अनुल्लङ्घ्य है, यह दो पक्षों को जोड़ने वाला ऐसा पवित्र बन्धन है जिसके पालन करने में ही जीवन का आनन्द है। यह बन्धन दोनों पक्षों के लिए समान रूप से मान्य है इसको तोड़ने का किसी पक्ष को अधिकार नहीं है। और यदि एक पक्ष इसका पूर्णरूपेण सम्मान कर रहा हो तो दूसरे पक्ष द्वारा इसकी पावनता भग करने का विचार भी मन में लाना अपराध है।

अयोध्या नरेश दशरथ ने अपने वचन का सम्मान करने के लिए राम जैसे आदर्श पुत्र के वियोग का दारुण दुःख सहन करना भी स्वीकार किया। राम ने अपने पिता के वचन की मर्यादा को अभंग रखने के लिए युवराज-पद त्याग कर चौदह वर्ष वन में वास किया। 'प्राण जाहुँ वरु वचनु न जाई' इस देश का आप्त वाक्य है, इस देश के वासियों के जीवन का निर्देशक मन्त्र है, भारत के पचास करोड़ लोगों के प्राणों का मूल मन्त्र है। राम को भी अनेक लोगों ने वहकाने का असफल प्रयास किया था कि वह, युवा पत्नी के सौन्दर्य बन्धन में बंधे बृद्ध पिता के दिये वचन को न माने किन्तु राम ने इन कुतर्कों की ओर तनिक भी ध्यान न दिया और वचन की पावनता को अमरता प्रदान की।

भारत के सामने आज इसी घटना की पुनरावृत्ति है। देश को स्वाधीनता दिलाने वाले एवं देश के संविधान का निर्माण करने वाले हमारे पूज्य नेताओं ने देश के भूतपूर्व नरेशों के साथ समझौता किया, उनकी रियासतों को भारत अधिराज्य में विलय करके उन्हें प्रिवी पर्स देते रहने का वचन दिया, अपने वचन को समझौते का रूप दिया और उसे संविधान का संरक्षण प्रदान किया। इसलिए नरेशों के साथ किये गए ये समझौते कागज के टुकड़े नहीं, पावन

प्रतिष्ठा पत्र हैं जिनमें एक दो की नहीं अपितु पचास करोड़ भारतीयों की वाणी प्रतिध्वनित है, जिनके भग होने से एक दो की नहीं बल्कि पचास करोड़ भारतीयों की प्रतिष्ठा धूल में मिलती है।

प्रिबी पसों के उ मूलन से न ता समाजवाद आता है और न आय वषम्य मिटता है हाँ, वचन निर्वाह के लिए विश्व प्रसिद्ध भारत के मस्तक पर कलक का अमिट धब्बा अवश्य लगता है। ठीक है कि संविधान में छोटे मोटे परिवर्तन संशोधन करने का संसद को अधिकार है किंतु क्या पचास करोड़ जनसंख्या वाले विशाल क्षेत्रीय एवं विश्व सम्मानित भारत की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का भी संसद को अधिकार है? यह अधिकार संसद को नहीं है यह तो संसद में बड़े तथाकथित समाजवादियों का अपने मतदाताओं के साथ विश्वासघात है, यह तो मुट्ठी भर लोगों का पचास करोड़ लोगों की प्रतिष्ठा से खेलना है यह तो महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल की आत्माओं को बलेश पहुँचाना है।

हमारे को प्रिबी पस छ द करने का कुविचार नतिकता का हमन है भारत की धर्मप्राणता की हत्या है देशवासियों के साथ विश्वासघात है।

चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी

मूर्ख गुड की डली न दे, भेली दे

किये हुए अनुबंध को ईमानदारी के साथ पूरा करना केवल सद्नीति ही नहीं है अपितु नतिकता की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है और यदि अनुबंध किसी सरकार ने किया हा और वह भी काफी सोच विचार के बाद तब ता हमका पूरा करना और भी जरूरी है। हाँ सरकार भी वह जिसने वाणिज्य एवं व्यापार में भाग लेना शुरू कर दिया हो तो उसने लिए अपने अनुबंधों का पूरा करना अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख की बनाए रखने की दृष्टि से भी अनिवार्य है। और यदि उस सरकार का राजकीय विह सत्यमव जयत हा ता हमके लिए तो मन से वचन में कम से सत्य का पालन करना अनिवार्य है। क्योंकि यह केवल उसकी अपना प्रतिष्ठा का ही प्रश्न नहीं है अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्राण जाहू बरू बचनु न जाई आपन वाक्य का पालन करने वाले धर्मप्राण भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

जब मोगिया ने गद्दताक से दयावान् होने के लिए कहा तो उसने पूछा, क्यों? मुझे दयावान् होना क्यों जरूरी है? तब हमारे लिए ही अग्न वचन

का पालन करना क्यों जरूरी है ? किन्तु जो प्रश्न शाइलॉक ने किया, वह कोई सरकार नहीं कर सकती । वह केवल संविधान के अनुसार ही आवश्यक नहीं हैं कि सरकार अपनी कथनी और करनी में सत्य का पालन करे अपितु यह तो हमारी परम्परागत निधि है, हमारी संस्कृति का मूल है । श्री के० सन्तानम ने गांधीजी का उदाहरण ठीक ही उद्धृत किया है । भारत ने विभाजन के समय पाकिस्तान को पचपन करोड़ रुपये का वचन दिया था किन्तु सरदार वल्लभभाई इस राशि को देने के पक्ष में नहीं थे । सरदार पटेल का तर्क अपनी जगह बड़ा अकाट्य था कि पाकिस्तान इस धन से अपनी सैनिक शक्ति दृढ़ करेगा और बाद में भारत के लिए मुसीबत बन जाएगा । किन्तु गांधी जी पर राष्ट्रीय सुरक्षा-विषयक इस तर्क का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि यह 'सत्य' के विरुद्ध था । वचन देकर मुकर जाना गांधीजी को असह्य था, इसलिए उन्होंने यह धन दिलवा कर छोड़ा । उस समय लोग गांधीजी की इस बात से सहमत नहीं हुए किन्तु बाद में उन्हें इस घटना के ऐतिहासिक महत्त्व को स्वीकार करना पड़ा ।

ईमानदारी सदा लाभकारी सिद्ध होती है । हो सकता है कि ईमानदारी का फल तुरन्त न मिले किन्तु इसका फल मिलता जरूर है और मोठा फल मिलता है । भारत इतनी विशाल और दीर्घकालिक योजनाएँ तैयार कर रहा है, इसलिए उसके लिए तो ईमानदारी का व्यवहार करना और भी जरूरी है । यदि अपने दिये गए वचन या किये गए अनुबन्ध को पूरा करने में राजकोष पर कुछ खर्चा भी पड़े, तब भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए । या यह केवल समाजवाद के प्रति हमारा प्रेम है ? किन्तु जिस समाजवाद की नींव चायदो और अनुबन्धों के खून पर रखी जाएगी, वह समाजवाद भी अधिक दिन नहीं टिक पाएगा । सरकार के बदनीयत होते ही सारा राष्ट्र बदनीयत हो जाता है और लोकतन्त्र की नींव खुद जाती है ।

जब मैं भूतपूर्व शासकों की वकालत करता हूँ तो कुछ लोग मुझे प्रतिक्रियावादी कह सकते हैं किन्तु किसी शोषित की वकालत करना चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो या भूतपूर्व शासक हो, प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति नहीं है । यह तो एक उदार सघर्ष है और इसके लिए काफी साहस की आवश्यकता होती है । किसी स्थान पर गांधीजी ने घनिकों को अच्छत बताते हुए कहा है कि उनकी वकालत करना तथा समाज में उनको ठीक स्थान दिलाना कर्त्तव्य है । भीड़ को खुश करना कोई सरल काम नहीं है किन्तु अपने धर्म का पालन

प्रतिष्ठा पत्र हैं जिनमें एक ढो की नहीं अपितु पचास करोड़ भारतीयों की पाणी प्रतिष्पन्नित है जिनके भग होने से एक ढो की नहीं बल्कि पचास करोड़ भारतीयों की प्रतिष्ठा धूल में मिलती है ।

प्रिबी पर्सों के उ मूलन से न तो समाजवाद आता है और न आम वषम्य मिटता है हाँ, वचन निर्वाह के लिए विश्व प्रसिद्ध भारत के मस्तक पर कलक का अमिट घंटा अवश्य लगता है । ठीक है कि संविधान में छोटे मोटे परिवर्तन संशोधन करने का संसद को अधिकार है किंतु क्या पचास करोड़ जनसंख्या वाले विंगल क्षेत्रीय एवं विश्व सम्मानित भारत की प्रतिष्ठा की धूल में मिलाने का भी संसद को अधिकार है ? यह अधिकार संसद का नहीं है, यह तो संसद में बैठे तथाकथित समाजवादियों का अपने मतदाताओं के साथ विश्वासघात है, यह तो मुट्ठी भर लोगों का पचास करोड़ लोगों की प्रतिष्ठा से खेलना है यह तो महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल की आत्माओं को बलेग पहुँचाना है ।

भरपूर के प्रिबी पस बंद करने का कुविचार नतिजता का हनन है भारत की धमप्राणता की हत्या है, देशवासियों के साथ विश्वासघात है ।



चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी

भूख गुड की डली न दे, भेली दे

किये हुए अनुबंध को ईमानदारी के साथ पूरा करना केवल सद्नीति ही नहीं है अपितु नतिजता की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है और यदि अनुबंध किसी सरकार ने किया हो और वह भी काफी सोच विचार के बाद तब ता उसका पूरा करना और भी जरूरी है । हाँ सरकार भी वह जिसने वाणिज्य एवं व्यापार में भाग लेना शुरू कर दिया हो तो उसने लिए अपने अनुबंध को पूरा करना अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख को बनाए रखने की दृष्टि से भी अनिवार्य है । और यदि उस सरकार का राजकीय चिह्न सत्यमेव जयते हा तो उसने लिए तो मन से वचन से कम से सत्य का पालन करना अनिवार्य है क्योंकि यह केवल उसका अपना प्रतिष्ठा का ही प्रश्न नहीं है अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रश्न है प्राण जाहू बर वचन न जाई आप्न वाक्य का पालन करने वाले धमप्राण भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न है ।

जब पाणिपा ने गाइलाक से दयावान् होने के लिए कहा ता उसने पूछा क्या ? मुझे दयावान् होना क्या जरूरी है ? तब हमारे लिए ही अपने वचन

करना और भी कठिन काम है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय हत्याति एवं अपनी साख को ध्यान में रखते हुए अपने वचन का पालन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र में आग बल्ले की दृष्टि से यह बहुत ज्यादा जरूरी है। भूतपूर्व ग्रासक एवं उनके वंशज अपने अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। वाणिज्य एवं राजनीति के क्षेत्रों में जिस योग्यता की अपेक्षा है उनमें वह मौजूद हैं। प्रिंसीपस बढ़ कर देने से वे भूले नहीं मर जाएंगे। जनसाधारण में आज भी उनकी साख है, उनकी प्रतिष्ठा है और जितनी अधिक है जितनी कि सत्ताह्वित कांग्रेसियों को न कभी मिली है और न कभी मिल सकेगी। प्रिंसीपस बढ़ कर देने की धमकी पराजित कांग्रेसियों को दूषित मनोवृत्ति की परिचायिका है। उनका विचार है कि प्रिंसीपस बढ़ कर देने से भूतपूर्व राजा महाराजाओं का लोकप्रियता घट जाएगी किंतु इनको जिस बात का पता नहीं वह यह है कि इनका स्वयं का प्रभाव उल्टा पड़ेगा और स्वयं इन लोगों की लोकप्रियता कम हो जाएगी।

संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की धारा थी वहैपालाल माणिक लाला मुंशी ने रखवाई थी। उनका विचार था कि इस प्रकार वह स्वयं कांग्रेसियों की सेवा कर रहे थे। यदि वे मूल अधिकार संविधान में न लिख गए होते तो सर्वोच्च न्यायालय इनकी सब रूपेण रक्षा कर सकता था। किंतु इनका संविधान में लिखा जाना (यद्यपि स्वेच्छा से यह कदम उठाया गया था) आज नागरिकों के निये एक अभिशाप बन गया है क्योंकि सत्तह्वित तरह-तरह के परिवर्तन करना अपना अधिकार समझती है और इस तथा कथित अधिकार का दुरुपयोग करती रहती है। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की धारा रखवाते समय श्री मुंशी ने इस बात की परंपना भी नहीं की थी। वास्तव में यह सब कुछ उनका इच्छा के विरुद्ध एवं प्रतिद्वन्द्व है। इसी प्रकार जब भूतपूर्व ग्रासकों से सरदार प्रहलभ भाई पटेल ने अनुबंध किया था और उनकी रिपासों के बदले में प्रिंसीपस एवं कुछ विशेष अधिकार देने का वचन दिया था, तो उनकी इच्छा अपने वचन या अनुबंध की प्रमाण होते देखने की नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस बात को भी संविधान में सम्मिलित कर दिया था जिसमें सम्मोचन करने के बहाने प्राण काप्रसी अपनी ईर्ष्या एवं दुबुद्धि की साकार कर रहे हैं। यदि यह अनुबंध संविधान में सम्मिलित न किया जाकर पृथक् से सविनय अनुबंध पत्र के रूप में होता तो आज सर्वोच्च न्यायालय भूतपूर्व ग्रासकों की आर सत्ता है और उनका

अधिकारो की रक्षा करता। यद्यपि सरदार पटेल का दृष्टिकोण इस अनुबन्ध को दुगुनी सुरक्षा प्रदान करने का था और इसलिए उन्होंने उसे संविधान में शामिल किया था, किन्तु वर्तमान कांग्रेसी स्वार्थान्ध एवं ईर्ष्यान्ध होने के कारण उस अनुबन्ध की पावनता को भग करने पर तुले हुए हैं।



श्री एस० आर० पटेल

मन्त्री प्रबन्ध उद्यम मंच

प्रवीणों और शाही विशेषाधिकारो को अन्त में समाप्त कर देने के प्रस्ताव ने काफी गर्मी पैदा कर दी है।

शाही विशेषाधिकारो को खत्म करना कठिन है। राजे-महाराजे उनका उपयोग सरकार के साथ एक पवित्र समझौते के परिणामस्वरूप करते हैं। इसके विपरीत ऐसे अनेक राजनीतिज्ञ हैं जो इस प्रकार के विशेषाधिकारो अथवा सुविधाओ का उपयोग बिना किसी आधार के किये जाते हैं।

उदाहरण के तौर पर जिस मन्त्री-महोदय ने दस लक्षीय कार्यक्रम को अपनाने के लिए जोरदार दलीले दी थी यदि उन्होंने उनकी वजाय यह प्रस्तावित किया होता कि मंत्रियो, ससद्-सदस्यो और विधान सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारो और सुविधाओ को रद्द कर दिया जाए तो जनता उनकी आभारी होती और लोगो को उनकी दलीले पसन्द आती। एक केन्द्रीय मन्त्री को केवल 2250 रुपये माहवार मिलते हैं लेकिन उन्हें लगभग 4,000 रुपये के मूल्य की मुफ्त बिजली पानी की विशेष सुविधाएँ मिलती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनका कर-दायित्व और वार्षिकी-जमा में रकम भरने की मात्रा में कमी होना। वास्तव में उचित बात तो यह होती कि मंत्रियो को 80,00 से 10000 रुपये माहवार तक का वेतन दिया जाए लेकिन कोई चीज मुफ्त नहीं। आमदना पर उनको अपने कर देने चाहिए और सामान्य नागरिको की तरह उनको भी प्रत्येक वस्तु के लिए बाजार की कीमतें चुकानी चाहिए।

ससद् और विधान सभा के सदस्यों को भी अनेक प्रकार की विशेष सुविधाएँ और विशेषाधिकार प्राप्त हैं जिन्हें तत्काल खत्म कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक संसद्-सदस्य केवल एक बार हाजिरी-रजिस्टर में दस्तखत कर 31 रुपये प्रतिदिन की दर से 15 दिन की रकम वसूल कर सकता है, भले ही वह 14 दिन ससद् में मौजूद न रहे।

को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया यो न्यायाधीश महोदय ने उसके दण्ड की घोषणा के पहले उसकी मर्त्यता करते हुए कहा . 'जो तुम पर विश्वास करता है, उसे छलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती।' अपराधी ने उत्तर दिया : 'न्यायाधीश महोदय ! यदि मैं विश्वास करने वाले को न छलूँ, तो मेरी छली में और कौन आएगा ?'

नरेशो ने सरदार वल्लभभाई पटेल पर विश्वास किया और अपनी रियासते उनके हवाले कर दी । सरदार पटेल ने अपने अन्तिम क्षण तक उस विश्वास की रक्षा की । कुछ लोगो ने उन पर जोर दिया कि वह नरेशो के साथ विश्वासघात कर दे और उनको दिया वचन पूरा न करे किन्तु सरदार पटेल ने उनका डाँट कर चुप करा दिया । सरदार पटेल तो इन असत्यमार्गियों के वहकाने में नहीं आए किन्तु उत्तराधिकारी आज इस वहकावे में आ गए हैं । उनका विचार है कि अब कोई उनके सिर पर तो वचा नहीं, इसलिये वह अपनी मनमानी करने के लिये स्वतन्त्र है और ससद् की आड में अपने पर विश्वास करने वालो के साथ ठगी कर सकते हैं । शायद उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके इस दुष्कर्म को विश्व के अन्य देश तो देखेंगे और उनका क्या विचार है कि इस दुर्घटना के बाद से भारत के वचनों पर एक क्षण के लिए भी विश्वास करेंगे । क्या यह दण्ड कम है कि अन्य देश भारत की किसी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार न हो । विश्व में भारतवर्ष की साख मिट जाना उसके लिए बहुत बड़ा दण्ड है ।

°

°

°

यदि भारत सरकार नरेशो के साथ किये गये समझौतो के फलस्वरूप उनको मिलने वाले प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारो को संविधान में संशोधन करके समाप्त कर देती है तो उसके इस कदम से श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री वल्लभभाई पटेल का और मेरा अपमान होता है दूसरे शब्दों में, हम तीनों के नाम पर कलक लगता है ।

यदि एक देश की सरकार कुछ पैसे वचाने के लिये अपनी ससद् में दो तिहाई बहुमत से अपने संविधान में संशोधन करने से नहीं हिचकिचाती, तो आप ननिक कल्पना कीजिये कि फिर कौन व्यक्ति या देश उस सरकार का, उस ससद् का या देश का विश्वास करने को तैयार होगा ! और यह राशि भी कोई दान-स्वरूप दी जाने वाली राशि नहीं अपितु वह पवित्र राशि है जो

भी था कि शासन के नेपथ्य में वे अपने राज्यतंत्र का पूरा उपभोग करते रहेंगे। लाड माउंट बैटन ने अपने वक्तव्य में, जिसका कि यहाँ तदनुसार लिया जा चुका है स्पष्ट किया कि यह समझ लिया जाता है कि किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं डाला जाये और उनके आंतरिक राज्यतंत्र या प्रभुत्व पर अतिक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है और उन्हें सही सविधान मानने को भी बाध्य नहीं किया जायगा।

शक्ति का कोई लाभ नहीं

इस प्रकार (स्मरण पत्र के अनुसार) नरेंगों पर अपनी रियासतों को भारतीय सभ में मिलाने के लिए कोई नबाब नहीं था। यह रियासत सभा सभ में समझ लिया था कि उस स्थिति में किसी शक्ति का प्रयोग करने का परिणाम गम्भीर होते। नरेंगों ने यदि स्वयं को एकीकरण से अलग रखा होता तो वे काफी सहाय्य में राजकीय कर्मचारी बनाये रहते और अपनी रियासत में राजस्व का बिना किसी राज टाक के उपभोग करने जैसा कि वे बराबर करते रहे थे।

इसलिए हम से कम जो रियासत सभा में नरेंगों का दे सकता था, वह मनुष्य के क्षेत्र में नरेंगों के समाज का मान्यता और स्पष्ट रूप से सामित राज्य कर्मचारी और उचित आधार पर कुछ विषय व्यक्तिगत विशेषाधिकार थे कि नरेंगों ने अपने समस्त शासनाधिकारों को त्याग कर वे अपना रियासतों के विलीनीकरण को स्वीकार करके अपने वक्तव्य का पूरा कर लिया है इसलिए इन समझौतों के अंतर्गत लिए गये विशेषाधिकारों के आवासनों को पूरा करने की गारंटी देना भारत सरकार का कर्तव्य है। सविधान समझौतों के अनुसार विशेषाधिकार सब प्रकार के आय करों से मुक्त थे कि नरेंग अपने क्षेत्रों में संपूर्ण प्रमुख सम्पत्ति के इसी लिए उन्हें समस्त आय करों से मुक्त रखा गया।

अक्टूबर 1949 में भारतीय पत्रों ने सविधान सभा में रियासत सभा सभ का स्थिति का स्पष्ट करते हुए स्मरण पत्र में लिखी बातों का पुष्टि की — विशेषाधिकार समझौता नरेंगों द्वारा दिये जाने वाले व्यय को, जो कि वे पहले करते रहे हैं घटाकर कम से कम एक चौपाई कर देगा। किन्तु आर्थिक और राजनैतिक कारणों से अधिक उद्देश्य समझौते के राजनैतिक और नैतिक रूप पर ही अधिक बल दिया मानव स्मृति निबन्ध है।

अक्टूबर 1949 में गायद हम इस समस्या की उस भयंकरता एवं गम्भीरता को भूल गए हैं जो अगस्त 1947 में हमारे सामने थी ।'

मार्वाभौम सत्ता की समाप्ति पर हमें अपनी स्वाधीनता प्राप्ति के समय अंग्रेजों के साथ हुए समझौते के भाग को भी स्वीकार करना ही था । इस-लिये प्रवीपर्स समझौते तो शासकों को उनके सत्ता त्याग एवं अपनी रियासतों को विलय कराने की क्षत-पूति के रूप में हैं । सरदार पटेल ने कहा :

“इस पर हमें कुर्तक करने की विल्कुल आवश्यकता नहीं है—मैंने जान बूझ कर थोड़े मूल्य का प्रयोग किया है जो कि हमने उस स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए चुकाया है जिसने लाखों लोगों के भाग्य को प्रभावित किया है ?”

उन्होंने सविधान सभा को बतलाया कि रियासत मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सशोधनों का, मैमूर, सीराष्ट्र, ट्रावन्कोर और कोचीन सभ की विधान बनाने वाली सभाओं ने परीक्षण कर लिया है । इन सभाओं द्वारा प्रस्तावित कुछ रूपान्तरों को इन सशोधनों में सम्मिलित कर लिया गया है, कुछ को इन विधान सभाओं के प्रतिनिधियों से तर्क करके समाप्त कर दिया गया है । दूसरी रियासतों और रियासतों के सभों के प्रतिनिधियों द्वारा लोगों की इच्छाओं और विधि को उसी तरह स्वीकार करना सम्भव नहीं था ।

ये रियासतों में उचित रूप से बनी हुई व्यवस्थापक सभाएँ नहीं थी, और न उनमें, भारतीय सविधान में अंतिम रूप से विलय होने से पूर्व, व्यवस्थापक सभाओं का बनाया जाना ही सम्भव था ।' इसलिये इन रियासतों में वहाँ के शासक, राज प्रमुख की अनुमति लेकर सविधान लागू करने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं था ।

सविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में, सविधान ग्रहण करने से पहले 26 नवम्बर 1949 को सरदार पटेल ने रियासतों की ओर से घोषणा की —

“सम्माननीय सदस्यों को याद होगा, 12 अक्टूबर को मैंने अपने वक्तव्य में नये सविधान के अन्तर्गत रियासत मंत्रालय की स्थिति को इस सदन के सामने पूर्ण रूप से स्पष्ट किया था । रियासतों के द्वारा सविधान की स्वीकृति की विधि पर जो हमने विचार किया है वह मैं सम्मानित सदस्यों को बतला दूँ । मैं सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्न हूँ, कि

य समस्त 9 रियासतें जो सविधान की पट्टी सूची के विभाग में विनिष्ट रूप से दी गई हैं उस होने हैदराबाद रियासत के सहित उस सविधान का जिस कि हम प्रहरण करने जा रहे हैं उसी तरह स्वीकार करने के लिए प्रस्तावित कर दिया है जसा कि मैंने अपने वक्तव्य में 12 जनवरी का बताया था ।”

पटेल की अतुष्टि

रियासत मन्त्रालय के सचिव श्री बी० पी० मनन और सविधान सभा के मुख्य प्रारूप लेखक (चीफ ड्राफ्ट्स मैन) श्री एस० एन० मुकर्जी के बीच जिस तरह 1949 में लगाने हुए पत्र-व्यवहार में यह स्पष्ट है—कि सविधान सभा के अंतिम अधिवेशन के बाद ही सविधान का रियासत सम्बन्धी ६ राज्यों का अन्त्य गये अन्तिम रूप में सरदार पटेल की तरफ से अनुष्ठित नहीं थे । श्री मुकर्जी ने अपने उत्तर में धारा 363 के सम्बन्ध में रियासत मन्त्रालय की कुछ उल्टी समझ का निर्देष्ट किया मन्त्रालय ने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है जिन में मुख्य आकृति यह थी (1) प्रिवीपस की धन राशि को चुकाने की सवधानात्मक गारंटी और उनकी आमदनी से मुक्ति । (2) सविधान सभा की योजना के अन्तर्गत प्रसविदाओं और समझौता का कोई धारा “यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहे किन्तु इसका माध्यम ही ऐसी प्रसविदाओं और समझौतों के लिये भारत सरकार द्वारा लिये गये कचन का सवधानात्मक माध्यम दी जाय ।

श्री मुकर्जी ने कहा,

जहां तक (1) का सम्बन्ध है धारा 291 के अन्तर्गत इसका विधान स्पष्ट बनाया गया है और असद्विषय रूप से प्रिवीपस की धन राशि का भारत सरकार की सम्पत्ति निधि पर केवल अधिकार ही नहीं है बल्कि इस राशि का भुगतान भी इसी निधि से किया जायेगा । इसी धारा में आगे यह भी दिया गया है कि यह धन राशि सभी प्रकार के आधिकार से मुक्त रहेगा । धारा 363 किसी तरह भी धारा 291 में दी गई गारंटी और सवधानात्मक कचन को समाप्त नहीं कर सकती । धारा 362 और 363 के अन्तर्गत (2) के भाग की धारा को पूरा करती है । पहली नज़रों के अधिकारों के विनियामक इत्यादि की स्पष्ट सवधानात्मक माध्यम प्रदान करता है और दूसरी समझौता और प्रसविदाओं इत्यादि की धाराओं को “यायालय के अधिकार क्षेत्र में बाहर

रखती है। निसदेह धारा 363 अधिकार के विषय में उठे किसी विवाद या किसी उत्तरदायित्व या वचन या सविधान की किसी सधि, समझौते प्रसविदाओं इत्यादि से सम्बन्धित उठे विवादों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगाती है, किन्तु धारा के प्रारम्भिक भाग में जो कुछ दिया गया है उसके लिये यह स्पष्ट रूप से एक आवश्यक उप सिद्धांत है।

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर

प्रिवीपर्सों के सम्बन्ध में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगाने के तर्क का पक्ष श्री मैनेन को दिलाया गया था जो कि रियासत मन्त्रालय द्वारा इन शब्दों में बताया गया था, “यदि इन समझौतों को न्यायालय में ले जाने की छूट दे दी गई तो यह निरर्थक ही दुखी होने का कारण बन जायगा।”

एक अन्तिम प्रकरण में श्री मुकर्जी ने कहा —

“प्रारूप लेखन समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) को अब सविधान के विधानों से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। सविधान के किसी विधान के सम्बन्ध में सदेह का सही विश्लेषण अब अधिकार पूर्वक केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निश्चित किया जा सकता है। हम यह नहीं समझते कि किसी का भी सविधान के किसी विशेष विधान के सम्बन्ध में उसके सही अर्थ का अनुमान लगाने या क्षेत्र के विषय में दुखी होना उचित है। डाक्टर अम्बेडकर की राय में साधारणतः सविधान की किसी धारा में सशोधन करने का प्रस्ताव तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि न्यायालय में उचित रूप में इस पर विवाद न हो चुके और सर्वोच्च न्यायालय को इसका विश्लेषण करने का सुअवसर न प्राप्त हो जाये।”

यह बताना लाभदायक होगा कि सन 1937 में उसके दो वर्ष बाद तक वामपक्षीकांग्रेसी नेताओं ने नरेशों के राज्यतंत्र के विषय में अपने असहमति निर्देशों से नरेशों को मुस्लिम-लीग की गोद में जाने को विवश कर दिया था। किन्तु कम से कम यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस उस समय रियासतों में कुछ सुधारों और जन प्रतिनिधियों की मांग कर रही थी किन्तु उसमें उनके (रियासतों) मध्य में सम्मिलित होने की गति भी उस मांग के साथ थी। प्रजातंत्र के मोर्चे को सुदृढ़ बनाने के लिए यह एक उचित और सराहनीय मांग थी।

जस वय वा सरदार पटेल ने नरेगा की इच्छा और राय से एक रक्तहीन प्राप्ति" लाने के बदले में 'चोड़ा सा मूल्य' देकर वही उससे महान उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। समझौते के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित जिस परित्याग का नरेगा से प्रस्ताव किया गया था उसके लिए केवल सरदार पटेल ही नहीं पूर्ण सविधान सभा एक पक्ष के रूप में थी उसके नियमित वाक्पत्र के अनुसार जो नरेगा के विरुद्ध 3॥ वष पहले बनाया गया था, पुनः मोल भाव करने का कोई कारण नहीं है।

श्री मुरारजी आर देसाई

उपप्रधान मंत्री माननीय श्री मुंगर जी आर० देसाई ने पटेल स्मारक व्याख्यान माला के अंतर्गत 18 दिसम्बर सन् 1963 में ही प्रिन्सिपल एव विनोदाधिकारी के विरोधियों को मुंह तोड़ उत्तर दत्त हुए गताश्रया से प्रतीत भारतीय एकता का अपना शासन में कितना सजीव चित्रण किया है (यह व्याख्यान आकाशवाणी नई दिल्ली से प्रसारित भी किया गया था।)

"किन्तु अगल दिसम्बर में क्या हुआ जबकि उन्होंने उड़ीसा और छत्तीस गढ़ की छोटी रियासतों को मिला कर एक कर दिया तो हम स्वयं रह गए। हममें सन्देह नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से हुए परिवर्तन से प्रभावित होकर नन रियासतों की स्थिति हमारे पक्ष में हो गई थी और आगाम्य व सान्नाय पूर्व कालीन ब्रिटिश भारत में दली रियासतों की सीमाएं पार कर गईं थी। इन रियासतों के पासको ने जिन्हें ब्रिटिश सत्ता के भीतर काफी अधिकार प्राप्त थे, उस परिवर्तन के प्रभाव को अनुभव करना आरम्भ कर लिया था। किन्तु उनमें से यह अनुमान किसा को नहीं था कि १6000 वर्ष भीत में पला 70 लाख जनसंख्या वाली और 2 करोड़ के राजस्व वाली उड़ीसा और छत्तीस गढ़ की 39 रियासतों का जिन के भीतर ही उड़ीसा और मध्य प्रांत के आसन्न क्षेत्र में विनश्य हो जाएगी। इस उद्देश्य के उपरांत पहली बार सरदार पटेल ने अपनी रियासत विपक्ष नीति की शुरुआत की। 16 दिसम्बर 1947 का दिल्ली नोटन पर उन्होंने कहा यह बात हर किसी को स्पष्ट हो गयी होगी कि बाइस या त्रिकुतन अथवा लोकतान्त्रिक संस्था तभी कुशलता पूर्वक अपना काम कर सकती है जबकि उस इकाई का जिसमें वह समाविष्ट

है, अस्तित्व समयक रूप से स्वायत्तता सम्पन्न हो। यदि कोई रियासत चाहे अपने छोटे आकार के कारण, चाहे अपनी पृथक स्थिति के कारण चाहे अपन पड़ोसी स्वायत्त क्षेत्र से विभिन्न सम्बन्ध होने के कारण चाहे अपेक्षित साधनों के अभाव में अपनी आर्थिक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग न कर पाने के कारण चाहे अपने निवासियों के पिछड़ेपन के कारण और चाहे स्व-प्रशासन के उत्तरदायित्वों को निभाने की अपनी असमर्थता के कारण, वर्तमान शासन व्यवस्था को अपनाने में समर्थ नहीं हो पाती है तो उसका लोकतन्त्रीकरण और सविलयन करना अनिवार्य हो जाता है।”

एकीकरण का आरम्भ बड़े अच्छे ढंग से हो चुका था और शताब्दियों से चनी आने वाली दो ऐतिहासिक असंगतताओं को देश के पिछड़े से पिछड़े भागों से हटा दिया गया था। इन क्षेत्रों में उत्पन्न की गई चिनगारी शीघ्र ही लपट का रूप ले गई। एकीकरण की ज्योति (मशाल) जो सरदार लेकर चले थे उसने अपना मार्ग शीघ्र ही दक्षिण की रियासतों, कोल्हापुर, गुजरात, पंजाब की व देश की अन्य छोटी-छोटी रियासतों में पा लिया, किन्तु उस सम्बन्ध में सरदार को सबसे बड़ी सफलता मिली काठियावाड़ में, जिसके विलय का उन्होंने गाँधी जी को वचन दिया था और जिसे गाँधी जी को अपने जीवन काल में ही पूर्ण होते देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। 449 इकाइयों वाली 220 रियासतों ने बहुत से छितरे हुए द्वीपों और राज्यों ने काठियावाड़ के मानचित्र को 860 भागों में विभक्त कर रखा था। सरदार इस कार्य की सिद्धि के लिये उत्सुक थे, किन्तु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मतभेदों के कारण सरदार ने सरकार से त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया था, इसलिए उन्होंने बम्बई और अहमदाबाद जाने का निश्चय किया जिससे कि वह काय क्षेत्र के समीप रह सके, और उन्होंने श्री० बी० पी० मैनन और उनके साथी अफसरों को राजाओं से बातचीत करने के लिये काठियावाड़ भेजा। जनवरी 1941 में अहमदाबाद में श्री बी० पी० मैनन ने, काठियावाड़ को एक संयुक्त रियासत बनाने के लिये राजाओं की सम्मति की, सूचना उन्हें दी। मैंने सरदार के चेहरे पर कीर्ति और उनकी अपनी जन्म भूमि पर कार्य सिद्धि का ज्ञान देखा।

छोटी रियासतों का वास्तविक रूप से एकीकरण पूर्ण हो जाने के बाद सरदार ने अपना ध्यान कुछ कमी वेशी के साथ, काठियावाड़ के नमूने पर, बड़ी रियासतों की समस्या की ओर लगाया। मार्च 1948 में 'कीरेनरी

घोम्बोसिस' (जंग में रुधिर जम जाना) व आक्रमण के कारण, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण बीमारी से प्रगति किसी सीमा तक रुक गई। बावजूद इसके, बीमार दगा में भी उनके नेतृत्व में या बाद में दे-रादून में धीरे धीरे स्वस्थ होने पर हिमाचल प्रदेश, विध्य प्रदेश पेशू मध्यभारत और राजस्थान की रियासतों तक, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतों व अतिरिक्त राजाओं से बड़ी चतुराई के साथ बातचीत होने पर प्रगति फल चुकी थी। एकीकरण का यह तरीका छत्तीसगढ़ और पूर्वी रियासतों के अनुरूप ही था। छोटी रियासतों का एक सघ बना कर पड़ोस की बड़ी रियासत के साथ मिला दिया गया था। इस प्रकार विध्य प्रदेश का केन्द्र रोवा था, पेशू का केन्द्र पटियाणा था मध्य भारत की रियासतों के सघ में खालियार व इन्दौर बड़ी रियासतें थी, और राजस्थान की संयुक्त रियासतों का केन्द्र उदयपुर था। एकीकरण का केन्द्र बड़ी रियासतों के बीच में बनाना एक चतुराई का काम था कि इसने भारतीय रियासतों और प्रांतों के बीच में एक रफ्तार के प्रबंध का दृढ़ कर दिया और उसी समय शीघ्रता से उसी तरह की उपमा जय छोटी रियासतों की पूरक स्थितियां में कमी कर दी। इन सघों के नेता शासकों को बना कर, सरदार ने अपन 16 दिसम्बर 1947 के वक्त में का रचनात्मक प्रमाण दिया जिसमें उन्होंने अपने इस विश्वास को स्पष्ट किया था कि 'मरेणों का अभिप्राय उनकी अपनी जातों और देश की सेवा में निहित है न कि उनके राजस्व को हड़ता पूरक जारी रखने में।'

एकीकरण के तरीके ने रियासतों में उत्तरदायी सरकारों की सीमाओं में बढ़ा दी। उससे राजनयिक दत्ता की कमिफ उन्नति और बड़ी रियासतों में उत्तरदायी सरकार बनने में प्रगति हुई और जिसका उपयोग छोटी रियासतों में लोकतन्त्र की उन्नति करने में किया गया। सरदार के पयास केवल एकीकरण तक ही सीमित नहीं थे। वह जय तबहीं धनर से सविधान में यह उत्तरदायी सरकार की ओर शीघ्रता से बढ़ और उद्धान रणा की गतिमान पद्धति स्थापित की जिसमें कि अधिक परिपक्व और उन्नतिमान प्रजातन्त्र भारतीय प्रांतों में विकसित हुआ और केन्द्र का इन नई इकाइयों में प्रजातन्त्र का पनपान का सहारा मिला। इन इकाइयों और पुराने प्रांतों के बीच में एक समाहित गतिमान पद्धति शीघ्रता से आरम्भ की गई।

यह एक आश्चर्य की बात है कि सरदार का मस्तिष्क जितनी तेजी से एकीकरण के अंतिम चित्र की ओर पहुँच रहा था। यद्यपि वे धीरे धीरे

प्रगति का प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु चल तेजी से चल रहे थे। छोटी रियासतों के प्रान्तों में विलयन के साथ ही छोटी रियासतों का विलयन बड़ी रियासतों में कराने की ओर उन्होंने एक वर्ष से कम समय में ही प्रगति कर ली थी। उन्होंने तेजी से एक रूपता, एकता और प्रजातन्त्रीय मार्ग पर चलना आरम्भ कर दिया था। जबकि यह पद्धति जारी थी तब भी उन्होंने इन छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में, भारतीय संघ में लगभग प्रांतों की पद्धति पर, बढ़ाने के लिये सोचना आरम्भ कर दिया था।

तो भी भारतीय एकता के लिये, कश्मीर और हैदराबाद, दो रुकावटें अब भी थीं। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान अपने नए रूप में, पूरी शक्ति के साथ कश्मीर पर आक्रमण की पहल कर चुका था। तब रियासत भारत में मिल गई और हम उसकी रक्षा के लिये दौड़े। इस प्रकार हड़ता से चुनौती का सामना करना पड़ा किन्तु रियासत का एक बड़ा भाग पाकिस्तान के हाथों में पड़ गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने झगड़े को रोक दिया। तब भी इसके भारत में मिल जाने के बाद रियासत ने सवैधानिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक रूप से उत्तम प्रगति की है। आज इसने भारतीय संघ के स्वाभाविक तत्वों के बीच में अपना उचित और सम्मानीय स्थान प्राप्त कर लिया है।-

हैदराबाद की रियासत तब भी एक विशेष श्रेणी की थी। यद्यपि यह विधिवत् पाकिस्तान में नहीं मिल पाई थी, इसमें कोई सदेह नहीं कि रियासत के कुछ विशेष तत्वों और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ तक कि प्रशासन के अधिकारियों तक में, कुछ भावनात्मक एवं धार्मिक कड़ी थी। वास्तव में, इसमें सदेह भी नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान भारत के विपक्ष में अपनी स्थिति के लिये पड़पंथ रच रहा था। एक युद्ध प्रिय साम्प्रदायिक संस्था, निश्चल शान्ति की हँसी केवल रियासत में ही नहीं बल्कि उसकी सीमाओं पर भी उड़ा रही थी। सुविधाएँ, प्रोत्साहन, एवं धानि-प्रत्यायन रखने पर भी हम किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त करने में अगफल हो चुके थे। उसी समय भारत की एकता एवं सुरक्षा को, भारत के पेट के उम नामूर द्वारा दी गई धमकी, जैसा कि सरदार पटेल उसे कहा करते थे, बढ़नी जा रही थी। अन्त में, इसको शल्य क्रिया द्वारा ठीक करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रहा, - उस समय की घटनाओं ने भली भाँति परिचित होने के कारण मैं कह सकता हूँ कि उनकी। अद्वितीय शल्य क्रिया की चतुराई उनकी

दृढ़ विचार एवं भारतीय एकता के लिये उनकी एकाग्र लगन एवं निष्ठा के बिना यह चीर फाड़ सकल नहीं हो पाती और हैदराबाद को रियासत हमारे राजनतिक शरीर में बराबर पीथा दन वाली बना रहती । तब भी वह विजय प्राप्त करने पर उदार थे, इमको सबसे पहले निजाम ने स्वीकार किया होगा कि उनका (निजाम के) साथ केन्द्र उदारता का व्यवहार ही नहीं किया बल्कि सामर्थ्यानी का व्यवहार भी उस व्यक्ति (सरदार पटेल) के द्वारा हुआ जो कठोरता और सक्ति के लिये प्रसिद्ध था । मेरे विचार से हैदराबाद की समस्या का जो कि खतरे की दी गई धमकी के कारण खो हो गई थी 'पुलिस कारवाही द्वारा समाधान करना भारतीय एकता का एकीकरण करने के लिये बड़ी देन थी कम से कम इसे दूसरी रियासतों के मिलाये जाने के बराबर का दर्जा तो दिया ही जाना चाहिये ।

एक बार मैं ही हैदराबाद का प्रश्न उस ढंग से तय किया गया जिसने भारतीय एकता और सुरक्षा को सुरक्षित किया । सरदार पटेल अब व प्रश्ना का हल करने के लिये स्वतन्त्र थे, जिसकी कि उन्होंने मय सभा और अकाली बड़ी रियासतों का भारत की संवैधानिक पद्धति में मिलाने की बहुत पहले ही विशिष्ट आह्वति बना ली थी । उसका अनुसार रियासतों के सभा को, संविधान के अनुसार उन समस्त विषयों को लेकर, जिनके लिये सभा के अधिकार भारतीय प्राप्ति तक बड़ा दिया गया था भारतीय सभा में पूर्णतः मिलाने के लिये बातचीत आरम्भ की गई । नये सभों में प्रजातन्त्रीय पद्धति के साथ प्रशासनिक समस्याओं के संवैधानिक एकीकरण के बीच वाले समय के बचाव के लिये, सरदार ने जिस ढंग से राज प्रमुखा और रियासतों के जन प्रिय नेताओं को अपने अनुकूल बनाया वह कठिन सिद्ध नहीं हुआ । किन्तु आर्थिक समस्याओं ने बहुत सी कठिनाइयाँ बड़ा दीं इसके लिए विस्तार पूर्वक ध्यान देने और देख रेख करने की आवश्यकता हुई । "सब विषय एक पा" न्यायिक ऐववाहरी बमेटी" (आर्थिक अवयवण कमटी) नियुक्त की गई जिसके 'चेयरमन श्री० बी० टी० कृष्णामाचारी के जिसको रिपोर्ट मुझे पा" है यह नई सधि और रियासतों की आर्थिक समस्याओं पर एक विमल नक़्क़ प्रमाण (दस्तावेज) है । बमेटी ने निम्न विस्तृत सिद्धान्त आर्थिक एकता के लिये प्रस्तुत किया और अधिकतर इन सिद्धान्तों के अनुसार अलग अलग रियासतों में सम्बंधित प्रस्तावों को कार्यान्वित किया गया है —

सधि का आर्थिक एकीकरण प्रान्तों और रियासतों के बीच में निम्न विषयों में पूर्ण समानता पर आधारित होना चाहिये —

(1) केन्द्रीय सरकार को रियासतों में वही कार्य और अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये जो वह प्रान्तों में करती है।

(2) केन्द्रीय सरकार को प्रान्तों की भाँति ही अपने प्रशासनिक संगठनों के द्वारा ही रियासतों में भी कार्य करना चाहिये।

(3) केन्द्रीय आय व अन्य साधनों का भाग दान प्रान्तों व रियासतों से एक रूपता व समानता पर आधारित होना चाहिये।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं के विषय में, और बटने वाले संयुक्त राज्य शुल्क का भाग देने के सम्बन्ध में, आर्थिक सहायता के लिये दान, "आर्थिक सहायताओं" और दूसरे प्रकार की समस्त आर्थिक एवं तकनीकी सहायताओं के लिये प्रान्तों और सरकारों के साथ व्यवहार में समानता होनी चाहिये।

मैं रियासतों के एकीकरण को प्राप्त करने के एक दूसरे आर्थिक परिणाम, शासकों के प्रिवीपर्सों की स्वीकृति को भी बतलाना चाहता हूँ। इन भुगतानों की कुल घन राशि, जो मूल्य देश ने नरेशों द्वारा अपने प्रभुत्व और राज्याधिकारों को समर्पण करने का चुकाया, अब भारतीय सघ को लगभग 4 करोड़ रुपया देना होता है। जब हम लाभों पर ध्यान देते हैं जो कि देश को इन एकीकरणों के द्वारा प्राप्त हुये हैं और वे परिस्थितियाँ जो सन् 1947 में मौजूद थी, मैं माहस पूर्वक यह कहता हूँ कि इन समझौतों के विषय में कोई शका उठाना भी केवल अनुउदारता और सकुचित विचार ही नहीं बल्कि उन्हें अस्वीकार करना अनैतिक भी होगा। विशेष रूप से जब हम यह मानते हैं कि जिस समय ये समझौते हुये थे, उस समय दूसरा पक्ष, वर्तमान स्थिति के विरुद्ध मोल भाव करने की स्थिति में था, जब वही पक्ष वर्तमान सरकार और ससद की दया पर है। उस भाव से और उससे अधिक विकसित एकीकरण के भाव से भी, मैं सरदार पटेल के उन शब्दों में बतलाता हूँ जो कि उन्होंने नरेशों के साथ हुए समझौतों और रियासतों के एकीकरण से सम्बन्धित संविधान सभा की धारा पर बोलते हुए कहे थे। उन्होंने समझौतों को निम्न शब्दों में न्याय सगत बतलाया था—

(इससे आगे माननीय मुरारजी देसाई ने सरदार पटेल द्वारा अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में दिये गये व्याख्यान—“मानव स्मृति से लेकर .. .काफी आघात पहुँचायेगा .. .तक को उद्धृत करके आगे कहा.” (सरदार पटेल का व्याख्यान इसी पुस्तक में पृष्ठ 57 से पृष्ठ 59 तक,

द्वारा अनुन का लिए गए कम योग का तत्त्व, इन अमर पवित्रों में बद्ध कर दिया है।

हमारी सत्त्विति एक दर्शन के अनुसार अ पाप करना तो पाप है ही, अ पाप का सहन करना भी महापाप है। इसी बात का वर्तमान राष्ट्र कवि श्री रामचारी सिंह 'दिनकर' ने अपने काव्य कुछ क्षेत्र में भीष्म पितामह के मुख से कहलवाया है

छीनता हो स्वयं कोई, और तू,
त्याग तप से काम ले, यह पाप है।
पुण्य है, विच्छेदन कर देना उसे,
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो ॥

केवल इतना ही नहीं भारतीय दर्शन के अनुसार तो किसी दूसरे के प्रति अ पाप होता देखकर चुप रहने वाला भी पाप का भागी होता है। परम पूज्य राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने भी कहा है—'सच्चा अहिंसक सामाजिक अ पाप का विरोध किए बिना नहीं रह सकता।

इस अ पाप पूर्ण प्रस्ताव का विरोध करने के लिए नरेशों ने जो गति पूर्ण एक विधिमय मार्ग ग्रहण किया है वह उनके पद के प्रतिष्ठा के अनुकूल है और वास्तव में प्रसन्नोद्य भी है—

12 एवं 13 अगस्त 1967 को भारतीय नरेशों एवं उनके प्रतिनिधियों का नयी दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने इस (अराष्ट्रीय) प्रस्ताव का एक स्वर से खण्डन किया तथा इसका सक्रिय विरोध करने के लिए स्वयं को कंसल्टेशन आफ रूलर्स फार इण्डिया' (भारतीय नरेश विचार विमर्श समिति) नाम से संस्थापित किया। 15 अगस्त को नरेशों ने कंसल्टेशन आफ रूलर्स आफ इण्डियन स्टेट्स इन ककोड फार इण्डिया संस्था का गठन किया, जिसे संक्षेप में ककोड फार इण्डिया या ककोड' कहते हैं।

अंत में समिति के समस्त सदस्यों ने एक मत होकर सभा अध्यक्ष को अधिकार देकर उनसे निम्न लिखित वक्तव्य प्रकाशित करने का निवेदन किया

वक्तव्य

मह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी स्वतंत्रता की बीसवीं वर्षगांठ की सप्ताह में नरेशों का जिनमें से बहुत सों ने सविधान सभा में स्वतंत्रता के सहितानों के रूप में पूर्ण सहयोग दिया है यहाँ उन्हीं सभी पत्रा एवं समझौतों के विषय में जिन्होंने संगठित भारत का निर्माण किया है उन्हीं वाले मामलों पर विचार करने के लिए एकत्रित होना पड़ा है। हम वर्तमान प्रस्ताव पर शोक प्रकट करने और उस वापस लेने के लिए कहने के अनिश्चित

और कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में इन सधि पत्रों एवं समझौतों को तोड़ना विश्वासघात के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

भारतीय परम्परा

“दिये हुए वचनों के प्रति सच्चे रहना भारत की परम्परा है और हम यह कह सकते हैं कि यह भारतीयों के चरित्र में स्वाभाविक है। इस मामले में केवल मौखिक रूप से नहीं कहा गया है बल्कि ये पवित्र सधि पत्र हैं जोकि सावधानी के साथ विचार विमर्श करने के बाद किए गए हैं। यदि भारत सरकार इन वचनों का परित्याग करने की इच्छा करती है तो यह उन भारतीय परम्पराओं के मूल्यों को कम करना होगा जिन पर भारत के हर नागरिक को गर्व है, और इस कार्य से प्रतिज्ञा शब्द ही निरर्थक हो जाएगा। भारत सरकार राष्ट्रीय सम्मान और नैतिक मूल्यों की केवल संरक्षक ही नहीं है बल्कि विश्व में भारत की प्रतिष्ठा के लिए भी उत्तरदायी है।

जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है यह प्रश्न केवल प्रिवीपर्स का ही नहीं है, यद्यपि यह हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, किन्तु यह तो सिद्धान्त का विषय है। भारतीय होने के नाते इन नैतिक सिद्धान्तों से हमारा सम्बन्ध है जोकि समाज का आधार है, उस न्याय से जोकि राज्य का आधार है, उस सम्मान से जो भारत की प्रतिष्ठा का आधार है वह आधार बहक जाएगा। इन सबके लिए भारत के नरेश सगठित हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि इस घटना ने नरेशों में एकता की एक नई रुचि और परस्पर भाईचारे को जागृति कर दिया है।

गम्भीर समस्याएँ

सचमुच ही यह अजीब बात है, कि ये लोग ठीक वही हैं, जिन्होंने भारतीय एकता का निर्माण करने में सहायता दी। अब उन्हीं के साथ उपेक्षा का व्यवहार किया जा रहा है जोकि किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। देश के सम्मुख गम्भीर समस्याएँ हैं, जिन पर सरकार को अति आवश्यक रूप में ध्यान देकर अपनी शक्ति लगानी चाहिए।

हम यह साधिकार कह सकते हैं कि भारत की भौगोलिक एकता के निर्माण में हमने एक छोटी सी भूमिका पूरी की है और यह विचार करते हैं कि जो योगदान हमने अभी हाल ही के भूतकाल में दिया है वह केवल कर्तव्य निभाने की उत्सुकता थी जिसे कि हमें भारतीय जनता के लिए करना चाहिए था क्योंकि हमारे सामने राष्ट्र को सुदृढ़ एवं स्मृद्धिगाली बनाने का कार्य था। जैसे कि हम सदैव से, इस देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों और देश की सेवाओं के लिए, अपनी परम्पराओं के अनुसार सजग रहे हैं।

हम यह अत्यधिक प्रसन्नता है कि जब भी वे लोग मौजूद हैं जो नैतिक मूल्यों और दिए हुए वचनों की पवित्रता को धोखा मानते हैं और उसमें हम भारते के स्वतंत्र पत्रों को भी सम्मिलित करते हैं जो कि अपने निष्ठा दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में स्पष्ट और निश्चय रहे हैं।

इस अवसर हम पर अपनी विश्वास प्रगट करते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस महासम्मेलन जो कि अपनी महान् देश भक्ति और परम्परा के लिए दृढ़तः प्रवृत्त रहती है इस विषय पर उचित रूप से पुनः विचार करेगी और अधिक गति बित्त एवं सत्यता के साथ इस पर कार्य करेगी।



जनवारी

भारतीय दशन में नैतिक व्यवस्था पर सर्वाधिक बल दिया गया है और इसे श्रुत कह कर पुकारा गया है। ऋग्वेद में श्रुत की सत्य से पहले उद्धृत बतलाया गया है श्रुत व सत्य चाभीदातपसोऽन्यजायत (ऋग्वेद 10/190/1)। भारतीय मनीषियों ने श्रुत को मानव जीवन के लिए नित्यता माना है।

असत्य से हट कर सत्य के मार्ग पर अग्रसर होना भट्टहरि के अनुसार 'यायपथ' का अनुसरण करना है। नीति शतक में भट्टहरि ने कहा है कि धीर पुरुष यायपथ से अपना पग कभी पीछे नहीं हटाता 'याम्यात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा'।

अपने प्राप्य से संतुष्ट न होकर दूसरों के सुख या धन को हर लेने की प्रवृत्ति 'स्तम' कहलाती है। हमारे यहाँ इसे दानवी प्रवृत्ति कहकर त्याग्य बतलाया गया है। इसके विपरीत जीरो को हँसत देखो मनु हंसो और सुख पाओ की प्रवृत्ति अस्तेय है। भारतीय जीवन की सचालिका प्रवृत्ति यही है। हमारे यहाँ तो बड़े माष्ट शब्दा में उद्धोष किया गया है सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वेभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमागमयेत् ॥' अर्थात् सभी सुखी हो, सभी निरोग हों सभी कल्याण के दर्शन करें और कभी किसी को किसी प्रकार का दुःख न हो।

जिस राष्ट्र के जीवन में श्रुत की प्रधानता हो जिस राष्ट्र के वाता (धीर पुरुष) यायपथ से पग पीछे न हटाते हों और जिस राष्ट्र के जीवन की सचालिका प्रवृत्ति अस्तेय हो उस राष्ट्र में तपाकयित समाजवाद की दुहाई देकर पचास करोड़ 'व्यक्तियों' द्वारा किये गए समझौते और दिये गए वचनों को भंग करने की कुछ दृष्टि की कुमत्तता किस प्रकार मफल हो सकती है।

सत्यमेव जयते जिस राष्ट्र का गौरव चिह्न हो, अग्रिम (भाग) जिस राष्ट्र का सर्वोपरि जीवन मूल्य हो तथा 'प्राण आहुँ धरु वधन्तु न जाई' जिस राष्ट्र का मौलिक मूल स्वर हो उस राष्ट्र में भृशभर स्त्रियों की दुर्भावना पचास करोड़ की समग्रता के सामने कहाँ टिक सकती है।

